लोक-सभा वाद-विवाद का संद्यिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

छठा सत्र Sixth Session





[खंड 23 में ग्रंक 21 से 3. नक हैं Vol.XXIII contains Nos. 21 to 31

लोक-सभा सचिवालय नई दिल्ली LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

मूल्य : एक रूपया Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

प्रक 30-गुरुवार, 19 दिसम्बर, 1968/28 प्रग्रहायए।, 1890 (शक) No.30 -Thursday December 19, 1968/Agrahayana 28, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAI	L ANSWERS TO QUESTIONS:	
ता. प्र. संख्या/ _{S. Q. Nos.} विष	ाय Subject	ges/Pages
841 हरी खाद तथा उर्वरकों की मांग	Requirements of Green Manure and Fertilize	ers 1-3
843 उत्तर प्रदेश सर्किल में टेली- फोन कनेक्शन	Telephone Connections in U.P. Circle	3-6
844 टेलीफोन राजस्व सम्मेलन की सिफारिशों की क्रिया- न्विति	Implementation of Recommendations of the Telephone Revenue Conference	6-7
8:45 निर्वाचन के दौरान मंत्रियों द्वारा घन खर्च किये जाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on spending Money during Election by Ministers	7-12
846 सुपर बाजार दिल्ली	Super Bazar Delhi	12-14
847 निर्वाचन संचालन नियमों में संशोधन	Amendment to Conduct of Election Rules	15-17
च. सू. प्र. संख्या/S. N. Q. Nos.		
45 राजस्थान में नांमाकन अधि- वक्तओं का	Enrolment of Advocates in Rajasthan	1 7-20
प्रक्तों के लिखित उत्तर/	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता. प्र. सं./S. Q. Nos.		
842 हरिजनों, आदिम जातियों, तथा पिछड़े वर्गों के शीघ्र विकास के लिए योजना	Plan for rapid development of Harijan's Tribals and Backward Classes	21
848 चीनी के निर्यात के लिये राज सहायता	Subsidy for Export of Sugar	21

^{*} किसी नाम पर अंकित यह 🕂 चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को समा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

^{*}The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र.संस्या /S. Q. Nos. प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी /	विषय Subject WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-C अ	পুত্ত/Pages atd.
849 हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमि- टेड	Hindustan Teleprinters' Limited	21-22
850 कालकाजी नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के विस्था- पित व्यक्तियों को प्लाटों का अलाट किया जाना	Allotment of plots to Displaced persons from East Pakistan in Kalkaji, New Delhi	22
851 उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव	Panchayat Elections in U.P.	22–23
852 कोयला खनन उद्योग द्वारा मजुरी बोर्ड की सिफा- रिशों की क्रियान्विति	Implementation of the recommendations of the Wage Board by Coal Mining Industry.	23
853 अनुसूचित जातियों /अनुसूचित आदिम जातियों के लिए लोक सभा/विधान सभाओं में स्थानों के आरक्षण की अविध का बढ़ाया जाना	Extension of Period of Reservation of Seats in Lok Sabha and Assemblies for Schedule Castes and Scheduled Tribes	ed 23–24
854 सुपर फास्फेट का उत्पादन और आयात	Production and Import of superphosphate	24
855 उपस्थिति बोनस योजना	Attendance Bonus Scheme	24-25
856 पश्चिमी बंगाल में पटसन मिलों में छटनी	Retrenchment in Jute Mills in West Bengal	25
857 मत पेटियों का निर्माण	Manufacture of Ballot Boxets	25-26
858 उत्तर प्रदेश में गो वध	Slaughtering of Cows in U.P.	26
859 जिला रामपुर (उ.प्र.) में गोवंश के पशुस्रों का वध	Slaughtering of Bovine Cattle in District Rampur (U.P.)	26–27
8 60 राजस्थान से भारी संख्या में पशुग्रों को अन्य स्थानों में लेजाना	Exodus of Cattle from Rajasthan	27
861 कर्मचारी भविष्य निघि संग- ठन	Employees Provident Fund Organisation	27

	3. C C	Subject	geo/Pages	
प्रश्ना	के लिखित उत्तर-(जारी)W	ITTEN ANSWERS TO Q	UESTIONS—Contd.	
5061	रतलाम के डाक तथा तार कर्मचारी	P & T Employees at Ratla	m 3	5
5062	नई दिल्ली स्थित काल- काजी बस्ती में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाना	Settlement of East Pak. D Kalkaji Colony, New I	isplaced persons in Delhi 35–30	6
5063	मध्य प्रदेश की ग्राम पंचा- यतों में डाकघर	Post offices in Gram Panc. Pradesh	hayats of Madhya	5
5064	मध्य प्रदेश में डाक तथा तारघर, टेलीफोन केन्द्र आदि	P and T Offices, Telephone Madhya Pradesh	Exchanges etc. in	ı
5065	राज्यों को उर्वरकों का नियतन और उसकी खपत	Allocation and consumptio States	n of Fertilizers in	7
5066	भारतीय खाद्य निगम को अनाज की संप्लाई के लिये भुगतान रोक लेना	Withholding of payments f grains to food corporat		8
5067	मार्डन बेकरोज (इंडिया) लिमिटेड	Modern Bakeries (India) L	td. 38-39	•
5068	जम्मू-काश्मीर के रिटर्निग अफसर के विरुद्ध कूट रचना और साक्ष्य गढ़ने के आरोप	Charges of forgery and fab against Returning office Kashmir		0
5069	मरूस्थल में खेती कराने का कार्यक्रम	Desert Reclamation progra	amme 40-4:	1
5070	विदेशों में पढ़ रहे अनू- सूचित जाति/अनृसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी	Scheduled Caste/Scheduled studying Abroad	Tribe students	i
5071	गुजरात को ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Tractors to Gujr	at 41-4	2
5072	मद्रास सरकार को गेहूं और चीनी का नियतन	Allocation of wheat and su Government		12
		A ist N		

5072 32-2		
5073 सेन चीनी जांच आयोग	Sen Sugar Enquiry Commission	42-43
5074 निजाम शूगर फैंबटरी, ग्रांध्र प्रदेश	Nizam Sugar Factory, Andhra Pradesh	43
5075 चीनी के मूल्य निर्धारित करने के लिए 'जोद'	Zones for determining Sugar Price	43-44
5076 गन्ने की खेती की लागत	Cost of sugarcane cultivation	44-45
5077 सफाई के काम में जागीर- दारी पद्धति का उन्मूलन	Eradication of Jagirdari System in Scavenging	45
5078 अन - अधिसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को रियायतें	Concession to De-Notified Tribes and Scheduled Tribes	45-46
5079 कोयला खानों द्वारा आदर्श स्थायी आदेश अपनाना	Adoption of Model Standing orders by Coal Mines	46
5080 कृषि उद्योग निगम	Agro Industries Corporation	46-47
5081 क्सांसी डिघीजन में बेरोज- गारी	Unemployment in Jhanii Division in U.P.	47-48
5082 वर्ष 1968-69 में आसाम में आदिवासियों के कल्याण कार्यों पर व्यय	Expenditure on Tribal Welfare in Assam during 1968-69	48
5083 मैसूर राज्यों को उपहार के गेहूं का तथा खाद्य पदार्थों की सप्लाई	Supply of free Gift wheat and Food Articles to Mysore	48-49
5084 घातु से बनाये गये गोदाम	Metal Storage Structures	49–50
5085 खाद के रूप में पशुओं के रक्त का प्रयोग	Use of Animal Blood as Manure	я̀
5086 डाक दरों की वृद्धि का छोटे समाचारपत्रों पर	Effect of increase of Postal Charges on small Newspapers	5 0
प्रभाव 5087 उड़ीसा को पर्मिपग सेटों की सप्लाई	Supply of pumping sets to Orisis	50-51

द्यता. प्र. संस्था/U.S. Q.Nos.	विषय	Subject	1	पृष्ठ/Pages	
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/	WRITTEN ANSW	ERS TO QUESTION	√S–Co	ontd.	
5088 मछली पालन संसाधनों का विकास	Development of F	Fisheries Resources .	***	51	
5089 मछली उद्योग का विकास	Development of fi	ishing Industry	.	52	
5090 होशियारपुर संसदीय निर्वा- चन क्षेत्र में निर्वाचन स्थान करना	Postponement of Parliamentary	Election to Hoshiarpe Constitutency	1 r	52	
5091 दिल्ली और जयपुर के बीच सीघे डायल घुमा- कर टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling sy	stem		52 -5 3	
5092 चुनाव कार्य के लिये सामु- दायिक विकास खण्डों से जीपें वापस लेना	Withdrawal of jee	ps from C.D. Blocks.		53	
5093 हिन्दुस्तान टेली प्रिन्टर्स लिमिटेड	Hindustan Telepri	innters, Limíted .		53 –54	ļ
5094 हिन्दुस्तान टेलीप्रिम्टसं लिमिटेड	Hindustan Telepri	inters, Limited	,,,,	54	ŧ
5095 हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टसं लिमिटेड	Hindustan Telepri	inters, Limited	·••	54-55	5
5096 केन्द्रीय मत्स्य उद्योग निगम लिमिटेड	Central Fishiries	Corporation Ltd.		55–50	5
5097 सहकारी समितियों का विकास	Development of c	cooperatives		56-5	7
5098 बाटा मिला की गेहूं की सप्लाई	Wheat suppty to	Flour Mills		5	
5099 भाण्डागारों का निर्माण	Construction of V	Varehouses	••	57-5	
5100 मोडर्न बैकरी, मद्रास	Modern Bakery,	Madras	"	1	
5101 टेलीफोन के बारे में शिका∙ जन्में	Complaint regard	ling a Telephone in B	omba	y 58–5	15

का उत्पादन तथा समा-

हार

प्रदनों के लिखित उत्तर-जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

5126 कृषि उत्पाद बिक्री समिति, बुलन्दशहर	Agricultural Produce Market Committee, Bulandshahr	; 71–72
5127 उत्तर प्रदेश में किसानों हारा मकई की बिकी	Sale af Maize by Farmers in U.P.	72
5128 रुई विकास परिषद् बम्बई	Cotton Development council, Bombay	72–73
5129 अस्तील भारतीय बीमा कर्मचारी संस्था की मान्यताका रह किया जाना	De-recognition of All India Insurance Employees, Association	74
5130 गिर शेरों की संख्या में कमी	Gir Lions	74-75
5131 भ्रष्ट आचरम् के आधार पर निर्वाचन लडने के लिए अभ्यर्थियों को विवर्जित करना	Debarring of candidates to contest Elections on the grounds of corrupt practice	75 –76
5132 विदेशों से आयातित उर्घ- रकों का बिहार में बिना बिके पड़ा रहना	Fertilizers imported from Abroad lying unsold in Bihar	76
5133 विसाखापटनम की पहा- ड़ियों में काफी बागान के लिए भूमि	Land for Coffee plantation in hills of Visakha- patnam	76-77
5134 मनीपुर एपेक्स मार्केंटिंग कोआपरेटिव सोसायटी	Manipur Appex Marketing Cooperative Society	77-78
5135 मध्य प्रदेश में आयकर न्यायाधिकरण की बैंच	Income-tax Tribunal Bench in M.P.	78-79
3136 रूस से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from USSR	7 9
137 हरिजनों के साथ ब्यवहार	Treatment meted out to Harijans	79-80
3138 विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ कृषि के सम्बन्ध में चर्चा	Discussions with the World Bank President on Agriculture	80

Project

5152 कांडला उर्वरक परियोजना

परिवर्तन

के स्थापना स्थान का

Change of Locatian of Kandla Fertilizers

87

Telegraph Facilities to villages and Small Towns

94

5166 गांवों तथा छोटे कस्बों में

तार की सुविधायें

Subject

अता. प्र संख्या/ U. S. Q. Nos.

विषय

श्रता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.

विषय

Subject

पुष्ठ/Pager

विषय	Subject	ges/Pages
(दौ) चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	117
(तीन) साक्ष्य	Evidence	117
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	116
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	117
63 वां प्रतिवेदन	Sixth-third Report	117
रूस के शिष्ट मंडल की यात्रा के बारे में वन्तन्य	Statement re visit of Soviet Delegation	117
श्रीफखरुद्दीन अली अहमद	Shri F.A. Ahmed	117
नियम 377 के ग्रन्तगंत मामला	Matter under Rule 337	118
सभा की कार्यवाही	Proceedings of the House	418
श्री ही. ना, मुकर्जी	Shri H N. Mukerjee	118
श्रीयशवन्तराव चव्हारण	Shri Y.B. Chavan	119
मारतीय दंड सहिता (संशोधन) विधेयक	Indian Penal Code (Amendment) Bill	120
प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये समय बढ़ाना	Extension of time for presentation of Report Select Committee	120
महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में	Re. Death of Mahatma Gandhi	120
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re Question of Privilege	121
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापिस लेने के सम्बन्ध में केरल सरकार के कथित निर्णय के बारे में	Re; Kerala Government's Reported Decision to withdraw cases against Central Government Employees	
नागालैंड विधान सभा (प्रतिनि- धित्व में परिवर्तन)	Legislative Assembly of Nagaland (Change in Representation) Bill	1 23
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendrapal Singh	
श्री रंगा	Shri Ranga	
	(xv)	

श्री रगाधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
खंड 2 से 5 और I	Clauses 2 to 5 and 1	129
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	129
श्री वी. कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthy	129
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	129
श्री कंवर लाल गु ^ए त	Shri Kanwar Lal Gupta	130
श्री रा. बस्आ	Shri R. Barua	130-131
श्री एस. एम. जोशी	Shri S.M. Joshi	131
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	131
श्री एम. मेघचन्द्र	Shri M. Meghachandra	131
श्री शिव नारायए।	Shri Sheo Narain	132
श्रीक,लकप्पा	Shri K. Lakkappa	132
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	132
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	32-134
भारतीय टैरिक (संशोधन) विषे: यक	Indian Tariff (Amendment) Bill	134
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to concider	134
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shaffi Qureshi	134
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	136
श्रीमती तारा स्प्रे	Shrimati Tara Sapre	137
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	137
श्री नरेन्द्र सिंह महोडा	Shri Narendra Singh Mahida	138
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	138
श्री राजा राम	Shri Rajaram	138
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	13 9
श्री चेंगलराया नायडू	Suri Chengalraya Naidu	139

(ivx)

Subject

पुष्ठ / Pages

विषय

जांच समिति (इस्पात के सौदे) का प्रतिवेदन	Report of Committee of Inquiry (Steel Transsactions)	
श्री मधुलिमये	Shri Madhu Limaye	157
श्री श्री जी. मो. विस्वास	Shri J. M. Biswas	158-160
श्री प्र. चं. सेठी	Shri P. C. Sethi	160
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	160
श्री हरदयाल देवगुगा	Shri Hardayal Devgun	160

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण) LOK-SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK-SABHA

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 1968/ 28 भ्रग्नहायण, 1890 (शक)
Thursday, December 19, 1968/Agrahayana: 28, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

प्रध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हरी खाद तथा उदंरकों की मांग

●841. श्री नारायण स्वरूप शर्माः श्री श्रटल बिहारी वाजपेयीः

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में इस समय प्रत्येक वर्ष कितनी हरी खाद की मांग है और इस समय यह दास्तव में कितनी मात्रा में उपलब्ध है;
 - (ख) कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और
 - (ग) उक्त मांग को पूरा करने के लिए मावी कार्यक्रम क्या है;

साह्य शान्ते): (क) से (ग): पूछी गई जानकारी देने वाला एक विवरण समा पटल पर रस दिया गया है।

विवरगा

देश में उगाये जाने वाली हरी खाद की फसलों में, ढेंचा और सनहम्प दो लोक प्रिय फसलें हैं। हरी खाद के और भी साधन है, जैसे गुआर, मूंग, उड़द और लोबिया आदि दो काम में आने वाली फसलों का उगाना और हरी पत्ती की खाद बनाना। किसो वर्ष विशेष में हरी खाद लगाने के लक्षित क्षेत्रों के ज्ञान से उस वर्ष के लिए हरी खाद की मांग का पता चलता है। हरी खाद के अन्तर्गत 1967-68 के दौरान अनुमानत: 220.6 लाख एकड़ भूमि आविरत की गई थी, तथा चालू वर्ष (1968-69) के लिए 253.8 लाख एकड़ तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (1973-74) अनुमानित लक्ष्य लगभग 310 लाख एक है। विभिन्न हरी खादों की वार्षिक आवश्यकता तथा उपलब्धता के विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है क्योंकि किसानों के पास हरी खाद के कई अन्य साधन मी हैं।

अधिकांश राज्य अपनी हरी खाद के बीजों की आवश्यकता के विषय में आत्म निर्भर है। फिर भी, 1968 की खरीफ में बीने के लिए मैसूर, गोवा, अन्डेमान और निकोबार और नागालैंड राज्यों/ केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों ने अपनी बीजों की कमी कमशः 3500 मैट्रिक टन, 30 मैट्रिक टन, 0.1 मैट्रिक टन का अनुमान लगाया था।

किसान प्राय: अपनी हरी खाद के बीजों की आवश्यकता को पूरा करने का प्रबन्ध अपने उत्पादन से, अपने साथी किसानों से और निजि व्यापार से, कर लेते हैं तथा राज्य सरकारें भी किसानों को अपने राज्य से तथा अन्य पड़ौसी राज्यों से इन बीजों को प्राप्त कराने में सहायता देती हैं।

हरी खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

- (1) राज्यों को इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 30 प्रतिशत ऋग तथा 20 प्रतिशत अनुदान तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।
- (2) कुछ राज्यों में हरी खाद की फसलें उगाने के लिए किसानों को सिचाई के लिए पानी मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- (3) कुछ राज्य किसानों को हरी खाद की फसलें उगाने के लिए बीज सहायतार्थं दरों पर देते हैं।
- (4) व्यावसायिक प्रथवा अनाज की किसी फसल को हानि पहुँचाये बिना, खाद की हरी फसलें बोने का आयोजन करने के लिए उचिन शस्य प्रशालियों का विकास किया गया है। शस्य चक्कों में शैम्बिक फसलों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाता है।

Shri Narain Swarup Sharma: 62 percent of land in the country is in the hands of 10 percent big farmers. We cannot call them zamindars after the abolition of zamindari. The benefit of the fertilisers supplied by the Government is mostly reaped by the so-called zamindars only. I want to know what steps Government are going to take so that these fertilisers may reach the small farmers?

श्री प्रज्ञासाहिब शिन्देः यह प्रश्न हरी खाद के बारे में है जिसका वितरण सरकार नहीं करती है। सभा पटल पर रखे गये विवरण में केवल वे ही उपाये बताए गये हैं जो राज्य तथा केन्द्र द्वारा छोटे तथा बड़े किसानों की अधिकाधिक हरी खाद इस्तेमाल करने में सहायता करने के लिये किये जा रहे हैं।

Shri Narain Swarup Sharma: According to the statement the position about green manure is not satisfactory. In such circumstances, Government should not reject offers of setting up fittiliser plants in the country. Will Government see to it that more such factories are opened?

श्रध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्नु से उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Ram Gopal Shalwale: Government are importing fertilisers to meet internal requirement. Experts are of the opinion that imported fertiliser reduce the fertility of the soil after two years. Will Govt, take steps to step up the production of indigenous manures. Cows are butchered in this country. Cowdung can serve as a good manure. Have Government thought over the question of banning its consumption as a domestic fuel in the villages?

श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे: मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि अर्जेव खाद्य से भूमि की उत्पादन शक्ति कम हो जाती है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कूड़ा-करकट और गोवर के रूप में जो स्थानीय संसाधन उपलब्ध हैं उन्हें प्रयोग में न लाया जाये। परन्तु यह राय कि अर्जेव खाद्य से भूमि की उत्पादन शक्ति का हास होता है बिल्कुल गलत है।

उत्तर प्रदेश सर्किल में हेलीकीन कनेक्शन

+

#843. श्री कंवरलाल गुप्तः

श्री शारदा नन्द:

भी ओंकार सिंह:

भी जि० व० सिंह:

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये बहुत से आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सर्किल के टेलीफोन प्राधिकारियों के पास अनिग्गित पड़े हैं;
- (ख) उक्त सकिल के गुड़गांव जिला के पुन्हाना तथा हसनपुर कस्बों के निवासियों से कितने मावेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;
 - (ग) सरकार इन व्यक्तियों के अनुरोध कब तक स्वीकार कर लेगी ; और
- (घ) क्या इन नये कनेक्शनों को देने के बाद हेडल एक्सचेंज में इन तीन कस्बों के लिये एक अलग ट्रंक बोर्ड लगाना सम्भव होगा ?

ससद-कार्यतथा संचार मन्त्रालय में राष्ट्य मन्त्री (श्री इ॰ कु॰ गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) पुन्हाना में 7 और हसनपुर में 15 इस समय प्रतीक्षा सूची में हैं।

- (ग) इन आवेदकों को 6-8 महीने की अवधि में कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है।
- (घ) इस समय होटल में ग्रलग ट्रंक बोर्ड की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta: There is great demand for telephone connections in the country. Telephone is a necessity now-a-days. I think Government have not got mough resources to provide connections early. I want to know what new scheme Government are proposing to introduce, what will be its benefits and when it will be implemented?

श्री इ० कु० गुजराल: मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि टेलीफोन लगवाने में कठिनाई है क्योंकि टेलीफोनों की कमी है और टेलीफोन लगवाने वालों की सूची बड़ी लम्बी है। इस सम्बन्ध में हमारे रास्ते में कठिनाई धन का अभाव है। योजना आयोग बांड जारी करने के हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है परन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भी कंदरलाल गुप्त: वह योजना क्या है ?

श्री इ० कु० गुजराल: संक्षेप में योजना यह है कि बिजली बोर्ड़ी की तरह डाक तथा तार विभाग को बाजार से धन प्राप्त करने की अनुमित दी जायेगी और जिनके पास वे बांड होंगे उन्हें टेलीफोन दिये जायेगे।

Shri Kanwar Lal Gupta: What is the number of applications pending for telephone connections so far and how many applicants are proposed to be covered during the next plan? It will be very gratifying if figure for Delhi are also given.

श्री इ० कु० गुजराल: इस समय देश में लगभग 11 लाख टेलीफोन है। लगभग 5-6 लाख व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में है। हमारा विचार है कि चौथी योजना में, यदि संसाधन उपलब्ध हुए तो लगभग 15 लाख टेलीफोन और लगाए जाने चाहिये क्योंकि हमें आशा है कि उस समय प्रतिक्षा सूची काफी लम्बी हो जायेगी। दिल्ली में इस समय लगभग 70,000 टेलीफोन है और 50,000-60,000 की प्रतीक्षा सूची हैं। चौथी योजना में इनकी संख्या दुगुनी करने का विचार है बशर्तिक हमें धन उपलब्ध हो जाये।

Shri Tulshi Das Jadhav: According to the P. & T. circular Rs. 2500 have to be deposited for getting a telephone connection. It is a difficult proposition. Will Govt take into consideration this difficulty of the persons desirous of getting new telephone connections?

The persons making local trunk calls are issued receipts after 2-3 months. It is submitted in the form of bills. If anybody wants to make an inquiry about it, the local office says that they have no records and directs them to contact the head office. Will Government make arrangements for maintaining one copy thereof in local offices?

श्री इ०कु० गुजराल: महानगरों के मामले में यह राशि 2500 से बढ़ाकर 3000 रूपये कर दी गई है। छोटे नगरों के लिए 2500 रुपये हैं। यह राशि "अपना टेलीफोन लगाओ" योजना के अन्तर्गत देनी पड़ती है। टेलीफोन कनेक्शनों के लिये तीन श्री शिया बनी हुई हैं। एक 'अपना टेलीफोन लगाओ" श्री श्री जिसके अन्तर्गत 2500 रुपये या 3000 रुपये जमा

कराने पड़ते हैं। दूसरी श्रेणी डाक्टरों आदि की विशेष श्रेणी है। इसके बाद तीसरी या साधारण श्रेणी है। इन तीन श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन दिय जाते हैं।

यदि ट्रंक काल सार्वजिनिक ट्रंक काल कार्यालय से किया जाता है तो रसीद दी जाती है। यदि अपने टेलीकोन द्वारा किया जाये तो कोई रसीद नहीं दी जाती।

श्री रमानी: केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे भारत में प्रनीक्षा सूची में बहुत सारे आवेदनपत्र हैं। कोयम्बदूर नगर में पिछले तीन वर्षों से प्रतीक्षा सूची में 3000 से अधिक आवेदनपत्र हैं। लोक लेखा समिति में भी यह प्रश्न उठाया गया था कि अधिकारियों ने हमें बताया कि पर्याप्त पुर्जे तथा कच्चा माल नहीं मिल रहा है। पुर्जे तथा कच्चा माल शीधिता से उपलब्ध करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ताकि अधिक कनेक्शन दिये जा सकें।

श्री इ० कु० गुजराल: सारे देश की तस्वीर सामने रखी जाये तो भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। जहां तक टेलीफोन कनेक्शनों का सम्बन्ध है, धन की कमी के कारण चाहे कच्चा माल हो या पुतें हमें बहुत अधिक कमी का सामना करना पड़ेगा। यह स्थित आगामी कुछ वर्षों तक बनी रहेगी।

Shri Bhola Nath Master: It has been stated that there is difficulty in giving new telephone connections because of the delay in the schedule of setting up a telephone factory in Rajasthan. The position today is that telephones etc. are not being supplied to individuals and PCOs. for which sanctions have been given. Keeping this in view, will Govt. examine the question of setting up a new telephone factory?

श्री इ० कु० गुजराल: जहां तक फैक्टरी का सम्बन्ध है, हमने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि हम ट्रांसिमशन उपकरण बनाने के लिये एक दूसरी फैक्टरी स्थापित करने जा रहे हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रोज से पृथक टेलीफोन उपकरण बनाने के लिये एक और फैक्टरी स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। फैक्टरी कहां स्था-पित की जायेगी, इस बार में इस समय बताना सम्भव नहीं है। इसकी स्थापना से स्थित में थोड़ा बहुत सुधार तो अवश्य ही होगा।

Shri Shiv Charan Lal: What are the reasons for not providing the post offices with telephones when applications to that effect have been sent to the hon. Minister? What are the conditions for providing telephones at the permanent residences of MPs.?

श्री इ० कु० गुजराल: संसद सदस्यों के बारे में स्थिति यह है कि उनके नई दिल्ली निवास पर एक टेलीफोन लगाया जाता है जिसकी लागत लोक-सभा या राज्य समा द्वारा ब्रह्म की जाती है। सदस्य अपने निवास स्थान पर एक और टेलीफोन लगवा सकता है। परन्तु यह सब तभी हो सकता है जब ऐसा करना सम्भव हो।

Shri Shiv Charan Lal: My question has not been answered. In may village, Chaoli, there is a post office but the P. C. O. from there is at a distance of 5-6 miles. I have sent application twice for giving telephone connection there. What are the

reasons for not giving this connection? I have also seen Dr. Ram Subhag Singh in this connection but no telephone has been provided so far.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): We shall provide the hon. Member with a telephone.

श्री सु० कु० तापिड्या: क्या सरकार का ध्यान हाल ही में समाचार-पत्रों में छपे इस समाचार की ओर गया है कि इंडियन देती को स द्वारा एक नई प्रणाली निकाली गई है जिसके अनुसार एक ही एक्सचेंज पर लोग एक नए उपकरण तथा नए नम्बर द्वारा जो पहले नम्बर के साथ जुड़ा होगा देली फोन पर बात कर सकेंगे ? क्या सरकार इसे व्यवहाय समभती है और यदि हां, तो इसे किन सिकलों में लगाया जायेगा ?

श्री इ० कु० गुजराल: सरकार का ध्यान इस ओर गया है। यह बहुत ही उपयोगी आविष्कार है। एक और आविष्कार के बारे में विचार किया जा रहा है जिससे एक केबल बोर्ड पर अधिक लाइनें, लगभग 20 लाइनें चालू की जा सकेंगी। हमने ऐसी एक प्रणाली के आयात के लिए आर्डर दे चुके हैं ताकि हम यह पता लगा सकें कि वह हमारे लिये उपयोगी होगी अथवा नहीं, और फिर उसे अपने यहां बनाना शुरू कर देंगे।

श्री बी॰ शंकरानन्द : इस समय तो टेनीफोन अमीर ही लगवा सकते हैं क्योंकि "अपना टेलीफोन रागाओ" योजना के अन्तर्गत काफी बड़ी रकम जमा करनी पड़ती है। पता नहीं सरकार "अपना टेलीफोन लगाओ" की सेवा गरीबों तथा मध्यम वर्ग को कब उपलब्ध करेगी। क्या सरकार नगरों में सार्वजितक टेनीकोन तथा स्थानीय टेलीफोन बूथों की संख्या बढ़ाने के बारे में विचार करेगी?

श्री इ० कु० गुजराल: सरकार ने अव पहली बार, एक निर्णय कर लिया है और लोकल पब्लिक काल आफिसों के लिये एक विशेष प्रतिशतता निर्धारित कर दी है। हम पब्लिक काल आफिस खोलने के लिये कुल अधिष्ठापित क्षमता का पांच प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने की अब कोशिश कर रहे हैं। हमारा अन्तिम लक्ष्य 10 प्रतिशत का है। मैं यह बता दूं कि हम फार्म तथा कृषि क्षेत्रों को टेलीफोन देने की ओर विशेष व्यान दे रहे हैं, ताकि आधुनिक फार्म तैयार किये जा सकें।

टेलीफोन राजस्व सम्मेलन की सिफारिशों की क्रियान्वित

#844. श्री स॰ चं॰ सामन्त । क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

- (क) नई दिल्ली में सितम्बर, 1968 में हुए टेलीफोन राजस्व सम्मेलन द्वारा बन्बई टेलीफोन केन्द्र में पांच अंकों के मीटर लगाने तथा मीटरों के फोटोग्राफ लेने के उपकरण लगाने के बारे में की गई सिफारिशों को कियान्वित करने के लिये कौनसे तथा कितने मूल्य के उपकरणों की आवश्यकता है; बौर
- (स) क्या कलकता, मद्रास, दिल्ली तथा अभ्य नगरों में भी ऐसे ही व्यवस्था किये जाने की सम्मावना है ?

ससद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) बम्बई टेलीकोन प्रगाली के लिये मौजूदा 4 अंकों के मीटरों के स्थान पर पांच अंकों के मीटरों के स्थापन के लिये लगभग 16.5 लाख रुपयें की कीमत के 88 पांच अंक मीटर रेकों की आवश्यकता है जिनमें 94,500 उपभोक्ता मीटर लगे हुए हों। वहां से 4 अंकों के मीटरों का प्रयोग अन्य स्थानों पर किया जाएगा। उपभोक्ता मीटरों के आंकड़े (फोटोग्राफ) लेने के लिए फोटोग्राफ उपस्कर की कीमत जिसमें फिल्म दर्शी और सूक्ष्मदर्शी (ब्यूअर और स्केनर) लगे हों, लगभग 55,000 रुपये होगी।

(ख) जी, हां।

श्री स० चं सामन्त: क्या अतिरिक्त उपकरण आयात किया जायेगा या यहीं पर उसका निर्माण किया जायेगा ?

श्री इ० कु० गुजराल: जहां तक पांच श्रंकों के मीटरों का सम्बन्ध है, वे भारत में बनाए जायेंगे। जहां तक फिल्म दर्शी और मीटरों के फोटोग्राफ लेने वाले कैमरे का सम्बन्ध है शुरु में हम 4 मुख्य नगरों के लिये चार सेट आयात कर रहे हैं और बाद में यदि यह उपयोगी पाया गया और यदि इसे यहां बनाया जा सका तो हम उन्हें यहां बनाने की कोशिश करेंगे।

श्री म० च० सामन्त: क्या सम्मेलन की ग्रन्थ सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो निकट मविष्य में किन पर अमल किया जाने वाला है ?

श्री इ० कु० गुजराल: सम्मेलन की सिफारिशों के परिएगमस्वरुप मेरे समापितत्व में एक समिति बनाई गई है जो सारे देश में बिल बनाने की प्रगाली का पुनर्विलोकन करेगी और 'टेंडर्ड बिलिंग सिस्टम' और प्रथाओं का सुभाव देगी। समिति काम कर रही है। यह ही मुख्य सिफारिश थी। दूसरे सम्मेलन का ज्यान विभिन्न नगरों में बकाया राशि की ओर दिलाया गया था। बकाया को खत्म करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी: सरकार ने राजस्थान तथा मैसूर सिंकलों में टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय के विकेन्द्रीकरन तथा अन्यत्र ले जाने का फैसला किया है जबिक महाराष्ट्र, मद्रास, केरल, गुजरात, पंजाब तथा ग्रन्य स्थानों पर आंशिक विकेन्द्रीकरण हुआ है। अन्य स्थानों में इसका विकेन्द्रीकरण न करने और कुछ स्थानों में आंशिक विकेन्द्रीकरण करने के क्या कारण हैं?

श्री इ० कु० गुजराल: सरकार की नीति समूचे टेलीफोन राजस्व लेखे का विकेन्द्रीकरण करना है और घीरे-घीरे इस दिशा में प्रगति हो रही। यदि कुछ राज्यों में ऐसा नहीं किया गया तो दूसरे चरण में ऐसा किया जायेगा।

Restrictions on Spending Money During Election by Ministers

*845. Shri Jagannath Rao Joshi: Will the Minister of Law be pleased to state:

- (a) whether any restrictions have been imposed on spending money and on its distribution arbitrarily by the Ministers during Election days in view of the observations made by the Supreme Court in this regard; and
 - (b) if so, the details thereof and the reaction of State Governments thereto?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम) : (क) जी नहीं। (खे प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Jagannath Rao Joshi: I am surprised to hear the reply from the hon. Minister because on a previous occasion, on the 1st August 1968 in reply to a question he stated:-

"The Government has taken note of the observations made by the Supreme Court and Election Commission."

The Supreme Court had observed:

"The Commission desires that in the interest of fair and free elections, certain healthy conventions should be introduced and, if necessary, changes should also be made in the rules regulating the distribution of discretionary grants by Ministers."

Keeping this in view the Centre had sought the opinion of all the State Governments. So many months have lapsed, it has not been made known yet as to what are the opinions of the State Government in this matter. Unless we set up healthy traditions, it is very difficult to have free and fair elections in this country. While dismissing the petition against Shri Sukhadia, the Rajasthan High Court observed

"The Rajasthan High Court in its judgment, while dismissing the election petition against Shri Sukhadia has held that the construction work of Nala in Baluchistan colony, Udaipur at a cost of of Rs. 2,70,000 was started on 1.2.67 in contravention of the rules requiring prior budget allotment, administrative sanction, technical sanction under the influence of Shri Sukhadia." In the Supreme Court judgment it has been observed. That perhaps it may not be a corrupt practice but it is an evil practice. Sir, when you were Chief Minister of Andhra Pradesh, you resigned from your office because of some strictures passed against you by the Andhra Pradesh High Court. You thus established a healthy tradition by your example.

Keeping in view the strictures passed against Shri Sukhadia, was some directive issued from the Centre asking him to resign from his office?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं गलतफहिमयां दूर करना चाहता हूं । यह ठीक है कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है और शायद मैंने पहले मी इसकी कोर निर्देश किया था।

"चुनाव एक ऐसी चीज है जो निष्पक्ष रूप से होने चाहियों। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाओं के तुरन्त पहले धन व्यय करना, हालांकि वह जनता की मलाई, के लिये हो, एक कुरीति है चाहे शायद यह भ्रष्टाचार न भी हो।"

जब यह बात मुक्ते मालूम हुई, तो मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा कि क्या चुनाव नियमों के तदनुसार संशोधन करना सम्भव अथवा आवश्यक है। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया यह थी कि अभी यही पर्याप्त होगा क्यों कि उच्चतम न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि यह भ्रष्टाचार है तथा वह सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को परिपत्र जारी करेंगे। तदनुसार सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को 25 जून, 1968 से एक परिपत्र जारी किया गया। मैं इस परिपत्र की एक प्रति सभा पटल पर रख दूंगा। उसके बाद हमने गृह-कार्य मंत्रालय को लिखा और गृह-कार्य मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों के विचारों का पता लगाया। सभी मंत्रालय इस बात पर सहमत हो गये हैं कि चुनाव से तीन महीने पहले स्वविवेकीय निधि से कोई व्यय न किया जाये। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्वविवेकीय निधि के बारे में एक और नियम बनाना उचित होगा कि चुनाव के दौरान उससे व्यय न किया जाये।

Shri Jagannath Rao Joshi : This is the verdict of the Supreme Court that necessary rules should be framed in this connection. I would like to know whether a direction should not be issued for setting up healthy traditions and to see that such a thing is not done during and after the elections.

श्री गोविन्द मेनन: मैंने बताया है कि इस मामले में क्या किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की आशंकायें मुख्य चुनाव आयुक्त को बता दूंगा क्योंकि चुनाव उनके द्वारा कराये जाते हैं।

Shri Sheo Narain: I had suggested that every voter should be issued indentity card. I would like to know action taken by Government in this connection? The Government should see that more money is not spent in the elections and no conveyence is used for the voters.

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : इसका मूल प्रश्न में कोई सम्बन्ध नहीं ।

Shri Rabi Ray: I would like to know the grounds on which the Supreme Court had given a verdict against Shri Chenna Reddy and his election had been declared null and void.

A demand had been raised by the opposition parties that in the interest of healthy traditions and impartial elections, the Government should resign before the elections. This demand was not accepted then. Now non-Congress Government have also come into being after 1967 elections, and the opposition parties are prepared to accept such a tradition. I would like to know whether Government would accept this proposition now.

श्री गोबिन्द मेनन: मैं सदस्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिये। श्री चेन्ना रेड्डी के बारे में प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ग्रध्यक्ष महोदय: उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति उपलब्ध हो सकती है। इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि विरोधी दल चुनाव से पहले त्यागपत्र देने के लिये तैयार हैं?

श्री गोविन्द मेनन : यह नीति का प्रश्न है ग्रीर यह मामला इससे भिन्न है।

श्री चिन्तामिए पारिएग्रही: प्रशासन घन के कुछ लोगों के पास एकत्र होने को रोक नहीं रहा है। क्या यह तथ्य नहीं कि नहीं कि केवल विवाह तथा चुनात्र में ही कुछ लोगों को घन बाटा जाता है।

श्री प० गोपालन: चुनाव के दौरान घन व्यय करने तथा मनमाने ढंग से वितरण करने के अतिरिक्त कुछ मंत्री एक और प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों को अपने लिये सुरक्षित बना रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधान सभा में गृह-कार्य मंत्री श्री चव्हाण के विरुद्ध शिकायत की गई थी कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र करार निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर अनुचित ध्यान दे रहे हैं। प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी विभिन्न शिकायतें हैं, क्या सरकार मंत्रियों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र को अनुचित महत्व देने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिये तैयार है।

श्री मु॰ यूनस सलीम: निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि विशिष्ट राशियों के वितरण के मामले में मंत्रियों को राज्य के साम न्य हित को घ्यान में रखना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र नहीं चुना जाना चाहिये। यदि वह निर्वाचन क्षेत्र मंत्री का भी हो तो उसको अनुचित प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये।

श्री चपलाकांत मट्टाचार्य: निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव रखा था कि यह नियम समाप्त कर दिया जाना चाहिये कि उम्मीदवार अपने चुनाव व्यय का हिसाब दें। इस प्रस्ताव को कियान्वित करने के लिये क्या किया गया है।

श्री गोविन्द मेनन: मुक्ते ऐसे प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुगा: आसाम राज्य में चाचगांव निर्वाचन क्षेत्र से उप चुनाव में राज्य के परिवहन मंत्री ने प्राथमिक स्कूलों के लिए सरकारी धन का वितरण किया था जब कि यह उनका कार्य दोत्र नहीं है। क्या सरकार इसे भ्रब्टाचार समभती है और यदि हां, तो ऐसे मंत्रियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री गोविन्द मेनन: चुनाव में भ्रष्टाचार के प्रश्न न्यायालयों में निपटाये जाते हैं, सरकार द्वारा नहीं।

श्री हेम बस्त्रा: मैने एक विशिष्ट मामले के बारे में पूछा था।

डा॰ राम सुभग सिंह : यह गलत आराप है।

श्री हेम बरुग्रा: यह गलत नहीं है और मेरे पास सभी कागज पत्र हैं।

डा॰ राम सुभग सिंह: वह जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उनके विरुद्ध कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता। श्री कार्तिक उरांव: चुनाव सम्बन्धी भ्रष्टाचार के अधिक मामले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मतदानाओं के लिये परिवहन की व्यवस्था करने से सम्बन्धित होते हैं। क्या सरकार मतदाताओं के लिये चुनाव के स्थान पर जाने के लिये परिवहन की व्यवस्था करेगी ताकि ऐसा भ्रष्ट प्रमाव कम किया जा सके।

श्री मु० यूनस सलीम : सरकार द्वारा परिवहन व्यवस्था किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं हुआ है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम: इस प्रश्न का सम्बन्ध आगामी चुनावों में मंत्रियों द्वारा सरकारी शिवत के दुष्पयोग से हैं। कई आश्वासन दिये गये हैं परन्तु वे बातें क्रियान्वित नहीं की गई हैं, बिल्क उससे श्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि हो रही है। क्या सरकार उन पर विचार करेगी अथवा यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो क्या एक उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इस सुभाव पर विचार किया जायेगा कि कम से कम नामनिर्देशन के पत्र दाखल करने की तीथि से मंत्री त्याग पत्र दे दें और वे चुनाव के दौरान काम चलाऊ मंत्री के रूप में काम करें।

श्री गोविन्द मेनन: सरकार इसके लिये तैयार नहीं है।

श्री ग्रमृत नहाटा: क्या सरकार सार्वजनिक समवायों से दान लेने को भ्रष्टाचार मानने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री गोविन्ट मेनन : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री रंगा: क्या सरकार कम से कम इस बात पर घ्यान देगी कि मंत्री चुनाव के समय अपने दलों के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य न करें और जब तक मंत्री रहें, विभिन्न व्यक्तियों अथवा समवायों के दान स्वीकार न करें और उसे अपने तथा अपने दलों के साथ अन्य उम्मीदवारों के चुनाव पर व्यय न करें।

श्री गोविन्द मेनन: कांग्रेस ने कुछ स्वस्थ नियम बनाये हैं और मुक्ते आशा है कि अन्य दल भी ऐसे नियम बनायेंगे।

श्रष्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने मंत्रियों का उल्लेख किया है । चाहे वे किसी दल के हों।

श्री गोविन्द मेनन: इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Achal Singh: I would like to know whether Election Commission has suggested that security deposit for candidates to State Assemblies should be Rs. 750 and for Lok Sabha it should be Rs. 1500 only.

श्री मु० यूनस सलीम : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जो: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रियों को भूठे वचन न देने के लिये कहा जायेगा अथवा ऐसे वचनों पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether it is a fact that while giving verdict on the case of Shri Chenna Reddi, Andhra High Court suggested that the Ministers should resign at least six months before the elections. The Supreme Court did not offer any comments on that which means that the decision of Andhra High Court was upheld. In view of that will the Government take a decision in the interest of democratic traditions so that the Ministers do not misuse their positions.

श्री गोविन्द मेनन: मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मंत्रियों का चुनाव के समय त्यागपत्र देना जनतंत्रिक परम्परा है। यह ठीक है कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने ऐसा कहा है परन्तु अपील किये जाने पर उच्चतम न्यायालय ने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

श्री जि॰ मो॰ विश्वास: यदि मंत्री चुनाव से पहले त्यागपत्र दें तो उनमें से कोई भी चुनाव जीत नहीं सकता।

Shri Prakash Vir Shastri: The Supreme Court has not reversed that decision.

सुपर बाजार, दिल्ली

+ *846. श्री भारत सिंह चौहान : श्री टी० पी० शाह : श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के सुपर बाजारों के कार्य संचालन में सुधार के लिए कुछ प्रस्ताव भेजें हैं; और
 - (ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को जून, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष के बारे में कोआपरेटिव स्टोर लि० के कार्यकरण के सम्बन्ध में सांविधिक लेखा- परीक्षकों की टिप्पिएायां सूचित की थीं। उन्होंने यह सुभाव भी दिया था कि प्रबन्ध समिति में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए और महत्वपूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति खुली मर्ती अथवा सरकारी कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति द्वारा होनी चाहिए।

(ख) भारत सरकार ने प्रबन्ध सिमिति को पुनर्गिठित किया है, जिसने लेखा-परीक्षा में निकाली गई किमियों को दूर करने के लिए कार्यवाही की है और सुधार के लिए उपाय किए हैं जिनमें प्रशासनिक तथा परिचालन व्ययों में बचत, स्टाक स्तर का नवीन व्यवस्थाकरण, ऋय नीतियों का मानकीकरण, प्रशासनिक तथा लेखा प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना और व्यापार का विस्तार करना भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी की सेवाएं स्टोर को उनके महा-प्रबन्धक के रूप में कार्य करने के लिए सौंपी गई हैं। सहकारिता विभाग का एक अधिकारी भी प्रबन्ध समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेता है।

Shri Bharat Singh Chauhan: May I know whether it is a fact that Super Bazars in Delhi have been taken over by Central Government since the cooperatives have been a failure?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी: सुपर बाजार सहकारी नियमों के अन्तर्गत चलाये जाते हैं। दिल्ली सुपर बाजार के लिये केन्द्रीय सरकार केवल प्रबन्धक समिति नियुक्त करती है और दिल्ली प्रशासन के माध्यम से धन देती है। अधिनियम के ग्रन्तर्गन पंज यक को बहुत अधिकार है।

Shri Bharat Singh Chauhan: I would like to know whether any selection board has been appointed to recruit staff in the Super Bazar-and whether their experience in commercial line is also taken into account.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी: भर्ती प्रबन्धक समिति द्वारा की जाती है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं। भर्ती काम दिलाऊ दफ्तर तथा विज्ञापन द्वारा की जाती है।

Shri Prem Chand Verma: The balance sheet of Super Bazar shows that its total capital was Rs. 18,71,910 and a loss of Rs. 7,08,778 has deen shown upto 30th June, 1966, which means a loss of 40 percent in one year. Whether it is also a fact that furniture and air conditioners worth Rs. 35,71,661 were purchased. I would like to know whether a plan was framed for furniture etc. in advance? If not, the persons responsible for such a dwindling of capital. Whether any concrete steps are taken by the Government to prevent such bungling in the Super Bazar and whether Government will try to make good this loss in 1968-69 or 1969-70.

श्री एम॰ एस॰ गुरुपदस्वामी: सरकार ने 58 लाख रुपये दिये थे और पहले वर्ष सुपर बाजार में 7,08,878 रुपये का घाटा हुआ था। यह आंकड़े काफी समय पहले समा को बताये गये थे। आपात की स्थिति में सुपर बाजार शुरू किया गया था। रुपये के अवमूल्यन के बाद ऐसा किया गया था। तब इस बात की आवश्यकता समभी गई थी कि समूचे देश में विभागीय स्टोर खोले जायें। इस विचार से यहां सुपर बाजार खोला गया है, यह ठीक है कि सभी प्रयत्नों के बावजूद कुछ कमी रह गई है। कुछ अनुभव न होने के कारण तथा जल्दी में शुरु होने के कारण शुरु में कुछ हानि हुई है अब हमारा प्रयत्न यह है कि यथासम्भव इस घाटे को पूरा किया जाये। मुभी आशा है कि 1968—69 में स्थिति कुछ अच्छी होगी।

Shri Hukam Chand Kachwai: The items of merchandise in Super Bazar are of poor quality and are sold at higher rates. I would like to know the measures adopted to bring revolutionary change in the administration of Super Bazars.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी: यह कहना ठीक नहीं है कि सभी सुपर बाजार घाटे में चल रहे हैं। यह ठीक है कि कुछ सुपर बाजार घाटे पर चल रहे हैं। सभी सुपर बाजार

सहकारी विधियों के अन्तर्गंत संगठित किये गये हैं । केन्द्रीय सरकार केवल वित्तीय सहायता दे रही है। राज्य सरकारों की भी सहकारी सिमितियां होने के नाते उनमें रुचि है। इसिलये सुपर बाजार के सभी दोषों के लिये केन्द्रीय सरकार को जिम्मेवार ठहराना ठीक नहीं है। हम इस बात के मरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि सुपर बाजार ठीक तरह से काम करें और भविष्य में उनमें कोई हानि न हो।

माननीय सदस्य को मंगलवार को, जब सुपर बाजार बन्द रहता है, शकर मार्केट में जा कर देखें कि क्या वहां सुपर बाजार से अधिक मूल्य हैं अथवा नहीं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया: मैं यह जःनना चाहता हूँ कि क्या सरकार विभिन्न राज्यों में चल रहे सुपर बाजारों को कुछ सुभाव देगी कि वे भी व्यापारियों की दक्षता तथा योग्यता का लाभ उठायें और उनका सहयोग प्राप्त करें ताकि वे भी ठीक रूप से कार्य कर सके तथा नौकरशाही प्रवृत्ति वाले लोग वहां न रखे जायें।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी: व्यापारी लोग सुपर बाजार से सहयोग नहीं करते । परन्तु जहां तक उपायों का सम्बन्ध है, हमने कुछ मानदण्ड निर्धारित किये हैं तथा राज्य सरकारों के माध्यम से उन्हें सब विभागीय स्टोरों को भेज दिया गया है । प्रशासन तथा प्रबन्ध इत्यादि के बारे में मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

Shri Shiv Chandra Jha: Mr. Speaker, Sir, I am talking about the Super Bazar in Delhi, especially the Super Bazar situated in Conaught Place. I occasionally go there and often go to the books counter. What I find there is that more English books are available and the number of Hindi books available there is very much less. Moreover serious books in Hindi like "Mare Kahani", "Vishwa Itihas Ki Jhalak", and "Dr. Rajendra Babu Ki Atam Katha" are not at all available there. Likewise the majority of English books that are available there are light books and serious books are not available there. The books published by Pallik n and Fountara are not available there. I would like to know the reasons therefore from the hon. Minister?

Secondly I would like to know whether the selection of books is made by any individual or a Committee has been constituted for that purpose? I would like to know the names of the persons, who are responsible for the selection of books.

श्री एन० एस० गुरुवदस्वामी: मैं माननीय सदस्य के सुभाव को स्वीकार करता हूँ। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सुपर बाजार के लिये सब प्रकार की वस्तुओं की खरीद करने के लिये एक ऋय समिति है।

Shri Shiv Chandra Jha: Who are the members of that Committee?

श्री एम० एस० गुरुप्दस्वामी: इसका निर्णय मंत्री द्वारा नहीं किया जाता कि क्या वस्तुयें खरीदनी हैं और क्या नहीं। इसका निर्णय समिति करती है और ऐसा करते समय वह जनता की मांगों तथा अन्य बातों को ध्यान में रखती है।

श्री रिव राय: प्रश्न यह पूछा गया है कि क्रय सिमिति के सदस्य कौन हैं?

निर्वाचन संचालन नियमों में संशोधन

#847. श्री श्रीचन्द गोयल: क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि निर्वाचन संचालन नियमों में संशोधन करके ऐसा उपबन्ध किया गया है जिसके अनुसार पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार हो कि वह किसी मी मतदाता से उस सुभिन्नक चिन्ह को दिखाने को कह सके जो उसने मत-पत्र पर लगाया है;
 - (ख) वया इससे गोपनीयता के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है ; और
 - (ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री श्रीचन्द गोयल: क्या परिषद के चुनावों के लिये निर्वाचन संचालन नियमों में संशोधन किया गया है ताकि अशिक्षित मतदाता अपने साथ एक अन्य वयस्क को ले जा सके तथा क्या मंत्री महोदय के विचार में ऐसा करना गोपनीयता के सिद्धान्तों का टल्लंघन नहीं है तथा क्या इससे भ्रष्टाचार पैदा नहीं होगा ?

श्री मु॰ यूनस सलीम: मुख्य प्रक्त से यह प्रक्त पैदा नहीं होता। इस सम्बन्ध में नियम हैं। नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अन्धा है अथवा किस अन्य कारण से मत नहीं डाल सकता तो वह अपने साथ एक व्यक्ति को लें जा सकता है।

श्री श्रीचन्द शोयल: वर्तमान कानूनी स्थिति यह है कि नामंकन पत्रों के अवैध रूप से रह किये जाने पर चुनाव को अवैध करार दे दिया जाता है, चाहे इसमें चुनाव जीतने वाले व्यक्ति की कोई भी गलती न हो। क्या मन्त्री महोदय कानून में ऐसा संशोधन इसने की वांछनीयता पर विचार करेंगे जिससे नामांकन पत्रों के रह किये जाने के तुरन्त बाद अपील की जा सके ताकि उस पर थोड़े ही दिनों में निर्ण्य किया जा सके तथा वह व्यक्ति चुनाव में भी माग ले सके और बाद में चुनाव को अवैध करार न दिया जाय।

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): यह एक सुभाव है।

Shri Sarjoo Pandey: The hon. Minister has just said that an amendment in the rules has been made for those who are blind or illiterate or otherwise unable to exercise their votes, they can take a person each with them. The effect of this will be that the voter will be taken by force and he will be compelled to say that he is unable to cast his vote. Thus it will be a breeding ground for corruption. The other effect of this will be that secrecy will not be observed. Keeping there things in view I want to know whether the hon. Minister is ready to withdraw this amendment?

Shri M. Yunus Saleem: So far as the hon. Member's question is concerned. I have already submitted that this question does not arise out of the main question. If any suggestion is given by the hon. Members for preserving the secrecy that will be kept in mind.

Shri Sarjoo Pandey; Mr. Speaker, the rule was there according to which a person can go to the Presiding Officer himself and can say that he is unable to cast his vote. Now what is the necessity of taking another person? There is already a law for the Presiding Officer then what is the need for this amendment?

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए ।

श्रध्यक्ष महोदय: शोर मचाने से कोई लाभ नहीं होगा। मान ीय मन्त्री को उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं। मःननीय सदस्य सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपरार: चुनाव चिन्हों की व्यवस्था इसलिये शुरु की गई थी, ताकि अशिक्षित मतदाता यह पता लगा सके कि वह किस उम्मीदवार को मत देना चाहता है। इस बात को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि एक अन्य नियम की जरूरत क्यों पड़ी। जिसके अनुसार अपने मन चाहे उम्मीदवार को मत देने के लिये अशिक्षित मतदाता अपने साथ एक सहायक ले जा सके?

श्री मु० यूनस सलीम : ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल अशिक्षित मतदाता को ही ग्रामित दी जाये ।

श्री श्रीवन्द गोयल : ऐसा नियम है। ग्राप कैसे कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है। यह मामला अधीनस्थ विधान समिति के सामने पेश किया गया था। क्या ग्रापको मालूम नहीं कि नियमों में इस प्रकार का सशोधन किया गया है? आप नियम की जानकारी के बगैर ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

Shri Shiv Charan Lal: These bearded persons do not give clear reply.

श्रध्यक्षं महोदय: मुभे इस बात पर गम्भीर आपित्ति है। आप अपने शब्द अभी वापस लें अन्यथा आपको समा से बाहर जाना होगा।

Shri Shiv Charan Lal: I withdraw my remarks.

श्री गोविन्द मेनन: श्री गोयल ने जिन नियमों का उल्लेख किया है उनका सम्बन्ध राज्यों में विधान परिषदों के चुनावों से है। ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पढ़ित के अनुसार होते हैं। अतः मतदाता के लिये विभिन्न नामों के सामने 1,2,3,4 इत्यादि लिखने आवश्यक होते हैं। इन चुनावों में चिन्हों की पद्धित नहीं अपनाई गई है। इसलिये अन्धे मतदाताओं को यह छूट दी गई है कि वे अपनी पसन्द के उम्मीदवारों के नामों के सामने 1,2,3,4 इत्यादि के अंक लिखवाने के लिये अपने साथ एक साथी ले जा सकें। हाल में एक संशोधन करके यह छूट अशिक्षित मतदाताओं को भी दी गई है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इस मतदान पद्धित के कारण अशिक्षित मतदाताओं के लिये मत देना संभव नहीं होता।

Shri O. P. Tyagi: The Spirit of democracy is that able, honest and gentle persons should be elected as Members of Parliament and Assemblies. But the fact is that the present system of elections is very costly and nobody can fight, the elections unless he has a jeep car and 10 to 12 thousand rupees to spend. Under the present circumstances no

poor person, who is able and honest can be elected as a member of parliament or Assembly and if in any case any such person is elected he is influenced by the rich people by giving him money and as such he is unable to express his independent opinion in the House to which he has been elected as a member. He cannot raise his independent voice, because he has become an agent of a few capitalists. I want to know from the hon. Minister whether Government contemplates to make the election system cheaper so that poor people too who areable and honest are elected as Members of Parliament or Assemblies?

श्री गोविन्द मेनन : वया यह एक ऐसा सामान्य मामला नहीं है, जो मुख्य प्रश्न से पैदा नहीं होता ?

श्रध्यक्ष महोदय: जी हां।

अल्प सूचना प्रश्न SHORT NOTICE QUESTIONS

राजस्थान में ग्रधिवक्ताग्रों का नामांकन

ध०स्०प्र० 15. श्री नवलिकशोर शर्मा: क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को राजस्थान विधिन्न परिषद् के उस विनिश्चय का पता है जिसके अनुसार प्रधानों, प्रमुखों, इम्प्र्वमेंट ट्रस्टों के अध्यक्षों का पद धारण करने वाले या वैसे ही अन्य व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित तथा विधि व्यवसाय करने से विवर्जित किया गया है; और
 - (ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनस सलीम): (क) राजस्थान विधिन्न परिषद् ने प्रधानों, प्रमुखों, इम्प्रूबमेंट ट्रस्टों के अध्यक्षों का पद धारण करने वाले या वैसे ही अन्य व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित तथा विधि-व्यवसाय करने से विविज्ञित करने का कोई विनिध्चय नहीं किया है। विधिन्न परिषद ने जो किया है वह यह है कि उसने यह संकल्य पारित किया है कि सारवान पारिश्रमिक और विस्तृत कार्यपालिक कृत्यों वाले पदों में नियो-जित व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए और यदि वे पहले से नामांकित हों तो उन्हें अधिवक्ताओं के रूप में विधि-व्यवसाय बन्द कर देना चाहिए और विधिन्न परिषद को इसकी सूचना, यदि अभी तक न दी हो तो, दे देनी चाहिए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Naval Kishore Sharma: May I know whether according to the Resolution of Council the advocates entrolled under Bar Council shall be allowed to do practice and if not, whether the Law Minister proposes to frame some other rules in supersession of these rules? May I know the views of the hon. Minister regarding this Resolution?

विधि मंत्री (श्रो गोविन्द मेनन): मारत के विधिज्ञ परिषद् ने विधि व्यवसाय के सम्मान हित में निम्नलिखित नियम पास किया है:

''एक अधिवक्ता जब तक वह विधि व्यवसाय करता है तब तक किसी व्यक्ति, सरकार, धर्म, निगम अथवा समवाय का पूर्णकालीन कर्मचारी न होगा तथा ऐसी कोई नौकरी प्राप्त करने पर वह उस विधिज्ञ परिषद को सूचित करेगा, जिसमें उसका नाम दर्ज है तथा उसके बाद जब तक वह रोजगार में है, तब तक विधि व्यवसाय करना बन्द कर देगा।''

Shri Naval Kishore Sharma: May I know whether the Chairman improvement Trust is covered under the definition of a full time employee? This rule of the Bar Council is applicable to full time employees only. May I know whether those people also who are the heads of democratic institutions and get some allowances in their capacity as head of the institution and also discharge certain executive duties, are covered by this rule? I personally feel that this decision will not only be a hinderance in the way of development of democratic institutions Rajasthan, but it will be blocking the way of development of democratic institutions throughout the whole country. It will be a bad precedent for any bar Council to block the way of intelligent and educated persons from entering into autonomous institutions. It means that this restriction can be extended to M. L. As, and M. Ps, in future, I would like to submit that the rule of the Bar Council of India just quoted by the hon. Minister is applicable to full time salaried employees only. Now whether this rule will be applicable to those persons also who are holding offices in autonomous institutions and getting some allowances for that? My submission is that this question should be considered seriously and the hon. Minister should take some such decision in this matter or some such direction should be given to the Bar Council that their decision is not correct and it is set aside.

श्री मु० यूनस सलीम : यह प्रश्न सबसे पहले महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद् के सामने आया था। दो अधिवक्ताओं ने जिनमें से एक को 300 इपये प्रतिमास तथा दूसरे को जो कि महाराष्ट्र जिला परिषद तथा समिति अधिनियम के ग्रन्तर्गत चयन बोर्ड का सदस्य था. 700 रुपये प्रतिमास पारिश्रमिक मिलता था, महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद में नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की थी। महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद इस नतीजे पर पहुंची थी कि नियमों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को जिसे इतना अधिक पारिश्रमिक मिलता हो तथा जिसके इतने विस्तृत कार्य-पालिक कृत्य हों अधिवक्ना के रूप में विधि व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद के इस निर्णय का भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा भी अनुमोदन किया गया था। इस के बाद भारतीय विधिज्ञ परिषद का यह निर्णय राज्यों की सब विधिज्ञ परिषदों के पास भेज दिया गया था। मारतीय विधिज्ञ परिषद् के इस निर्णय को देखते हुये राजस्थान विधिज्ञ परिषद् ने यह संकल्प पःरित किया था कि सारवान् पारि-श्रमिक और विस्तृत कार्यपालिक कृत्यों वाले पदों में नियोजित व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित नहीं किया जाना चाहिये और यदि वे पहले से नामांकित हों तो उन्हें अधिवक्ताओं के रूप में विधि व्यवसाय बन्द कर देना चाहिये और विधिज्ञ परिषद् को इसकी सूचना, यदि अभी तक नदी गई हो तो, दे देनी चाहिये। इसलिये यदि कोई मामला इस संकरुप के अन्तर्गत आता है, तो उसे विधिज्ञ परिषद की नामांकन समिति के पास जाना होगा तथा यदि वह विधिज्ञ परिषद् के निर्णय से असंतुष्ट रहता है तो इसके लिये अन्य रास्ते हैं।

श्री सु० कु० तापडिया : मैं समभता हूं कि यह प्रश्न केवल परिश्रमिक प्राप्त करने का नहीं है अपितु विस्तृत कायंपालिक कृत्यों वाले व्यक्तियों को विधि व्यवसाय की अनुमित देना न्याय प्राप्त करने के रास्ते में एक रुकावट है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरए देता हूं। एक पटवारी, प्रधान अथवा प्रमुख के अधीन काम करता है। यदि वह प्रधान अथवा प्रमुख एक मामले में अधिवक्ता के रूप में पेश होता है तो उस पटवारी को उस मामले में उस प्रधान अथवा प्रमुख के विरुद्ध गवाही देना मुश्किल होगा जिसमें कि वह अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत हुआ है। संभव है कि महाराष्ट्र तथा राजस्थान में ऐसे संकल्प जिनका माननीय मंत्री द्वारा उल्लेख किया गया है कार्यपालिक शक्तियों के नाजायज इस्तेमाल की सम्भावना को दूर किये गये हों। महाराष्ट्र करने पारित विधिन्न परिषद् के संकल्प को देखते हुये तथा इस बात को देखते हुये कि उसका अनुमादन मारतीय विधिन्न परिषद् द्वारा किया गमा है, मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन अन्य राज्य विधिन्न ।रिष्ंों ने ऐसे संकल्ग पारित किये हैं? इन संकल्गों की वांछनीयता के बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री गोविन्द मेनन: इस मामले में सरकार का कोई विचार नहीं है। अधिवक्ता अधिनियम की योजना इन विधिज्ञ परिषदों के स्वायत्तशामी संस्थायें बनाने की है। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्ण्य से असंतुष्ट है तो वह केन्द्रिय विधिज्ञ परिषद को अपील कर सकता है। अब हम इस अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। वास्तव में राज्य सभा द्वारा इसे हाल में पारित किया गया है। उस संशोधन के द्वारा सरकार द्वारा विधिज्ञ परिषदों को निदेश देने की व्यवस्था की जायेगी। जब तक यह कानून बनता है, तब तक यदि मैं माननीय सदस्य के तर्क से सहमत मी हूं, तो भी कुछ नहीं कर सकता।

Shri Onkar Lal Bohra: Mr. Speaker, Sir, the conception of our Panchayati Raj is to develop democratic institutions and give them an honoured place in society. That is why from Panchayat Samiti level up to district level we are trying to have democratic institutions. So in order to make them successful it becomes necessary for the intelligent section of society like advocates to get training in them. We should not try to deprive the practising advocates from taking part in such institutions. In Rajasthan a Panchayat Pardhan gets Rs. 150/- and a Jilla Parmukh gets Rs. 250/- So it is all the more necessary that we should not deprive them of their profession, only because we are giving them Rs. 150/- or Rs. 250/- so far as the resolution passed by Rajasthan Bar Council is concerned, my submission is, that we should see that atleast people upto the level of the Pardhans of Panchayat Samitis and Parmukhs of Jilla Parishads are not deprived of their professions.

भ्रध्यक्ष महोटय : पहले प्रश्न को ही दौहराया गया है। इसिलये इसका उत्तर देने की जरुरत नहीं।

श्री स० कुन्हू: मैं उस मावना से सहमत हूं जिससे यह विशेष नियम बनाया गया है। अधिवक्ता व्यवसाय की स्वच्छता को बनाये रखने यह नियम बनाया गया है। नियम के अनुसार कोई अधिवक्ता किसी निगम अथवा सरकारी निकाय का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होना चाहिये तथा पूर्णकालिक कर्मचारी होने पर उसे विधि व्यवसाय करने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिये। महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद के नियम के अनुसार वे पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होने चाहिये। अब वे कहते हैं कि उन्हें सारवान् परिश्रमिक नहीं मिलना चाहिये। इससे

काफी भ्रम पैदा हो जायेगा। जैसाकि एक माननीय सदस्य ने कहा है विधान सभा सदस्य तथा संसद् सदस्य मी इस नियम के अन्तर्गत आ जायेंगे। भ्रतः उन्हें विधि व्यवसाय करने से विविज्ञ कर दिया जायेगा। मुक्ते मालूम है कि विधिज्ञ परिषद एक स्वायत्त्रशासी निकाय है तथा विधि मंत्रालय का इस मामले में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं है। परन्तु मंत्रालय राजस्थान विधिज्ञ परिषद से इस सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ कर सकता है कि क्या सारवान् परिश्रमिक पाने वाले व्यक्तियों को विधि व्यवसाय करने से विचित रखना विधिज्ञ परिषद् अधिनियम के उस नियम के विरुद्ध नहीं होगा जिसमें कहा गया है कि उन अधिवक्ताओं को जो पूर्णकालिक कर्मचारी हैं विधि व्यवसाय करने की भ्रमुमित नहीं होनी चाहिये?

श्री मु॰ यूनस सलीम: शायद माननीय सदस्य इस संकल्प की भावना को पूर्णतया समभने में असफल रहे हैं। मानदण्ड केवल परिश्रमिक की प्राप्ति ही नहीं, अपितु विस्तृत कार्यपालिक शक्तियों का होना है। यदि कोई व्यक्ति केवल परिश्रमिक प्राप्त करता है तथा उसके पास कार्यपालिक शक्तियां नहीं है तो उसका मामलः इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आता।

Shri Randhir Singh: The villagers most of whom are not familiar with the laws, are confused because there are numerous Acts pertaining to Panchayats, Block Samitis and Jilla Parishads and as such many irregularities are being committed by them. It has been seen that all cases of revisions and appeals are accepted in Appellate Courts without exception. So it is necessary that the lawyers should go there, so that the villagers may get justice. If that is done the villagers will become familiar with the laws and a national cause will be served.

Secondly a lawyer can be a Solicitor General are Advocates General and can draw fat salary from the Government. He can be elected as a member of Parliament or that of a Legislative Assembly. Under these circumstances how the resolution passed by Rajasthan Bar Council can become operative? Will the Minister recommend to the Rajasthan Bar Council that their resolution is in operative in the light of the resolution passed by the Bar Council of India?

Shri M. Yunus Saleem: Only remuneration is not enough. If any Advocate General or Solicitor General or Government pleader get remuneration, he performs his professional duties for that. Therefore the criterion is a person who is receiving honorarium as remuneration and also enjoying wide executive powers.

Shri Meetha Lal Meena: The Pardhans of Gram Panchayats and the Parmukhs of Jilla Parishads are administrative officers. The M. Ps. and M. L. As. have got no such administrative powers. If the Pramukhs of Jilla Parishads and the Pardhans of Jilla Samitis are allowed to practise as advocates and also to perform administrative functions then it will be danger to justice. So it is good that this rule has been framed. I want to know whether it will be made legally valid by passing an Act?

Shri M. Yunus Saleem: The Council is authorised to frame rules under the Act and the Bar Council will frame rules as it deems fit, keeping in view the spirit of the Act.

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हरिजनों, श्रादिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शीघ्र विकास के लिए योजना

- #842: श्री ए० श्री घरन : क्या समाज कल्याए मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये न्यूनतम मूलभूत सूविधाएं उपलब्ध करने और उनके लिये जीवन निर्वाह का न्यूनतम स्तर सुनिध्चित करने में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण क्या सरकार का विचार देश में किसी अन्य वर्ग के लोगों को कोई अतिरिक्त सुविधा देने से पूर्व इन वर्गों का तेजी से विकास करने लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई श्रोजना बनाने का है;
 - (ख) यदि हां, तो इस विकास योजना का ब्यौरा क्या है; और
- (ন) इस योजना के अनुसार उक्त दलित वर्गों के लिये कब तक जीवन की न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने की सम्भावना है ?

समाज कल्याए विमाग में राज्य मंत्री (डा० धोमती) फूलरेए गुह : (क) से (ग) : एक ऐसे देश में जो स्वयं ही ग्रधोविकसित है समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक--आर्थिक परिस्थितियों में बड़े परिवर्तन लाने की समस्या ऐसी है जिसके शीघ्र अथवा आमूल उपचार नहीं हो सकते । 1950 से किये जा रहे उपायों के यथेष्ट परिएाम निकले हैं, तथा इन उपायों को कुछ समय तक जारी रखना पड़ेगा।

चीनी के निर्यात के लिये राज सहायता

- #848: श्री रा० की० ध्रमीन: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि चीनी के निर्यात पर सरकार अब भी राज सहायता देती है; और
- (ख) इस निर्यात के लिये उससे प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा से अधिक राशि की राज सहायता देने की नीति अपनाने के क्या कारण हैं ?
- खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क): जी नहीं। चालू वर्ष 1968 में सरकार निर्यात के लिये कोई राज सहायता नहीं दे रही है।
 - (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड

#849: श्री प्रेम चन्द वर्माः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड के कार्यकरण का किसी समय कोई सामान्य मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिगाम निकला; और
- (ख) क्या इनकी कार्य-प्रणाली में व्याप्त रुचियों का पता लगाने तथा उसमें सुघार करने के लिये सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ की सेवा प्राप्त करने का है ?

संसद-कायं तथा संचार तिभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल): (क): हिन्दु-स्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटंड के कार्य-निष्पादन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। कम्पनी निरन्तर उन्नित कर रही है, एवं कम्पनी के दार्य संचालन के विषय में सामान्य मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं समभी गयी है। कम्पनी ने 1967-68 के लिये 10 प्रतिशत के लाभांश (डिविडेण्ड) की घोषणा की है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को हब्टि में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

Allotment of Plots to Displaced persons from East Pakistan in Kalkaji, New Delhi

- *850. Shri Ranjit Singh: Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that about three thousand plots of land had been allotted to the displaced persons from East Pakistan in Kalkaji Colony, New Delhi:
- (b) whether it is also a fact that these plots have not so far been made available to them; and
 - (c) if so, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) 1365 plots have already been allotted by lottery out of 2117 plots formed in the colony.

(b) and (c): After a plot of land was offered to an applicant, he was required to make a deposit of 20% of the estimated amount of premium payable for the plot. Thereafter, plots were allotted by draw of lots. After that, the allottees have been asked to pay the first out of seven instalments by which they have to pay the balance of the premium. Some of the allottees have asked for extension of time and others numbering 1103 have paid the first instalment. The latter are being asked to execute the necessary agreement. So far nine persons only have executed agreements and seven out of them have been given authority to take possession of their plots from the Officer posted at the site in the Colony for this purpose.

Panchayat Elections in U. P.

- *851. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether Government are aware that Panchayat Elections have not been held in Uttar Pradesh for a period of more than six years;
 - (b) if so, the reasons therefor; and
- (c) the action taken by Government for holding elections for the Panchayats in Uttar Pradesh forthwith ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): Yes, Sir.

(b) and (c): Gram Panchayat elections had to be postponed, to begin with, on account of the then Fmergency Subsequently these elections, as well as fresh elections to Kshetra Samitis and Zila Farishads, have remained held up as the State Government have been wanting to amend the relevant laws with a view to affecting needed improvements. Meanwhile, the State Assembly stands dissolved. The State Government now propose to hold fresh elections to the Panchayati Raj bodies, at different levels, after the forthcoming mid-term poll in the State.

कोयला खनन उद्योग द्वारा मजुरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

- #852. श्री रिव राय: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) वया यह सच है कि सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया है कि कोयले के केन्द्रीय सरकार के मुख्य खरीदार केवल उन कोयला खान के टेन्डरों को ही, जिन्होंने कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मञ्जरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है स्वीकार करेंगे;
- (ख) यदि हां, तो किन-किन कोयला खानों में, विशेष रूप से महंगाई भत्ते के बारे में, मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है; और
 - (ग) उसका व्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) सरकार ने यह निर्णय किया है कि रेलवेज, इस्पात कारखानों तथा विद्युत उपक्रमों जैसे मुख्य सरकारी के ताओं को केवल उन्हीं कोयला खानों/प्रबन्धकों से कोयले की सप्लाई के टेन्डर स्वीकार करने चाहिए, जो अपने क्षेत्र के प्रादेशिक श्रम आयुक्त से प्राप्त यह प्रमाण-पत्र पेश करें कि उन्होंने कोयला खनन उद्योग सम्बन्धों मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कियान्वित कर दिया है।

(ल) और (ग): इस विषय के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के ध्यान में केवल वही मामले आते हैं, जिनमें औद्योगिक विवाद उठाए जाते हैं।

धनुसूचित जातियों/ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों के लिए लोक समा/विधान सभाग्रों में स्थानों के ग्रारक्षण की ग्रविध का बढ़ाया जाना

- #853. श्री श्रद्धाकर सूपकार: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए लोक सभा तथा विधान सभाओं में स्थानों के आरक्षण की अविध को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; ग्रीर
 - (ख) क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती)फूल ेणु गृह : (क) तथा (ख) सविधान के श्रनुच्छेद 334 के अधीन इस समय की गई श्रविध केवल वर्ष 1970 में समाप्त होगी, इसलिए इतना शीघ्र इस प्रश्न पर निर्णय लिया जा सकता।

सुपर फास्फेट का उत्पादन ग्रीर ग्रायात

- #854. श्री म० सुदर्शनम : क्या खाद्य तथा कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क नया यह मच है कि सुपर फास्केट के कुछ कारलानों ने कम मांग होने के कारण उत्पादन बन्द कर दिया है; और
- (ख) वया सुपर फास्फेट का आयात किया जा रहा हैं और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी तथा कितने मूल्य की सुपर फास्केट का आयात किया गया ?
- खाद्य. कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिग्दे): (क) कुणल विप्णान संगठनों की कमी और प्रोत्साहन सम्बन्धी उपायों की अनुपस्थिति में मुख्यत: सुपर-फास्फेट के स्टाक इकट्ठा हो जाने के कारण 1968 की अवधि में कुछ सुपर फास्केट के कारखानों ने विभिन्न अविधियों के लिये उत्पादन बन्द कर दिया था।
- (ख) पिछले 3 वर्षों की अवधि में खेतों में खाद देने के लिये सुपर-कास्फेट का कोई आयात नहीं किया गया है। फिर भी डाय-अमोनियम फास्केट, अमोनियम सल्फेट और एन० पी० के० जैसे कोम्पलैक्स उर्वरकों को ग्रायात किया गया था जिनमें फास्फोरिक ऐसिङ होता है।

उपस्थिति बोनस योजना

- #855. श्री कि० प्र० सिंह देव: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने कोयला खान बोनस योजना के समान एक 'उपस्थिति बोनस योजना' बनाने का प्रस्ताव किया था;
 - (ख) क्या इस प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकारों के विचार मालूम किये गये हैं;
 - (ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने क्या मत व्यक्त किये हैं;
 - (घ) क्या सरकार ऐसी योजना बनाने के लिए सहमत हो गई है; और
 - (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) अभ्रक, मैंगनीज और कच्चा-लोहा खानों के श्रमिकों के लिये कोयला खान बोनस योजना के आधार पर हाजिरी बोनस योजना बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग): सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श किया गया। उनमें से कुछ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि अन्य सरकारों ने उसका विरोध किया है। (घ) ग्रीर (ङ): इस विषय पर गैर-कोयला खान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के 7 नवम्बर, 1968 को हुए पांचवे अधिवेशन में विचार किया गया। उसमें यह तय किया गया कि इस सम्बन्ध में निर्णय लेने से पहले श्रमिकों और नियोजकों के संगठनों के विचार जान लेने चाहिए। आगे कार्यवाही तदनुसार की जा रही है।

Retrenchment in Jute Mills in West Bengal

*856. Shri Ramavatar Shastri: Shti B. K. Modak:

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a large number of Labourers have been retrenched in the various jute mills in West Bengal during the last few months;
 - (b) if so, the number with the names of mills;
- (c) whether it is also a fact that Bengal Jute Workers Union has urged the Government of India to intervence in the matter and to stop the illegal retrenchment;
 - (d) if so, the reaction of Government thereto;
- (e) whether it is also a fact that several suggestions have been offered by the Union to avert the crisis in jute mills; and
- (f) if so, the details regarding the suggestions and action proposed to be taken by Government to stop the retrenchment?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) to (f): According to the information received from the Government of West Bengal only 7 workers belonging to the regular working force were retrenched during the last six months—four from New Central Jute Mills Company Ltd., Budge-Budge, 24-Parganas; one from Kamarhati Co. Ltd., Kamarhati, 24-Parganas; and two from Howrah Mills Co. Ltd., Sibpur, Howrah. The problem of surplus labour is being tackled by the mills by taking steps to superannuate workers who are near the retiring age on payment of suitable compensation. Leave facilities are being libera ised and surplus workers deployed in carpet backing sections, where possible. These measures have created vacancies for many worker who would have otherwise become redundant.

- 2. There is no union by the name of Bengal Jute Workers' Union. However, the Bengal Chatkal Mazdoor Union has asked for an early meeting of the Industrial Committee on Jute to discuss the problems arising out of sealing of looms in some mills and has made the following suggestions:—
 - (i) Maintenance of status quo in jute mills as it existed on the 20th October, 1968;
 - (ii) Reduction of working hours to 45 hours a week;
 - (iii) Introduction of State Trading in procuring raw jute.

A meeting of the Industrial Committee on Jute had been called on the 28th December, 1968 but had to be postponed as this date did not suit one of the Unions. The Committee will be called to meet as early as possible.

मत पेडियों का निर्माण

#857. श्री ज्योतिमंय बसु: क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 1962 के साधारण निर्वाचनों के लिए मत पेटियों का निर्माण करने के लिए मैसर्स खेतान ब्रदर्स 4, क्वीन पार्क, बालीगंज, कलकत्ता को ठेका दिया गया था; और यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार तथा मैसर्स खेतान ब्रदर्स के बीच कोई लिखित करार हुआ था;
- (ख) करार के अनुसार उन्होंने कितनी मत पेटियों का निर्माण करना था ग्रीर इस प्रयोजन के लिए सरकार ने कुल कितना इस्पात दिया था;
- (ग) कितनी मत पेटियों का वास्तव में निर्माण किया गया और निर्माताओं के पास कितना ऐसा इस्पात बचा था जिसका प्रयोग नहीं किया गया था और क्या वह सरकार को लौटा दिया गया था; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या यह सच है कि मेसर्स खेतान ब्रदर्स द्वारा बनाई गई मत पेटियों को इस कारण रद्द कर दिया गया था क्योंकि इस फर्म के एक कर्मचारी से यह सूचना मिली थी कि पेटी का डिजाइन किसी एक विशेष राजनीतिक दल को पहले ही दिखा दिया गया है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार 1962 के साधारण निर्वाचनों के लिए मत पेटियों के निर्माण के बारे में सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक विवरण सभा-पटल पर रखेगी?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी नहीं।

- (ख) से (घ): प्रश्न ही नहीं उठते।
- (ङ) 1962 के साधारण निर्वाचनों के लिए मत पेटियों का कोई निर्माण नहीं किया गया था।

Slaughtering of Cows in U.P.

- *858. Shri Ram Gopal Shalwale: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that cows in large numbers are being brought from Rajasthan and Haryana and slaughtered in U.P.
 - (b) if so, whether it is a fact that cow slaughter is banned in U.P.;
- (c) if so, whether Government propose to issue directions to U.P. Government for the strict enforcement of the law in order to check the slaughtering of bovine cattle; and
 - (d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir.

- (b) Yes, Sir.
- (c) and (d) No Sir. The Act is being enforced by the U.P. Government. No direction from the Government of India appears called for.

Slaughtering of Bovine Cattle in District Rampur (U.P.)

*859 Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Chairman of the Standing Committee of the Municipal Corporation of Delhi has written a detailed letter to Government after his tour of the district of Rampur, U.P. about the slaughtering of 50,000 bovine animals in that District and urged upon them to stop that; and
 - (b) if so, the action taken by Government in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) Information is being collected from the State Government of Uttar Pradesh.

Exodus of Cattle from Rajasthan

- *860. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether Government's attention has been drawn to the exodus of cattle in large numbers from Jaisalmer, Barmer, Bikaner, Jodhpur Districts of Rajasthan due to serious famine conditions;
- (b) whether it is a fact that a large number of cattle heads are being transported to Uttar Pradesh with a view to slaughter them as a result of the aforesaid famine conditions in Rajasthan:
- (c) whether Government propose to transport the said cattle heads on Government level with a view to prevent slaughter of the said cattle heads; and
 - (d) if not, why?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

- (b) No, Sir.
- (c) Government of Rajasthan is already providing facilities for transport of cattle from these districts to other districts of the State or to such places where fodder and water is available so that cattle could be preserved till the next monsoon season.
 - (d) Does not arise.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

- #861. श्री स॰ मो॰ बनर्जी: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि विधि मंत्रालय ने पहले यह मत व्यक्त किया था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक उद्योग है; और
 - (ख) यदि हां, तो ग्रब अपना मत बदलने के क्या कारण हैं ?
 - श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां। ग्रप्रैल 1966 में।
- (ख) वर्तमान मत मद्रास जिमखाना क्लब और क्रिकेट क्लब ग्राफ इण्डिया, बम्बई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों पर आधारित है।

Industrial Unrest in Public Sector Undertakings

- *862. Shri Bhola Nath Master: Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:
- (a) whether a memorandum was submitted by the Hindustan Steet Ltd. to the National Commission on Labour to the effect that the cause of industrial unrest in public sector undertakings was due to influence of the political parties on Trade Unions;
- (b) whether it is a fact that loss to the tune of crores of rupees had to be suffered in the Durgapur Steel Plant from March to July, 1:67 due to labour unrest and failure of workers to work according to the code of discipline;
 - (c) if so, the number of cases of gheraos in Durgapur, during this period; and
- (d) whether such gheraos are due to the fact that the State Governments do not effectively apply the code of discipline?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) In its replies to the Commission's questionnaire, prefaced by a short memorandum, a reference has been made to this and other causes of industrial unrest;

- (b) According to the memorandum, the loss in the Durgapur Steel Plant was of the order of Rs. 12.70 crores.
 - (c) Ninetyfive during March to September 1967.
- (d) A number of factors have caused "gheraos" in the country, of which the failure of employers and workers to implement the Code of Discipline is only one.

दिल्ली में राशन की दुकानों से चावल की सप्लाई

- #863. श्री ग्रदिचन: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) दिल्ली में राशन की दुकानों से चावल की अनियमित सप्लाई के क्या कारण हैं:
- (ख) गत कुछ महीनों से इन दुकानों से घटिया किस्म के चावल सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं; और
- (ग) बासमती तथा श्रच्छी किस्म के चावल के न दिये जाने के क्या कारण हैं, विशेष-कर जबकि खुले बाजार में चावल का मूल्य बहुत अधिक है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रन्नासाहिब किन्दे): (क) और (ख): दिल्ली को चावल और गेहूँ के उत्तरी क्षेत्र में सिम्मिलत करने से वहां सांविधिक राशन व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। खुले बाजार में मारी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं और अधिकांश उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुले बाजार से ही करते हैं। तथापि दिल्ली में चावल और गेहूं का निर्गम निर्धारित मूल्यों पर उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से हो रहा है। उचित मूल्यों की दुकानों से दिए गए चावल की किस्म घटिया नहीं है परन्तु यह पौष्टि कारणों से पालिश करने पर प्रतिबन्ध होने से खुले बाजार में उपलब्ध चावल से हल्ली दिखाई देती है।

(ग) कुछ समय के लिए स्टाक की कमी के कारण बग्समती चावल देना बन्द कर दिया गया था परन्तु अन्य किस्मों के चावल पूरी मात्रा में उपमोक्ताओं के लिए उपलब्ध थे। 4 दिसम्बर, 1968 से बासमती चावल फिर से दिया जा रहा है।

धासनसोल तथा दुर्गापुर में मूमि का घंसना

♦864. श्री मुहम्मद इस्माइल: श्री भगवान दास:

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में आसनसील तथा दुर्गापुर सब डिवीजनों में बड़ी संख्या में ग्राम, कस्बे तथा बाजार घंस गये हैं;
- (ख) क्या यह भी सच है कि इसका कारण कोयला खानों के मालिकों द्वारा अवैध खनन है; और
 - (ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं। रानीगंज कस्बे, बाराकार कस्बे, केन्दुआ बाजार और कुल्टी में भूमि घंसने की थोड़ी सी घटन।यें हुई हैं।

- (ख) जी नहीं।
- (ग) प्रश्न नहीं उठता।

द्यासनसोल में मूमि घंसना

- ***865. श्री गरोश घोष : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज आसनसील क्षेत्र में कई ग्रामों तथा कस्बों को रिहायश के सम्बन्ध में खतरनाक घोषित कर दिया गया है;
- (ख) कुल कितने प्रामों को अयोग्य घोषित किया गया है और कुल कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा;
- (ग) क्या प्रभावित व्यक्तियों के लिये कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं, यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है; और
 - (घ) यदि कोई प्रतिबन्ध नहीं किये गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ध्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

- (ख) अभी तक 23 गांव खतरनाक घोषित किये गये हैं। यह मालूम नहीं है कि इसका प्रमाव कितने लोगों पर पड़ा।
 - (ग) और (घ) इन मामलों पर पश्चिमी बंगाल की सरकार विचार कर रही है।

Grants in Aid To States

- *866. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of Social Welfare be pleased to state:
- (a) the names of the states which have been furnishing the details of expenditure before the end of February each year in regard to the grants-in-aid given to them for their

development works according to the p. ovisions of Article 275 (1) of the Constitution and the Ministry of Home Affairs letter No. 74/4251-Lok dated the 17the November, 1951 addressed to all the Part 'A' States, except Uttar Pradesh and to all the Part 'B' States (except Jammu and Kashmir and Pepus); and

(b) the details of the amount sanctioned finally by the Central Government, spent and surrendered by the State Governments, item wise and year-wise during the last five years?

The Minister of State in the Department of Social Velfare (Dr. Smt. Phulrenu Guha)
(a) The procedure prescribed in the letter under reference was applicable in the pre-Planperiod. Also, thereunder only the details of schemes were required to be furnished. The
question of runishing the details of expenditure in accordance with that letter, therefore,
does not arise.

(b) The amount sanctioned finally by the Central Government is based on the actual expenditure figures. The details for the last five years are as under:

Year	(Rs. in lakhs)		
	State Sector	Central Sector	
1964-65	472,80	572,97	
1965-66	367.11	756 06	
1966-67	297.12	979-26	
1967-68 (Anticipated).	195.51	559.82	
1968-69 (-do-)	223.83	681,79	

चीनी की उत्पादन लागत में वृद्धि

#867. श्री हिम्मत सिंह का: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी की उत्पादन लागत जो अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन लागत की तुलना में मारत में पहले ही बहुत अधिक है, में किसी वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्ना-साहित्र किन्दे): चीनी की उत्पादन लागत के मुख्य तत्व ये हैं (1) गन्ने की लागत, (2) सरकारी कर और (3) बनाने की लागत जिसमें लगी पूंजी पर लाम भी शामिल है। चीनी तैयार करने की लागत का प्रक्रन टैरिफ आयोग को भेजा गया है। गन्ने की लागत में वृद्धि को प्रति एकड़ उपज बढ़ाकर और गन्ने में चीनी तत्व की बढ़ोतरी कर रोका जा सकता है। चीनी कारखानों को गन्ने की उपलब्धि बढ़ाकर और उसकी किस्म में सुधार कर चीनी तैयार करने की लागत में कमी करना भी सम्भव है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चीनी तैयार करने वाले प्रमुख राज्यों की राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे चीनी कारखानों के इदं-गिदं सधन विकास क्षेत्र बनाए और इस प्रयोजन के लिए केन्द्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता के आधार को उदार कर दिया गया है।

ग्रधिक निर्वाचन ग्रायुक्तों की नियुक्ति

#868. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या इस बात को देखते हुए, कि देश में मतदाताओं की संख्या जो वर्ष 1952 में 17 करोड़ 60 लाख थी बढ़ कर वर्ष 1967 में 20 करोड़ हो गई है, सरकार ने और अधिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करने की वांछनीयता पर विचार किया है जैसा कि सविधान में अनुच्छेद 324 में प्रकल्यित है; और
- (ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) सरकार यह आवश्यक नहीं समभती कि देश में मतदाताओं की सस्या बढ़ जाने मात्र से अधिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपास का उत्पादन

***869.** श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी:

श्रीलोबो प्रभु:

श्री सीताराम केसरी:

नया खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत दस वर्षों में कपास के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने तथा उस की किस्मों की सुघारने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं;
- (ख) इन विकास कार्यक्रमों पर कितना धन खर्च किया गया तथा इसके क्या परिएाभ निकले है;
- (ग) वर्ष 1950-51, 1955-56, 1960-61 और 1967-68 के मौसमों में कुल कितना भूमि पर कपास की खेती की गई थी और इन वर्षों में की गई कपास की खेती वाली भूमि में से कमश कितनी-कितनी भूमि में सिंचाई होती थी; और
- (घ) लम्बे रेशे वाली. मध्यम रेशे वाली ग्रीर छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन कितना कितना हुआ है ग्रीर पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों की समाष्ति पर तथा अन्तिम फसली वर्ष में हुए कपास के कुल उत्पादन का यह कितने प्रतिशत था?
- खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) रा यों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे पैकेज कार्यक्रम के आधार पर समन्वित कपास विकास योजनाओं और कपास की सघन खेती के अतिरिक्त, कपास उत्पादन और अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन को ग्रधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिये कपास के उत्पादन और उस की फसल की किस्म में स्धार करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें शुरू की गई है।
 - (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समा पटल पर रख दी जायेगी।
- (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है (विवरण 1) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2780/68]

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है (विवरण 2) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2780/68]

विकलांगों के सुयोग्य नियोजक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

- #870. श्री चेंलराया नायडु: क्या समाज कल्याए। मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के सुयोग्य नियोजकों और अत्यन्त कुशल विकलांग कर्मचारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना बनाई है ;
 - (ख) यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ होने की संभावना है ; और
 - (ग) इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

समाज कल्यारण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीवती) फूलरेखु: गुह: (क) हां श्रीमान् ।

- (ख) प्रथम पुरस्कार मार्च 1969 में दिए जांत का प्रस्ताव है।
- (ग) तीन पुरस्कार, जिनमें एक वाचन-पत्र, एक शील्ड तथा कांग्रेस का एक पदक शामिल होंगे, विकलांग व्यक्तियों के सुयोग्य नियोजकों को दिए जाने का प्रस्ताव है। इतने ही पुरस्कार, जिन में से प्रत्येक में एक वाचन-पत्र तथा 500 रूपये का नकद पुरस्कार शामिल होंगे। अत्यन्त बुशल विकलांग कर्मचारियों को दिए जाने का प्रस्ताव है।

वन संसाधनों का पूंजी नियोजन-पूर्व सर्वेक्षरा

- 5056. श्री हेमराज: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 13 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृषा करेंगे कि:
 - (क) क्या वन संसाधनों का पूंजी विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षरा पूरा हो गया है ; और
 - (ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्ना साहिब किन्दे): (क) ग्रीर (ख): यद्यपि विश्व खाद्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यंक्रम की सहायता से कियान्वित की जाने वाली वन साधन का निवेश पूर्व सर्वेक्षण परियोजना 31-10-68 को समाप्त हो गयी है, किन्तु चतुर्ष योजना की स्कीमों में से एक से रूप में वन साधन का निवेश पूर्व सर्वेक्षण का कार्य जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

राष्ट्रीय श्रम श्रायोग द्वारा गठित सिनित द्वारा सप्लाई करने वाले कर्मचारियों के काम की तथा सेवा की शर्तों का श्रध्ययन

5057. श्री सिद्धया : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफाई करने वाले कर्मचारियों की काम की तथा सेवा की शर्ती का अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिबेदन तैयार कर लिया है; और (ख) यदि हां, तो समिति की निफारिशें क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख): इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भायोग को प्रस्तृत कर दी है। सरकार को मात्रूम हुआ है कि समिति द्वारा की गई सिफ।रिशें आयोग के विचाराधीन हैं।

Low-Income Group Scholarships to Students in Madhya Pradesh

5058. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of Social Welfare be pleased to state:

- (a) the number of students in Madhya Pradesh who were granted low-income group scholarships by the Central Government during 1967-68;
 - (b) the total amount thereof;
- (c) the income group of guardians of students who were granted such scholarships; and
 - (d) the income-limit stressed by Madhya Pradesh Government ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha)

- (a) 1152.
- (b) Rs. 5,60,177.
- (c) and (d) Below Rs. 2000 per annum.

Sugar Mills in Madhya Pradesh

5059. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) the annual production of Sugar in each Sugar Mill in Madhya Pradesh during the last three years;
- (b) the quantity of sugar supplied by the Madhya Pradesh Government to the Centre and to each state during the said period; and
- (c) the quantity of sugar consumed in Madhya Pradesh each year during the said period?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The annual production of sugar by each sugar mill in Madhya Pradesh during the last 3 years was as under:—

Location of factory	Sugar produced during the season (October to September) (figures in tonnes)			
	1965-66	1966-67	1967-68	
Dabra	10,960	2,051	936	
Dalauda	4,871	1,679	Not worked	
Jaora.	6,026	1,926	1,860	
Mehidpur	3,687	Not worked	Not worked	
Sehore	10,352	1,851	803	

(b) Control over release of sugar from factories in Madhya Pradesh and other States is exercised by the Central Government and not by the State Governments. The

sugar produced by the factories in Madhya Pradesh was supplied to various other States as under:

			(In tonnes)			
	Gujarat	Maharashtra	U. P.	Delbi	Rajasthan	Total
1965-66	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
1966-67	174	765	196	186	Nil	1321
1967-68 (including free sugar)	51	591	180	115	66	1003

(c) The quantity of sugar consumed in Madhya Pradesh during each of the last 3 years was as under:—

	(Lakh tonnes)	
1965-66		1.57
1966-67	•••	1.42
1967-63		0,99

रतलाम में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी

5060. श्री स॰ मो॰ बनर्जी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि रतलाम, मध्य प्रदेश में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को निरंतर तथा जानबूभकर दंडित करने तथा तंग करने की घटनाएं हुई हैं;
- (स) क्या यह भी सच है कि वास्तविक बीमारी के आघार पर भी कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश नहीं दिया गया है;
- (ग) क्या इन मामलों में कानून और नियमों के विरुद्ध ग्रन्धाषुन्ध तथा गैर कानूनी दण्ड दिये गये हैं;
- (घ) क्या यह भी सच है कि इन गैर-कातूनी कार्यवाहियों के विरुद्ध विभागीय पत्र-व्यवहार करने तथा अभ्यावेदन देने अथवा अपील करने की अनुमित नहीं है और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है; और
- (ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में, विशेषतः उत्तरदायी अधि-कारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विमाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजरात): (क) जी नहीं, इसके विपरीत जनता तथा वफादार कर्मचारियों दोनों से हड़ताल में सिक्रय माग लेने वाले कुछ कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

- (ख) तथा (ग): जी नहीं।
- (घ) तथा (ङ)ः जी नहीं। लेकिन एक मिसाल ध्यान में आई है जहां याचिका अपने तत्काल उच्च अधिकारी के उचित माध्यम द्वारा न भेजकर सीधे ही उच्च प्राधिकारी को भेज दी गई थी और तत्काल उच्च अधिकारी ने याचिका को गलतफहमी के कारण अग्रसारित नहीं किया कि उच्च प्राधिकारी उनको सीधी भेजी गई प्रति पर कार्रवाही करेंगे। उनको इस संबंध

में उचित भ्रनुदेश दे दिये गये हैं। याचिकाओं की प्राप्ति स्वीकार करने का कोई नियम नहीं है।

रतलाम के डाक तथा तार कर्मचारी

5061. श्री स॰ मो॰ बनर्जी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि रतलाम के डाक तथा तार विमाग के कई कर्मचारियों को हाल ही में हुई ट्रेड यूनियन के आन्दोलनों में माग लेने के कारए दण्ड दिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो पदावनित, सेवासमाप्ति, स्थानान्तरण तथा निलम्बन आदि के अलग-अलग मामलों की संख्या कितनी है;
 - (ग) इन कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के कारण क्या हैं;
- (घ) क्या यह भी सच है कि कानून तथा नियमों के विरुद्ध गैर हड़ताली कमंचारियों को भी दण्ड दिया गया ; और
- (ङ) कर्मचारियों में फिर से विश्वास तथा प्रतिष्ठा की भावना पैदा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा सचार विमाग में राज्य मंत्री. (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी नहीं, जो भी कार्रवाई की गई वह 19-9-68 को हुई गैर-कानूनी हड़ताल तथा उसके बाद के आन्दोलन में माग लेने और उनसे संबंधित गतिविधियों के लिए की गई थी।

- (ख) पदावनित के मामलों की संख्या-कुछ नहीं अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के मामलों की संख्या 22 स्थानान्तरण के मामलों की संख्या 4 निलम्बन के मामलों की संख्या 33
- (ग) अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1964 के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई थी। कर्मचारियों का निलम्बन या तो गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप या विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने के उपक्रम के बतौर किया गया था। उनके स्थानान्तरण प्रशासनिक सुविधा के हित में किये गये।
 - (घ) जी नहीं।
 - (इ) उक्त परिस्थितियों में इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली स्थित कालाकजी बस्ती में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाना

5062. श्री प्र० रं० ठाकुर: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नई दिल्ली स्थित कालकाजी में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती के आवास भू-खंडों का अधिकार मकान के अलाटियों को कब तक दिया जायेगा;
- (ख) बस्ती का वर्तमान विकास विशेषकर पानी, बिजली और सड़कों के निर्माण की दिशा में कहां तक हुआ है; और
 - (ग) मकानों में अलाढी कब तक अपने मकानों का निर्माण आरम्म करेंगे ?

अम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा॰ रा॰ चव्हारा): (क) पुनर्वास विभाग द्वारा अलाटियों को पत्र जारी किये जा रहे है जिनमें कहा गया है कि आवश्यक करार कर दें और प्लाटों का कब्जा ले लें।

- (ख) बस्ती का आन्तरिक विकास, जिसमें सड़कों, नालियों, मल-व्यवस्था तथा सम्प (चौबचा), ऊपरी टंकी तथा जल संभरण के लिये पाइप लाइनों का निर्माण सिम्मिलित है प्रायः पूर्ण हो चुका है। मकानों के निर्माण के लिये आवश्यक जल-संमरण की त्वरित व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली नगर निगम की पाईप लाइनों में जल संभरण की वृद्धि करने के उद्देश्य से नलकूप खोदने, पम्प-गृह के निर्माण तथा पम्प स्थापित करने आदि का कार्य प्रगति पर है ताकि निगम बस्ती में जल संभरण की स्थायी व्यवस्था कर सके। दिल्ली नगर निगम की पुरानी कालकाजी बस्ती में स्थित लाइनों में मल का निकास करने के लिये निगम द्वारा एक सम्पर्क लाइन स्थापित की जा रही है, कार्य 8 से 10 मास की अविध में पूर्ण होने की संभावना है। जैसे ही प्लाटों के मालिक अपने मकानों का निर्माण कार्य ग्रारंम करेंगे सड़कों की रोशनी का कार्य पूर्ण हो सकेगा और रहने वालों के मकानों को बिजली दी जा सकेगी।
- (ग) वया सरकार से प्लाटों का कब्जा लेने के उपरान्त, अलाटी अपने मकानों के निर्माण की ब्यवस्था स्वयं करेंगे।

Post Offices in Gram Panchayats of Madhya Pradesh

- 5063. Shri G. C. Dixit; Will the Minister of Communications be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that Post Offices have not been set up in each Gram Panchayat area in Madhya Pradesh;
- (b) if so, the number of Gram Panchayat areas where Post Offices have been set up and the number of those Gram Panchayat areas where no post office exists at present; and
- (c) the time by which Government propose to achieve the target of opening a post office for every 2000 persons?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b): 5, 168 post offices are functioning in villages which are headguarters of Gram Panchayats. All villages in Gram Panchayat areas are covered by the existing post offices 11,383 villages, which are headquarters of Gram Panchayats, have not been provided with post offices.

(c) Does not arise as no such policy has been decided upon.

P and T Offices, Telephone Exchanges etc. in Madhya Pradesh

- 5064. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of Communications be pleased to state:
- (a) the target fixed in respect of introducing new telephone lines, branch offices, sub-Post offices and telephone exchanges in Hoshangabad and Eastern Nimad districts of Madhya Pradesh during the current year;
- (b) whether it is a fact that there is generally too much delay in setting up new post offices, sub-Post offices and telephone exchanges; and
- (c) if so, the action proposed to be taken by Government to ensure that these are set up according to schedule?

The Minister of State for Parlimentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral.): (a) One telephone trunk line between Khandwa and Khargone is likely to be commissioned during the current year.

One P. C. O. in Hoshangabad is expected to be opened during the year.

No new telephone exchanges are proposed to be set up in these districts during 68-69.

- 4 Branch offices, 2 each in Hoshangabad and East Nimad district are proposed to be set up during the year. 7 Branch offices (2 in Hoshangabad district and 5 in East Nimad district) are expected to be up, graded into sub-offices.
 - (d) No.
 - (c) Does not arise.

राज्यों को उर्वरकों का नियतन भ्रीर उसकी खपत

5065. श्री स्रजभान: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मारत में वर्ष 1964, 1965 और 1966 में विभिन्न नाइट्रोजन्स फौसकेटिक तथा ग्रनेक प्रकार के उर्वरकों का राज्य-वार कितना नियतन किया गया तथा उनकी कितनी ख़पत हुई; ग्रीर
- (ख) क्या उक्त अविध में राज्य-वार तथा वर्षवार प्रत्येक प्रकार के उवंरकों की कोई 'कमी / अधिकता थी ?
- खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्ना साहिब शिन्दे): (क) अपेक्षित जानकारी प्रदिश्चित करने वाले विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 1 तथा 2)। [पुस्तकालय में रखा गया। देंखिये संख्या एल. टी. 2781/68]
- (ख) राज्यों से व्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और मिलते ही समा पटल पर रख दिया जायेगा।

मारतीय खाद्य निगम को धनाज की सप्ताई के लिये भुगतान रोक लेना

5066. श्री श्रोंकार लाल बेरवा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृषा

- (क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम अनाज के टेन्डरों पर सप्ताई किये गये अनाज के मुल्य का 95 प्रतिशत खाद्यानों की सप्लाई होने के समय श्रीर शेष दो महीनों के अन्दर किए परीक्षरण की रिपोर्ट मिलने पर करता है;
- (ख) क्या कुछ परिस्थितियों में अनाज की सप्लाई के पूरे के पूरे भुगतान को रोकने का अधिकार भारतीय खाद्य निगम को है, और यदि हां, तो उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या मैससँ तिलक राज धर्मगाल, लुधियाना द्वारा पिछले चार महीनों मे जिला मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम, लुधियाना को सप्लाई किये गये समस्त अनाज के मूल्य के भुगतान को रोक लिया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ग्रीर क्या इस बात की सूचना सप्लाई करने वालों को देदी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां, केवल शेष 5 प्रतिशत का भुगतान जो लेबोरेट्री विश्लेषण रिपोर्ट मिलने पर किया जाता है को छोड़कर और उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है।

- (ख) जी नहीं।
- (ग) जी नहीं।
- (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

माडनं बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड

5067. श्री बाबू राव पटेल: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा गत तीन महीनों में बम्बई, अहमदाबाद, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में नगर-वार कितनी तथा कितने मूल्य की डबल रोटी की बिक्री की गई;
- (ख) श्वेत डबल रोटी में कौन-कौन से पोष्टिक तत्व मिलाये जाते हैं और विभिन्न नगरों में प्रत्येक 'लोफ' का भार तथा मूल्य कितना है ;
- (ग) प्रत्येक एकक द्वारा उस की स्थापना से ले कर अब तक नगर-वार तथा वर्ष-वार कितना मुनाफा कमाया गया ;
 - (घ) सरकार द्वारा विभिन्न एकको में अब तक वास्तव में कितनी पूंजी लगाई गई है;
- (ङ) बेकरियों में कितने तथा कौन-कौन से विदेशी विशेषज्ञ अथवा अधिकारी काम कर रहे हैं तथा एकक-वार उन के पदनाम क्या हैं तथा उनको कितना वार्षिक वेतन दिया जाता है ; और
- (च) उनको कितने समय के निये नियुक्त किया जायेगा, और उनको प्रतिवर्ष कितनी राशि अथवा वेतन का कितने प्रतिशत भाग अपने देश भेजने की अनुमति है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2782/68]

- (ख) ये तत्व इस प्रकार हैं:---
- (1) विटामिन 'ए'
- (2) थिया-माइन
- (3) रिबोफलाविन
- (4) नियासीन
- (5) आयरन
- (6) लाइसिन
- (7) दुग्ध चूर्ण और
- (8) माल्ट-सत

सभा के पटल पर रखे गए विवरण में विभिन्न शहरों में डबलरोटी की कीमत और वजन चताया गया है।

- (ग) क्योंकि माडनें बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड के पहले यूनिट ने केवल जनवरी, 1968 में उत्पादन शुरु किया था और मार्च, 1968 तक उत्पादन का एक वर्ष मी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।
- (घ) कम्पनी को 65 लाख रूपये के ऋगा के अतिरिक्त सरकार ने कुल एक करोड़ रूपये लगाए हैं। यह पूंजी यूनिट वार नहीं लगायी गई है।
 - (ङ) शुन्य।
 - (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू-कश्मीर के रिटर्निंग धाफिसर के विच्छ कूढ रखना धीर साक्य गढ़ने के धारोप

5068. श्री बाबू राव पटेल: श्री श्रीचन्द गोयल:

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने निर्वाचन अर्जी में जिस रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर के विरुद्ध शपथभंग, कूट रचना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए अजियोजन के आदेश दिये हैं उनके नाम क्या हैं;
- (ख) इन आफिसरों द्वारा किए गए अपराधों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर किन धाराओं के अन्तर्गत आरोप लगाए गए हैं;

- (ग) इन आफिसरों के अपराधों से विधान सभा के जिन अर्म्याधयों को लाम पहुँचा है उनके नाम क्या हैं तथा वे किस राजनैतिक दल के हैं;
 - (घ) क्या इन अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है; भ्रीर
 - (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मु॰ यूनुस सलीम): (क) रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर के नाम निम्नलिखित हैं :--

- (1) श्री अशोक कुमार, (आई० ए० एस०), सहायक आयुक्त (नं० 2), ग्रनन्तनाग (राजपुरा सभा निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर) और
- (2) श्री सफाया, सहायक निदेशक, पर्यटन, श्रीनगर (राजपुरा समा निर्वाचन क्षेत्र का सहायक रिटनिंट आफिसर)।
- (ख) आफिसरों को आरोप पत्र नहीं दिए गए हैं। उच्च न्यायालय ने इन आफिसरों से केवल यह कहा है कि वे बतायें कि शपथभग और कूट रचना भ्रादि के लिए उन पर अभियोग क्यों न चलाया जाये।
- (ग) उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आफिसरों ने यह अनियमिततायें राजपुरा सभा निर्वाचन क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर विधान सभा के सदस्य के रूप में श्री गुलाम मोहम्मद राजपुरी के अविरोध निर्वाचन को सुकर बनाने के लिए की थीं। श्री राजपुरी इण्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए अम्यर्थी थे।
- (घ) और (ङ): जी नहीं । आफिसरों ने उच्च न्यायालय द्वारा उनको दिए गए नोटिसों के विरुद्ध अपने लिखित कथन भेज दिये हैं ग्रीर मामला न्यायालय के समक्ष लिम्बत है। राज्य सरकार यह सनभती है कि इस प्रक्रम पर इन आफिसरों को निलम्बित करना उचित नहीं होगा ।

महस्यल में खेती कराने का कार्यक्रम

5069. श्री नरेन्द्र सिंह महीडाः श्री देवकीनन्दन पाटोदियाः

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मरुस्थल विकास बोर्ड ने चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात, हरियाणा ग्रीर राजस्थान के मरुस्थल में खेती करने का कार्यक्रम बनाया है;
 - (ख) यदि हां, तो इस का व्योरा क्या है; और
 - (ग) प्रत्येक राज्य में कुल कितना धन व्यय किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग): केन्द्रीय मकस्थल विकास बोर्ड ने 15 मई, 1968 की हुई ग्रपनी दूसरी बैठक में गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के महस्थल क्षेत्रों में चरागार विकास, भूमि संरक्षण, वनरोपण, कृषि विकास आदि की योजनाओं के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 करोड़ हपये के व्यय का सुफाव दिया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इस शीर्षक के अन्तर्गत होने वाले व्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मह क्षेत्रों में प्रारम्भ किये जाने वाले कार्य की विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय और उनके लक्ष्यों का निर्धारण धन के अन्तिम नियतन पर निर्भर करेगा। राज्यवार नियतन का प्रश्न केवल उसके उपरान्त ही उत्पन्न होगा।

विदेशों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी

- 5070. श्री सीमचन्द सीलंकी : क्या समाज कल्यामा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
- (क) इस वर्ष गुजरात से कितने विद्यार्थी विदेश गये हैं और उनमें अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं; और
- (ख) यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याए विभाग में राज्य मन्त्री (डा॰ (श्रोमती) फूलरेगु गुह): (क) ग्रीर (ख): विदेश-छात्रवृत्तियों की सामान्य परियोजना के अन्तर्गत गुजरात से 1968-69 के दौरान 4 विद्यार्थी अध्ययन हेतु विदेश गए। उनमें अनुसूचित जातियों/ग्रादिम जातियों का एक विद्यार्थी था।

विदेश छात्रवृत्तियों की विशेष परियोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और श्रादिम जातियों के आठ अभ्यार्थी चुने गये थे, किन्तु उनमें गुजरात का कोई नहीं था। गुण-आधार पर वे चुने जाते हैं; राज्यवार यथांश (कोटा) नहीं है।

गुजरात को ट्रैक्टरों की सप्लाई

- 5071. श्री सोमचन्द सोलंकी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) गुजरात राज्य को प्रति वर्ष कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता होती है और वर्ष 1968 में उसको कितने ट्रैक्टर सप्लाई किये गये;
- (ख) क्या ये ट्रैक्टर सरकारी अभिकरणों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा सप्लाई किये गये थे; और
- (ग) क्या गुजरात राज्य ने 1969 में ट्रैक्टरों के अतिरिक्त कोटे के कोई प्रस्ताव दिये हैं-रे
- खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख): देश में निर्मित ट्रैक्टरों के वितरण पर सरकार किसी प्रकार का

नियन्त्रए। नहीं रखती । शायद प्रश्न का सम्बन्ध आयातित ट्रैक्टरों से है। सन् 1968-69 में गुजरात राज्य को लगभग 1100 ट्रैक्टरों की आवश्यकता है। इसके मुकाबल में इसे 200 ट्रैक्टर पहले ही अलाट किये जा चुके हैं और बाकी शीझ ही अलाट कर दिए जायेंगे जिससे राज्य की आवश्यकता काफी हद तक पूरी हो जाएगी। ये ट्रैक्टर सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा वितरित किये जायेंगें।

(ग) जी नहीं, परन्तु राज्य सरकार ने 1969-70 के लिये 600 ट्रैक्टरों की आव-श्यकता की सूचना दी है। उस साल के लिए अलाटमैंट करते समय इसका भी ध्यान रखा जाएगा।

मद्रास सरकार को गेहुँ और चीनी का नियतन

- 5072. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने गेहूं तथा चीनी के अधिक नियतन के बारे में केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है; और
- (ख) यदि हां, तो कब तथा कितने गेहूं और चीनी का नियतन किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री स्रन्नासाहिब किन्दे): (क) और (ख): सितम्बर, 1968 में मद्राप्त सरकार ने सरकारी वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए गेहूँ का कोटा प्रति मास 10,000 मीटरी टन से बढ़ाकर 15,000 मीटरी टन करने के लिए अनुरोध किया था। राज्य सरकार का अनुरोध मान लिया गया था। इसके बाद मद्रास सरकार से गेहूँ और चीनी के और आवटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

सेन चीनी जांच ग्रायोग

- 5073. श्री नारायरा रेड्डी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
- (क) सेन चीनी जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;
- (ख) क्या सिफारिशों को पूर्ण ग्रथवा आंशिक रूप से स्वीकार तथा क्रियान्वित किया गया है: और
 - (ग) सभी सिफारिशों की स्वीकार न किये जाने के क्या कारए। हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिस क्रिन्दे): (क) और (ख): चीनी जांच आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न सम्बन्धित हितों के परामर्श से सावधानी विचार, स्वीकार तथा उन पर जहां व्यवहार्य समक्षा गया, कार्यवाही की गई जबकि अन्य की जांच और उन्हें घ्यान में रखा गया।

(ग) चीनी जांच आयोग की सिफारिशों से प्रतीत होता है कि चीनी उद्योग के बारे में कोई दीर्घ कालीन नीति तैयार करना किठन है क्योंकि गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में घट-बढ़ होने और गन्ने की फसल की स्थिति जोकि मुख्यतः मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है, के कारण प्रत्येक वर्ष परिस्थितियों में भारी अन्तर पड़ जाता है। कभी की अविध में इस घट-बढ़ से गुड़ और खंडसारी के मूल्य में वृद्धि और गन्ना चीनी बनाने की बजाए खंडसारी में लगाने से सम्बन्धित समस्याये पैदा होती हैं। अतः वर्ष विशेष के लिये नीति तैयार करते समय प्रत्येक वर्ष में चल रही परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है। यह विभिन्न हितों अर्थात् चीनी उद्योग, राज्य सरकारों आदि के परामशं से किया जा रहा है।

निजाम शुगर फैक्टरी, स्रांध्र प्रदेश

- 5074. श्रीनारायण रेड्डी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या निजाम भूगर फैंक्टरी लिमिटेड, शक्कर नगर बोधन, आंध्र प्रदेश, के बारे में 1959-60, 1960-61 तथा 1961-62 के वर्षों के लिये मूल्य लगाने के सूत्र के अन्तर्गत गःने के अतिरिक्त मूल्यों की धन राशि निर्धारित कर ली गई है।
 - (ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष में कितना अतिरिक्त मूल्य बताया है ;
- (ग) यदि अतिरिक्त मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है तो असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और
 - (घ) इस मूल्य की किस तारीख तक घोषणा कर दिये जाने की सम्भावना है ?
- खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) 1959-60 के लिए अतिरिक्त मूल्य घोषित कर दिया गया है। जहां तक 1960-61 और 1961-62 के वर्षों का सम्बन्ध है, मामला विचारधीन है।
- (ख) 1959-60 के सीजन का अतिरिक्त देय मूल्य 21.65 लाख रुपये था जिसमें से 9.27 लाख रुपये उनके अपने फार्म और 12.37 लाख उत्पादकों को दिये जाने थे। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार फैक्टरी ने उत्पादकों को 7.78 लाख रुपये का भूगतान कर दिया है।
- (ग) और (घ): 1960-61 और 1961-62 के वर्षों के आंकड़े एकत्रित कर लिए गए है और उन पर विचार हो रहा है। मूल्य का निर्धारण शीघ्र ही कर लिया जाएगा।

चीनी के मूल्य निर्धारित करने के लिए 'जोन'

- 5075. श्री नारायण रेड्डो: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) सरकार ने चीनों के मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु कितने 'जोन' बनाये हुए हैं ग्रीर प्रत्येक जोन में आने वाले चेत्रों तथा कारखानों का ब्योरा क्या है ;

- (ख) चीनी जांच आयोग द्वारा कितने 'जोन' बनाने की सिफारिश की गई है उसको स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ;
 - (ग) समय-समय पर विशेष 'जोन' अथवा 'जोन' के बनाने की कसौटी क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब किन्दे): (क) 1967-68 में सरकार द्वारा अधिगृहीत लेवी चीनो के निकासी मूल्य चीनी जांच आयोग द्वारा अभिस्तावित 5 जोनों के आधार पर निर्धारित किए गए थे। 1968-69 के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्य भी उसी आधार पर निर्धारित किए गए हैं। चीनी जांच आयोग द्वारा अभिस्तावित जोनों को और प्रत्येक जोन के अन्तर्गत आये क्षेत्रों और कारखानों को बताने वाला एक विवरण सलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी. 2783/68]

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

गन्ने की खेती की लागत

5076. श्री नारायण रेड्डी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार को देश के उद्या कटिबंधीय तथा उप-उद्या कटिबंधीय क्षेत्रों में गन्ने की खेती की प्रति एकड़ लागत के बारे में पता है; और यदि हां तो उनको यह जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई है;
- (ख) उनत क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों से गन्ने की खेती पर प्रति एकड़ कितनी लागत आई; और
- (ग) क्या सरकार ने इस लागत का पता लगाने के लिए कोई जांच अथवा सर्वेक्षण कराया है और यदि नहीं तो, इनके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रन्नासाहिब किन्दे): (क) से (ग): सन् 1955-63 के दौरान पुरानी भारतीय केन्द्रीय गन्ना सिमिति द्वारा अधिक गन्ना उत्पन्न करने वाले राज्यों में गन्ने के उत्पादन की कीमतों का अध्ययन किया गया था। अध्ययन की अविधियां तथा विभिन्न राज्यों में प्रति एकड़ अनुमानित उत्पादन व्यय दिखाने वाली तालिका निम्नलिखित है:—

राज्य उप-गर्म जलवायु वाले क्षेत्र	ग्रवधि	श्रनुमानित लागत रुपयों में प्रति एकड़
पंजाब (पुराना)	1955-58	372.87
उत्तर प्रदेश	1955-58	334.46
बिहार	1955-58	367.64

गरम जलवायु वाले क्षेत्र		
ग्रान्ध्र प्रदेश	1955-58	663.72
मैसूर	1960-63	1007.27
महाराष्ट्र	1956-59	1338.05

पिछले तीन वर्षों में विभिन्न कृषि निर्विष्टों के मूल्यों का विवरण इस बात का संकेत करता है कि इस अवधि के दौरान गन्ने के उत्पादन की लागत तत्कालीन स्तर से काफी बढ़ गई होती।

निरन्तर रूप से देश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के उत्पादन व्यय का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक व्यापक योजना बनाने का निश्चय किया हैं। इस योजना के अन्तर्गंत गन्ने के उत्पादन व्यय सम्बन्धी जानकारी भी प्राप्त की जाएगी।

सफाई के काम में जागीरदारी पद्धति का उन्मूलन

5077. श्री सिद्ध्या : क्या समाज कल्यामा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश के कुछ राज्यों में सफाई के काम में जागीरदारी पद्धति का उन्मूलन करने में कोई प्रगति हुई है,
 - (ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और
 - (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याए विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) से (ग) । जागीरदारी अथवा ज़ित-जनमानी व्यवस्था देश के कुछ उत्तरी राज्यों में विद्यमान है, परन्तु इसे कानून द्वारा रुढ़िगत अधिकार नहीं माना जाता है। यह समस्या स्थानीय प्रकार की है तथा सफाई के काम को नगर पालिकाओं के अधीन लिए जाने से इसका मुख्यतया हल किया जा सकता है। इसके लिए अतिरिक्त राशियों की आवश्यकता होगी और इसलिए यह चतुर्थ योजना में किए गए आंवटन पर आधारित होगा।

भ्रन-म्रिधसुचित भ्रादिम जातियों तथा मनुसचित भ्रादिम जातियों को रियायतें

5078. श्रो सिद्या: क्या समाज कल्या गांत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मैसूर तथा महाराष्ट्र राज्यों में अन-अधिसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को क्या विभिन्न रियायतें दी गई हैं; और
- (ख) क्या यह सच है कि उक्त राज्यों में ग्रन-अधिसूचित आदिम जातियों को विधान समा तथा लोक सभा में स्थानों के आरक्षण के अतिरिक्त अन्य सभी सुविधाएं दी गई हैं ?

समाज कल्यारा विभाग में राज्य मंत्री (डा॰ (श्रीमती) फूलरेरा गुह): (क) तथा (ख): मैसूर तथा महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों में अन-अधिसूचित श्रादिम जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्यारा के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा समाज

कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्टों में, जिन की प्रतियां प्रतिवर्ष सभा पटल पर रखी जाती हैं, दिया गया है। अनुसूचित आदिम जातियां उन विभिन्न सुरक्षणों की भी हकदार हैं, जिन की उनके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है, अर्थात विधान मंडलों में जगहों का आरक्षण तथा सेवाओं में पदों का आरक्षण, इत्यादि। अन-अधिसूचित आदिम जातियों के लिए विधान सभा तथा लोक सभा में जगहों का आरक्षण नहीं किया गया है।

कोयला खानों द्वारा ग्रादर्श स्थायी ग्रादेश ग्रपनाना

- 5079. श्री ईश्वर रेड्डी: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री कोयला खानों द्वारा आदर्श स्थायी आदेश अपनाने के बारे में 14 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4078 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या दोनों वर्गों की कोयला खानों के नामों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध हैं ; और
 - (ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख): सूचना एकत्र की जारही है। कृषि उद्योग निगम

5080. श्री एन शिवष्पा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कृषि-उद्योग निगमों के उद्देश्य तथा कार्य क्या हैं ;
- (ख) क्या यह सच है कि इन निगमों अथवा इनके द्वारा नियुक्त की गई एवेंसियों द्वारा अध्याभूति (गारंटी) की अवधि में नौ ट्रैक्टरों की निःशुलक मरम्मत आदि नहीं की जा रही है;
- (ग) यदि हां, तो इन निगमों द्वारा बेचे गये ट्रैक्टरों की ठीक प्रकार से मरम्मत आदि सुनिह्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;
- (घ) क्या सरकार ने फालतू पुर्जों के लिये कई लाख रुपये की कीमत के आयात लाइसेंस जारी किये हैं और यदि हां, तो क्या इन लाइसेंसों के आधार पर आर्डर दे दिये गये हैं; और
 - (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) कृषि-उद्योग निगमों के मुख्य उद्देश्य तथा कार्य कलाप संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार हैं:-

(1) उत्पादन, परिक्षण तथा खाद्य सम्मरण को प्रभावित करने वाले उद्योगों की उन्नति तथा कियान्विति करना :

- (2) कृषि तथा उससे सम्बन्धित धन्धों में व्यस्त व्यक्तियों को अपने क्रिया-कलागों के आधुनिकीकरण करने में सहयोग देना।
- (3) कृषि मशीनरी और औजारों तथा प्रक्रिया, डेगी, कुक्कुट, मात्स्यकी तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य उद्योगों के उपकरणों का वितरण ।
- (4) कृषि के लिए आदानों के कुशल वितरण में सहायता करना, और
- (5) कृष्कों तथा कृषि उद्योगों से सम्बन्धित व्यक्तियों को तकनीकी मार्ग दर्शन उप-लब्ध करना जिससे कि उनके इस उत्साह । एगं कार्य में कुशलता लाई जा सके।
- (ख) जी नहीं। कृषि उद्योग निग्मों तथा उनके नियुक्त एजेन्टों द्वारा बेचे गए ट्रैक्टरों की गारटी अवधि में निः शूल्क सर्विसिंग की जा रही है।
 - (ग) प्रश्न नहीं होता।
- (घ) और (ङ) विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों को तदर्थ अधार पर ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के आयात के लिए 104.29 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा नियुक्त की गई है जिससे कि वे किसानों को उचित मूल्य पर फालतू पुर्जें सप्लाई कर सकें। इसके मुकाबले में 42 लाख रुपये की राशि के आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं। सम्बन्धित कृषि उद्योग निग में द्वारा विदेशी सम्धरण कक्तीओं की लगभग 35 लाख रुपए तक के आर्डर पहले ही दे दिए गए हैं और शेष 7 लाख रुपये के सम्भरण की शर्तों के बारे में समभौता किया जा रहा है। 62 लाख रुपए तक के आयात लाइसेंस शीघ ही जारी हो जाने की सम्भावना हैं।

Unemployment in Jhansi Division of U. P.

- 5081. Shri Jageshwar Yalav: Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that there is a acute unemployment in Jhansi Division, particularly in hilly areas of Banda district in Uttar Pradesh, because of lack of employment opportunities in Jhansi, Jalaun, Hamirpur and Banda;
- (b) whether it is also a fact that large number of boys who have passed High School Intermediate and B. A. examinations in the Jhansi Division are facing acute problem of unemployment; and
- (c) if so, the steps proposed to be taken by Government to ease the employment position in Jhansi Division?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir): (a) Precise information is not available. However the number of employment seekers on the Live Register of the four Employment Exchanges as on 30th June, 1968 and the number of vacancies notified to these Employment Exchanges during the period July, '67 to June' 68 was as under:

Name of Exchange	No. on Live Register as on 30, 6, 1968	Vacancies notified during July, 67 to June, 68	
Banda	2,021	904	
Hamirpur	1,977	880	
Jhansi	8,203	3,057	
Jalaun	2,889	885	
Total:	15,090	5,786	

(b) The number of educated applicants (Matriculates and above) on the Live Register of Employment Exchanges as on 30th June, 68 in the Jhansi Division was as under:

Matriculates	3,684
Higher Secondary (including Intermediate under-graduates)	1,730
Graduates (including Post-graduates)	629
Total:	6,043

(c) Various development programmes proposed to be undertaken in the 4th Plan are designed to provide increasing number of employment opportunities for unemployed including the educated persons.

वर्ष 1968-69 में ग्रासाम में ग्रादिवासियों के कल्याए। कार्यों पर व्यय

5082. श्री कार्तिक उरांव : क्या समाज कल्याग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968-69 में आसाम के पहाड़ी तथा मैदानी सेत्रों में आदिवासी लोगों के कल्यागा कार्यों पर किये जाने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्यारण विभाग में राज्य मंत्री (डा॰ (श्रीमती) फूलरेशा गुह) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :-

मेसूर राज्य को उपहार के गेहूं का तथा खाद्य पदार्थी की सप्लाई

5083. श्रीक०लकप्पाः श्रीए०श्रीवरनः

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) मैसूर राज्य को 1967-68 में उपहार के रूप में दिए गए अमरीकी गेहूं तथा अन्य खाद्य वस्तुओं की मात्रा क्या है; और
 - (ख) मैसूर सरकार द्वारा इन वस्तुओं में से कितनी वस्तुओं को बांटा गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्तासाहिब किन्दे): (क) 1967-68 में भारत केयर करार, 1950 और भारत अमरीका करार, 1951 के अन्तर्गत आयात की गई गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थों की निम्नलिखित मात्रा मैसूर को सप्लाई की गई थी:

वस्तु	भारत केयर करार के ग्रधीन आयातित मात्रा (मी० टन•)	भारत अमेरीका करार के अधीन आयातित मात्रा (मी०टन०)	
सलाद तेल	1499.3	460.0	1959.3
गेहूँ (बुलगर गेहूँ सहित)	3597.3	5645.0	9242.3
सी०एस० एम० (कार्न-	7665.8	965.0	8630.8
सोय मिलक फूड मिश्रित)			
कार्न मील	910.4		910.4
दुग्ध चूर्ण	428.1	354.4	782.5
पी० बीन्स	-	130.0	130.0

(ख) भारत अमेरीका करार के अधीन आयात की गई उपहार वस्तुएं करार की शतों के अनुसार स्वीकृत सहायता एजेंसियों को वितरण के लिए सप्लाई की गई थीं जबकि भारत केयर करार के अधीन प्राप्त वस्तुएं राज्य सरकार द्वारा दोपहर के भोजन कार्यक्रम के अधीन वितरित की गई थीं। इससे फायदा उठाने वाले बच्चों की संख्या 897422 प्राथमिक स्कूल के बच्चे और 367483 स्कूल न जाने वाले बच्चे थी। उपर्यु क्त वस्तुओं के वितरण आदि में राज्य सरकार द्वारा कुल खर्च की गई राश्चि 39.6 लाख रुपये थी जिसका ब्योरा नीचे दिया जाता है:

			(लाख रुपये में)
(1)	सम्भालने / निकासी सहित परिवहन		21 00
(2)	केयर प्रशासन		9.6
(3)	स्थापन		9.0
		জা ৱ	39.6

बातु से बनाये गये गोदाम

5084. श्री कामेश्वर सिंह: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की करेंगे कि:

- (क) क्या किसानों में धातु से बनाये गये अनाज जमा रखने के गोदामों को लोकप्रिय क्याने के कार्यक्रम में मुंधेर जिले के खमरिया और बेगुसराय उप मंडलों को सम्मिलित किया गया है; और
- (ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारए हैं ; और इस सम्बन्ध में सुरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रीलय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब सिन्दे): (क) और (ख): फिलहाल घातुँ से बने गोदामी की लीकप्रिय बनाने की कार्यक्रम कोसी विकास परियोजना क्षेत्र तक ही सोमित है। इस क्षेत्र में बिनों की उपयुक्तता का पता लग जाने के बाद इस कार्यक्रम का विस्तार धीरे-धीरे बिहार के अन्य जिलों में भी किया जाएगा।

Use of Animal Blood as Manure

5085. Shri Jagannath Rao Joshi:

Shri Narain Swarup Sharma:

Shri Atal Bihari Vajpayee:

Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

- (a) the names of vegetables and fruits for which the blood of animals is used as manure:
- (b) whether it is proposed to ban the use of such manures for the fruit or vegetables, which are used for worshipping or taken on religious fasts; and
 - (c) whether the blood of cow is prohibited for such use?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) There are no specific fruits or vegetables for which animal blood is used as a manure but where it is available it may be used as manure for orchards.

- (b) No.
- (c) No.

Effect of Increase of Postal Charges on Small Newspapers.

5086. Shri Atal Bihari Vajpayee:

Shri Narain Swarup Sharma:

Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) the effect of the increase in postal charges on the financial position and circulation of small Newspapers; and
 - (b) whether Government propose to provide some relief to the small Newspapers?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Government have no specific information.

(b) The rates policy in respect of newspapers is under review.

उड़ीसा को पिंम्पग सैटों की सप्लाई

- 5087. श्री चिन्तामिए पाशिग्रही: क्या स्नाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या वर्ष 1966-67, 1967-68 ग्रीर 1968-69 में उड़ीसा में सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये पीम्पग सैटों की सप्लाई के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुग्रा है ; और
 - (ख) यदि हो, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मखली पालन संसाधनों का विकास

5088. श्री ए० श्रीधरन : क्या खाद्य तथा कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि मंगठन के एक क्षेत्रीय निकाय, हिन्द महासागर मछली आयोग के रोम में हाल ही में हुए अधिवेशन में मछली पालन संसाधनों के विकास के लिये एक तीन-सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया था ;
 - (ख) यदि हां, तो इस कार्येक्रम का ब्यौरा क्या है ;
- (ग) इस कार्यक्रम में मारतीय योगदान कितना है, और इस कार्यक्रम में सम्मिलित की जाने वाली भारतीय तटों पर मछत्री पालने की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और
- (घ) इस कार्यंक्रम के फलस्वरूप भारत में मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संमावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां। तीन-सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित मदों से सम्बन्धित है :--

- 1) मात्स्यकी सांख्यिकी का सुधार
- 2) बुरी तरह शोषित भंडारों का प्रबन्ध और
- 3) हिन्द महासागर के सर्वेक्षण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कार्येकम।
- (ख) कार्यक्रम का ब्योरा निम्नलिखित रूपसे निश्चित किया जायेगा :--
- सांख्यिकी एकत्रित करने की वर्तमान राष्ट्रीय प्रिशालियों का और विशेषज्ञ दल द्वारा उन के मानकीकरण सम्बन्धी कार्यों पर की गई सिफारिशों का प्रघ्ययन।
- 2) विशेषज्ञों के दलों द्वारा हिन्द महासागर की खाड़ी में ट्यूना और श्रीम्प मच्छिलियों के मडारों के शोषण की वर्तमान स्थित का अध्ययन।
- 3) विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण और विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिये अध्ययन । इस कार्य के लिये संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम से सहायता मिलने की आशा है।
- (ग) और (घ): भारत के इस विकास की यंक्रम में भेग लेने की सीमा को तथा पछली-उत्पादन में होने वाली वृद्धि की मात्रा को केवल प्राथमिक अध्ययन पूरा होने के बाद है। निश्चित किया जा सकता है।

मछली उद्योग का विकास

5089. श्री ए० श्रीधरन :

श्री भ्रोंकार लाल बैरवा:

श्री क० प्र० सिंह देव:

श्री यशपाल सिंह :

नया खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत में मुछली उद्योग के विकास कार्य में सहायता करने के लिये हाल ही में भारत और नार्वे के बीच एक ऋगा सम्बन्धी करार को अन्तिम रूप दिया गया है ;
 - (ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं;
- (ग) तथा इस करार के अन्तर्गत गहरे समुद्ध में से मछली पकड़ने की योजना बनाई जायेगी; जिन में कुछ परियोजनाए बेरल की सम्मिलित होंगी; और
- (घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन योजनाशों को कब तक कियान्वित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां।

- (ख) करार की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल. टी. 2784/68]
 - (ग) जी नहीं।
 - (घ) प्रश्त ही नहीं होता।

होशियारपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन का स्थान

5090. श्री श्रीचन्द गोयल: क्या विधि मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं 5080 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि होशियारपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन क्यों स्थगित कर दिया गया ?

विधि मंत्रालय में उपमत्री (श्री मु॰ यूनुस सलीम): पंजाब राज्य के बारे में 23 अगस्त, 1968 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के परिणामस्वरूप परिवर्तित परिस्थितियों में, निर्वाचन आयोग ने यह प्रनुभव किया कि प्रक्तूबर, 1968 में होशियारपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उपनिर्वाचन करने से, जैसा कि पहले अनुमोदित किया गया था, विवाचक नामाविलयों के पुनरीक्षण और राज्य में मध्याविध साधारण निर्वाचन के संचालन के लिए अन्य इन्तजामों में बाधा पड़ेगी। निर्वाचन ग्रायोग ने तदनुसार होशियारपुर निर्वाचन-चेत्र में उप-निर्वाचन को स्थिगित करने और उसे पंजाब राज्य में मध्याविध साधारण निर्वाचन के साथ-साथ कराने का विनिश्चय किया।

Direct Dialling System

5091. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that direct dialling system has been introduced between Delhi and Jaipur and also between Jaipur and Ajmer; and
- (b) if so, the reasons for not introducing that system between Jaipur and Kotah and also between Ajmer and Kota?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Direct dialling has been introduced between Delhi and Jaipur, while it has not been introduced between Jaipur and Ajmer.

(b) Aimer and Kota telephone system are at present manual exchanges. Direct dialling facilities can be introduced only between automatic exchanges and therefor it is not possible to provide this facility between Jaipur and Ajmer, Jaipur and Kota and Ajmer and Kota.

चुनाव कार्य के लिये सामुदायिक विकास खण्डों से जीपें वापस लेना

- 5092. श्री रा० की० ग्रमीन: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि चुनावों की तीन सप्ताहों की अविध के दौरान सामुदायिक विकास खण्डों से जीपें वापस ले ली गई हैं;
- (ख) यदि हां, तो क्या चुनावों से तीन सप्ताह की अविधि में उन जीयों का प्रयोग जूनावों के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था;
- (ग) क्या सरकार चुनावों से कम से कम तीन महीने पहले इन जीपों को वापिस लेने का विचार करेगी; और
 - (घ) उप-चुनावों तथा मध्याविध चुनावों में सरकार की नीति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० एस० गुरुवदस्वामी): (क) राज्य सरकारों को यह सुफाव दिया गया है कि चुनाव प्रविध में जीपें नामांकन की तारीख से लेकर मतदान की तारीख तक खण्डों से वापिस ले लेनी चाहिए और जिला समाहर्नाओं के नियत्रण में उनके द्वारा केवल चुनाव कार्य हेतु प्रयोग में लाने के लिए रखी जानी चाहिए।

- (स) और (ग): चुनाव अवधि में उगरोक्तानुमार जीपें वापिस लेने से पहले उनका उप-योग खण्डों के सामान्य विकास कार्य के लिए किया जाना है, उन्हें पहले वापिस लेने का प्रस्ताव नहीं है।
- (घ) राज्य सरकारों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनावों के दौरान खण्डों, से जीपों वापिस लेने का यह प्रबन्ध उप-चुनावों तथा मध्याविध चुनावों के दौरान भी उतनी ही अविध के लिए लागू होता है।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड

5093. श्री प्रेम चन्द वर्माः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड कम्पनी किस वर्ष स्थापित की गई थी उस समय इसके निदेशक मण्डल के सदस्य कौन-कौन थे तथा वही निदेशक मण्डल कितनी देर चलता रहा; और
- (ख) इसके वर्तमान निदेशक मण्डल के सदस्यों, अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के नाम क्या है तथा उनकी नियुक्ति किन-किन तरीखों को की गई थी और उनका कार्य-काल कितना है तथा उनकी नियुक्ति की शर्ते क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) तथा (ख)। श्रपेक्षित सूचना प्रदान करने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संस्था एल०टी० १७85/68]

हिन्दस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड

5094. श्री प्रेम चन्द वर्मा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) (एक) अनियमितताओं (दो) चोरी (तीन) माल की कमी हो जाने (चार) आग लगने अथवा ऐसे ही अन्य कारणों से हिन्दुस्तान टेलाप्रिन्टर्स लिमिटेड को इसकी स्थापना से लेकर अब तक कितनी धनराशि की हानि हुई;
- (ख) क्या इन मामलों की जांच कराई गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और
 - (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसद-कार्य तथा सचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) हिन्दु-स्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड का चोरी के कारण हुई हानि लगमग 2,610 क्ये हैं। कम्पनी को अनियमितताओं, स्टाक की कभी और आग लगने की घटनाओं, आदि के कारण कोई हानि नहीं हुई है।

- (ख) जी हां। कम्पनी के प्रबन्धक-वर्ग ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उचित अनुशास-नात्मक कः पंवाही की है और सुरक्षा के उपायों को भी, जहां कहीं आवश्यक समका गया और अधिक कड़ा कर दिया है।
 - (ग) उपयुक्त भाग (ख) के उत्तर को हब्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टसं लिमिटेड

5095. श्री प्रेम चन्द वर्मा: क्या संचार मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि:

- (क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टसं लिमिटेड के ऋष ठेकों तथा विऋष से सम्बन्धित कर्म-चारियों की भर्ती (500 रुपयों से अधिक मासिक वेतन वाले पदों के लिये) के नियम बना रखे हैं; और
 - (ख) यदि हां, तो उन नियमों का ब्योरा क्या है ?

ससद-कार्य तथा सचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख): हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड द्वारा, 500/- रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन वाले पदों के भनी के नियम बना लिये गये हैं तथा उन्हें ग्रन्तिम रूप दिया जा रहा है। खरीद के ठेकों तथा बिकी के विषय में कम्पनी द्वारा स्पष्ट नियम तथा शर्ते तय कर दी गई हैं। इन सभी को सामान्य वािराज्यिक पैराये पर तैयार किया गया है।

केन्द्रीय मत्स्य उद्योग निगम लिमिटेड

5096. श्री प्रेम चन्द वर्मा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे

- (क) केन्द्रीय मत्स्य उद्योग निगम लिमिटड की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना करने के उद्देश्य क्या थे;
- (ख) क्या कारखानों की स्थापना श्रीर उनके उत्पादन और विकास के लक्ष्य परियोजनाओं के प्रतिवेदनों के अनुसार प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो कब और कैंसे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या इस निगम की स्थानना में कोई विदेशी सहयोग शामित था और यदि हां, तो सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या थे, सहयोग की शर्ते क्या थीं जथा सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;
- (घ) कम्पनी इस समय किस चीज का और कितना उत्पादन कर रही है और क्या वे उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं;
- (ङ) गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा कितना उत्पादन किया गया, कितनी बिक्री हुई तथा इस उत्पादन में से कितने उत्पादन का निर्यात किया गया; और
- (च) क्या कम्पनी को इस समय किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो सरकार का विचार कठिनाइयों को किय प्रकार दूर करने का है ?
- खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिन्दे):
 (क) केन्द्रीय मार्त्स्य की निगम लिमि॰ की स्थापना 29 मितम्बर, 1965 में की थी।
 इसका मुख्य ध्येय था कि यह मछलियों को अधिप्राप्त कर उनके संरक्षण परिवहन ग्रीर भड़ांरण तथा भारत उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने की सुनिश्चितता तथा मारत के किमी भी
 भाग में विशेषकर कलकत्ता में उपभोक्ताओं को मछली उचित मूल्यों पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराना।
- (ख) एक कों की स्थापना की कोई सूचना नहीं थी। कार्य के दौरान विकास के लिए पानी के अनेक क्षेत्रों में कार्य आरम्भ करने का निश्चय किया गया था। विकास के फलस्वरूप उत्पादन के लक्ष्यों में होने वाली वृद्धि विवरण में सकेतित है। [पुर कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2786/68]

गुजरात का मयूराक्षी जलाशय, 1967 में और उत्तर प्रदेश की मिवारी भील 1968-69 में ही अधिग्रह्म की गई हैं। सन् 1967-68 के दौरान क्षमोदर घाटी निगम के जलाशयों से वास्ताविक उत्पादन 59000 किलोग्राम के अनुमानित उत्पादन के विपरीत 53000 किलोग्राम था।

- (ग) निगम में किसी प्रकार का विदेशी सहयोग नहीं है।
- (घ) अब निगम का कार्य केवल मछली के अधिप्राप्त करने तथा विक्रय तक ही सं।िमत है किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं की जाती। निगम ग्राजकल किसी भी प्रकार के मछली-उत्पाद का उत्पादन नहीं करता।
- (ङ) विभिन्न साधनों द्वारा अधिप्राप्त मछली की मात्राएं भिन्न-भिन्न साधनों के द्वारा कलकत्ता सहित, विभिन्न केन्द्रों पर बेची गई मछली की मात्राएं निम्न प्रकार है :--

वर्ष

मात्रा

1965-66 (3-12-1965 निगम के कार्य करना आरम्भ करने की तिथि से)

4,31,000 किलोग्राम

1966 67

14,41,000 ,,

1967-68

11,08,000 ,,

निगम ने मछली का नियति नहीं किया।

(च) निगम अभी निर्माण्डिमक अवस्था में है। इसे मछली अधिप्राप्त करने में भली प्रकार स्थापित तथा प्राप्ति और संभरण के परम्परागत केन्द्रों से संबन्धित गैर-सरकारी प्रति-योगितों व्यापारियों से मुकाबला करना पड़ता है। आजकल मछली की काफी मात्रा व्यापारियों से प्रतियोगिता में ही अधिप्राप्त की जाती है। प्रतियोगिता बाजार पर निभेरता कम करने के लिए निगम ने पहले ही निरन्तर संभरण के साधन बनाने के लिए पानी के क्षेत्रों के अधिग्रहण एवं विकास की नीति अपना ली है। विभिन्न राज्यों में कुछ जलाशयों का अधिग्रहण कर लिया गया है और उन पर विकास कार्य जारी है।

सहकारी समितियों का विकास

- 5097. श्री भोगेन्द्र काः क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
- (क) देश में कितने प्रकार की सहकारी सिमतियां कार्य कर रही हैं तथा उन सदस्यों की संख्या सहित उनकी राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;
- (ख) विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों में ऋगों, अनुदानों इत्यादि के खर्च में कूल कितनी सरकारी पूंजी लगी हुई है;
- (ग) क्या कुछ विशिष्ट प्रकार की सहकारी समितियों के विकास की बढ़ावा देने की सरकार की नीति है; और
 - (घ) यवि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ एस॰ गुरुपदस्वामी: (क) सहकारी सिमितियों को मौटे तौर पर साख सिमितियों तथा साखेतर सिमितियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहले वाली सिमितियों में राज्य। केन्द्रीय बैंक प्राथमिक कृषि साख तथा कृष्येतर साख सिमितियों, केन्द्रीय। प्राथमिक भूमि विकास बैंक, आदि शामिल हैं। बाद वाली सिमितियों में मुख्य रूप से विपएगन, विशायन, खेती, श्रमिक निर्माण, डेरी, श्रीद्योगिक, गृह निर्माण सहकारी सिमितियां आदि शामिल हैं। इनकी संख्या तथा सदस्यता के बारे में इनकी उपलब्ध आधुनिकतम राज्यवार स्थिति विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 2787/68]

- (ख) अब तक सरकार ने सहकारी सिमितियों में कच्चे तौर पर 110.94 करोड़ रुपए ऋगा के रूप में 88.30 करोड़ रुपए अंश पूंजी अंशदान के रूप में और 32.36 करोड़ रुपए अनुदानों तथा उपदानों के रूप में लगाए हैं।
- (ग) ग्रौर (घ)ः सरकार आर्थिक जीवन की बहुत सी शाखाओं, विशेष रूप से कृषि, लघु उद्योग, कृषि उपज के विप्णान तथा विधायन, उत्पादन आदानों तथा अत्यावश्यक उपभोज्य वस्तुओं के वितरण तथा सम्भरण के क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विकास को प्रोत्साहित करती रही है।

Wheat Supply to flour Mills

- 5098. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) the quantity of wheat supplied to the flour mills so far during the current financial year as also the terms on which supplied and the quantity of indigenous and imported wheat separately likely to be supplied to them by the end of the year; and
- (b) the number of mills working along with their capacities and the number of mills which are lying closed along with their capacities?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The total quantity of wheat supplied to the flour mills during the period April to October, 1968 was about 11.65 lakh tonnes. 3.74 lakh tonnes were allotted for November and December, 1968. It is not possible at this stage to indicate the quantity that will be supplied to the roller flour mills during the period January to March, 1969. A copy of the terms and conditions on which wheat is supplied to the roller flour mills is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. L. T. 2788/68] No separate account is kept of indigenous or imported, wheat Supplied to any recipient as all wheat, after reaching the Central depots, lose their identity except for quality, i e. whether it is red wheat or white wheat or superior wheat.

(b) 182 roller flour mills with a total monthly capacity of about 3.4 lakh tonnes are working and 9 roller flour mills with a total monthly capacity of 7709 tonnes are lying closed at present.

Construction of Warehouses

5099. Shri Maharaj Singh Bharati; Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) the time by which the programme formulated out by Government for the construction of warehouses for foodgrains in the producing areas would be completed and the progress made so far in this respect; and
- (b) the quantity of foodgrains likely to arrive in mandis in each Sta e after the end of the Fourth Five Year Plan and the storage capacity of warehouses proposed to be built in the said States?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Government have approved a total construction of 9.65 lakh tonnes capacity godowns, most of which are in the producing areas. These are expected to be completed during 1969-70. Godowns of 25,000 tonnes capacity have already been completed.

(b) As the Fourth Five Year Plan has not yet been finalized, it is not possible, at this stage, to estimate either the quantity of foodgrains likely to arrive in mandis after this period or the storage capacity for which funds will be provided in the plan.

Modern Bakery Madras

- 5100. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that the bread produced in the Modern Bakery in Madras, which has been set up with Australian assistance, is not selling and that production in the factory is much less than its capacity because of different food habits of the people there; and
 - (b) if so, the measures being adopted by Government in that connection?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The bread produced by the Government Company is selling in Madras City but the volume is not very large. Therefore, the production has not yet reached capacity level

(b) The Company has undertaken intensive publicity on the nutritional value of the Modern Bread and the sale has also been extended to cover larger areas.

देलीफोन के बारे में शिकायने

- 5101. श्री जाजं फरनेन्डीज: क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या उन्हें श्री सी॰ बी॰ एल॰ मटनागर, 23 वैली बिल्डिंग, सर पी॰ ए॰ रोड, बम्बई से टेलीफोन नम्बर 254626 के बारे में तारीख 7 सितम्बर, 1968 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;
- (ख) क्या उन्होंने अभ्यावेदन में लगाये गये गम्भीर आरोपों की कोई जांच की है; और
- (ग) बम्बई टेलीफोन कार्यालय के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

संसव-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

- (ख) बम्बई टेलीफोन परिमंडल ने इस शिकायत की जांच की थी। 24 अक्तूबर, 1968 को टेलीफोन प्रयोक्ता को जांच के परिणामों से अवगत कराया गया था। बिलों की रकम की शीघ्र अदायगी के लिए उनसे सहयोग करने के लिए कहा गया था ताकि टेलीफोनों का कनेक्शन न काटा जाए। इसके बाद 28 अक्तूबर, 1968 को प्रयोक्ता से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। पार्टी ने जाब्ता दीवानी की घारा 80 के अन्तर्गत 23 नवम्बर, 1968 को महाप्रबन्धक, टेलीफोन, बम्बई टेलिकोन परिमण्डल, बम्बई को एक नोटिस भी भेजा है।
- (ग) श्रभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जिससे किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवार्ड की जा सके।

मुख्य डाक घर बम्बई में चौकीदारों के लिये ड्यूटी के लम्बे घंटे

- 5102. श्री जार्ज फरनेन्डीज: क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि बम्बई मुख्य डाक घर कार्यालय के चौकीदारों को लगातार 12 घंटे तक की ड्यूटी देनी पड़ती है;
- (ख) यदि हां, तो क्या यह मजदूरों के कार्य घंटों के विनियमन कानून के विरुद्ध नहीं है;
 - (ग) क्या मजदूरों ने इस मामले में कोई अभ्यावेदन दिये हैं ; और
- (घ) यदि हां, तो प्रति दिन के काम के घंटों को घटा कर आठ घंटे करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हां, प्रतिदिन 12 घंटे की ड्यूटी निर्धारित है; हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि यह लगातार हो।

(ख) से (घ) : जी हां, इस सम्बन्ध में एक श्रम्यावेदन प्राप्त हुआ था और चौकीदारों के दैनिक कार्य-समय को 12 घंटे से कम करके 8 घंटे करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Unemployed Engineers and Diploma Holders

- 5103. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:
- (a) the number of unemployed engineers and diploma holders in the country at present on the basis of the information available with Government; and
- (b) the number of unemployed engineers given employment by Government through the employment exchanges during the last four months?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir): (a) Precise information is not available. However, the number of engineering graduates and diploma holders on the Live Register of Employment Exchanges as on 30-6-1968 was 7,848 and 29,871 respectively.

(b) The number of engineers placed in employment during January to June, 1968 was 1,529.

Withdrawal of Recognition of P & T Employees Unions

- 5104. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Communications be pleased to state:
- (a) the names of the Unions of Posts and Telegraphs Employees whose recognition has been withdrawn by Government as a result of their participation in the recent strike; and
- (b) the respective dates when recognition was accorded to them and the number of the members of each one of them at present?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communication (Shri I. K. Gujral): (a) The recognition of the following Unions has been withdrawn on 21-9-68 consequent upon their sponsoring and participation in the illegal strike on 19-9-68.

- 1. National Federation of P & T Employees.
- 2. All India Postal Employees Union (Class III)
- 3. All India Postal Employees Union (Postmen & Class IV)
- 4. All India RMS Employees Union (Class III)
- 5. All India RMS Employees Union (Mailguards & Class IV)
- 6. All India Telegraph Engineering Employees Union (Class III)
- 7. All India Telegraphs Engineering Employees Union (Linestaf and Class IV)
- 8. All India Telegraph Traffic Employees Union (Class III)
- 9. All India Telegraph Traffic Employees Union (Class IV)
- 10. All India (P&T) Administrative Offices Employees Association (Class III & IV).
- (b) These Unions had originally been recognised in 1954, when the realignment Scheme for the Unions of non-gazetted staff in the P&T Department was introduced. Their recognition was withdrawn in July, 1960 for organising an illegal strike but it was restored on 23-9-1961.

Information is not available regarding the correct membership of these Unions either before or at present.

Production of Pure Ghee

- 5105. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6374 on the 29th August, 1968 and state:
- (a) whether information in regard to production of pure ghee in 1967 has since been collected; and
 - (b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasah b Shinde): (a) and (b): Certain data has been collected but

needs further clarification before fulfilling the Assurance given in reply to Unstarred Question No. 6374 on 29th August, 1968.

Milk Procurement By D. M. S.

- 5106. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) the quantity of standard milk brought in to Delhi from outside places during August and September, 1968;
- (b) whether it is a fact that milk collected for Delhi from ourside places during the corresponding months last year was much more than the quantity this year; and
- (c) if so, the reasons for the less collection by the DMS of milk during these months?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Standard milk is prepared in the DMS and not brought from outside. The quantity of raw milk procured in August 1968 was 44,03,757 litres and in September, 1968 was 40,99,319 litres.

- (b) Yes, Sir. 46,45, '35 litres of milk was procured in August, 1967 and 47,89,202 litres during September, 1967.
 - (c) (i) Diversion of milk for khoa manufacture and other milk products during August, 1968, after the expiry of the Delhi Meerut and Bulandshahr Milk and Milk Products Control Order, 196.
 - (ii) Festivals like Dussehra and Navratri which fell during September, this year where as these festivals had fallen in October, last year.
 - (iii) Fall in production in dry areas of Haryana and Bikaner in Rajasthan.

Emoluments of Panchayat Secretaries in U. P.

- 5107. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether Government are aware that the Secretaries of Panchayats in Uttar Pradesh get only Rs. 50 p. m. as remuneration without any allowances such as dearness allowance, conveyance allowance, travelling allowance etc;
 - (b) if so, the reasons therefor; and
- (c) the steps being taken by Government to fix adequate pay and allowances of Panchayat Secretaries?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri M S. Gurupadaswamy): (a) Panchayat Secretaries in Uttar Pradesh are employed in the scale of Rs. 50-2-60-EB-3-75. They are paid dearness allowance and travelling allowance at the monthly rate of Rs. 12.50 and Rs. 5.00 respectively. Besides, an allowance of Rs. 2/-per month is also payable to every Panchayat Secretary by each Gaon Sabha in his circle.

- (b) The question does not arise.
- (c) On account of constraint of resources the State Government cannot at present provide funds for higher pay scales and allowances to Panchayat Secretaries. The Gaon

Panchayats are also not now in a position to shoulder any extra financial burden. The State Government are, however, exploring ways and means of augmenting the resources if possible.

Scheduled Castes and Scheduled Tribe Students in Engineering and Medical Colleges

- 5108. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of Social Welfare be pleased to state:
- (a) the total number of Scheduled Castes and Schedul 1 Tribes studying in Medical and Engineering Colleges in the country at present;
- (b) whether the number of these children in these colleges conforms to the ratio fixed by Government in this regard; and
 - (c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) to (c): The details are being collected from the State Governments/Union Territory Administrations and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Introduction of Automation in Sorting of Mail

5109. Shri Raghuvir Singh Shastri:

Shri D. C. Sharma:

Shri Beni Shanker Sharma:

Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) whether the Government propose to introduce automation in sorting of mail;
- (b) if so, the cost involved thereon and the foreign exchange element therein;
- (c) the number of employees likely to be rendered surplus thereby; and
- (d) the steps being taken to provide alternative employment to them ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) This is under examination.

(b) to (d): Do not arise.

जिला बुलन्द शहर में भूमि की बेचा जाना

- 5110. श्री राम चरण भन्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि ग्राम मामुरा परगना दादरी, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के प्रधान ने मई, 1965 में कुछ व्यक्तियों को 81 वीघा भूमि 10 रुपये प्रति बीघे की मामूली दर पर सब डिवीजनल मजिस्ट्रेंट की अनुमित से बेची थी;
- (ख) बया यह भी सच है कि उनमें से दो श्रलाटियों से उक्त भूमि को सब-डिवीजनल मिजिस्ट्रेट की अनुमित से मार्च, 1966 में किसी अन्य व्यक्ति को ईंटों के मट्टे बनाने के लिये 200 रुपये प्रति बीघे की दर से बेचा था;
- (ग) क्या यह भी सच हैं कि प्रधान ने जनवरी-फरवरी, 1967 में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अनुमति से कुछ और व्यक्तियों को 90 बीघा भूमि पुरानी दरों पर फिर बेची ;

- (घ) क्या यह भी सन है कि प्रधान ने उक्त भूमि को उन व्यक्तियों को अलाट किया था जिने नाम में या जिनके पिता के नाम में भूमि थी और भूमिहीन कृषि श्रमिकों, हरिजनों अगदि को भूमि अलाट नहीं की गई थी; और
- (ड) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रधान के विरुद्ध तथा पट्टे के रद्द करने और इस भूमि को भूमिहीन कृषि श्रमिकों और हरिजनों को अलाट करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्ना-साहिब शिन्दे): (क) जिला सिकन्दराबाद की दादरी तहसील के मधुरा परगना गांव की गांव सभा की भूमि-प्रबन्ध-समिति ने 6 अलग-अलग पट्टों के द्वारा 6 व्यक्तियों को 10 रुपये प्रति पट्टों के हिसाब से 30 बीघा 4 बिस्वे पक्की भूमि पट्टों पर दी थी। इसके लिए उपमंडल अधिकारी की स्वीकृति न तो ग्रावश्यक ही थी और न ही प्राप्त की गई थी।

- (ख) ऊपर कही गई भूमि में से, 3 पट्टों में 3 विभिन्न व्यक्तियों को (लगभग) 600 रूपये प्रति पक्का बीघा की दर से 13 बीघे 4 बिस्वे भूमि हस्तान्तरित कर दी थी, जिसके लिए उपमण्डल अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। जिस प्रयोग के लिए भूमि बेची गयी थी उसका सेल डीड में कोई विशेष वर्णन नहीं था।
- (ग) भूमि प्रबन्ध समिति ने 29 बीघे, 19 बिस्वे, 3 बिस्वासी भूमि अन्य चार व्यक्तियों को भूमि पर लागू होने वाली पुश्तैनी दरों से दस गुनी दरों पर पट्टे पर दी। इन मामलों में उपमंडल मजिस्ट्रेट की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी परन्तु राजस्व न्यायालय के इप में नामान्तरण आदेश उनके द्वारा ही किये गये थे।
- (घ) यह सच है कि भूमि प्रबन्ध सिमिति द्वारा पट्टे पर दी गई ऊपर वाली भूमि जिन टयक्तियों को दी गई थी उनमें से अधिकतर व्यक्तियों के पास जमीनें उनके अपने नाम या उनके पिता के नाम में हैं। उपर्युक्त भूमि में से कोई भी भूमि भूमिहीन श्रमिकों या हरिजनों को पट्टे पर नहीं दी गई है।
- (ङ) जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों की घाराओं के विरुद्ध पट्टे पर दी गयी जनीन के पट्टों को रह करने के लिए उपमंडल अधिकारी ने स्वयं ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है। यह कार्यवाही अभी अपूर्ण है। भूमि प्रबन्ध सिनित के प्रधान के विरुद्ध अपनी शक्ति के अनुचित प्रयोग के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा रही है तथा उन्हें आरोप पत्र भी दे दिया गया है। रह करने की कार्यवाही कानूनी होतो है श्रौर इन पट्टेदारों से कानूनी साधनों से खाली कराने पर ही भूमि उपलब्ध हो सकेगी। इसके बाद भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा जमीदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के उपबन्धों की धारा 198(2) तथा उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार नियम–1952 के नियम 174 (ए) के अनुसार फिर से भूमि नये पट्टे पर दी जाएगी।

P & T Consultative Committees in States

5111. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Government have formed posts and telegraphs Consultative Committees in all States;
 - (b) whether such a Committee has been formed in Bihar Circle also;
- (c) if so, whether Government have prescribed the frequency of the meetings of the said Committees:
- (d) whether it is also a fact that on meeting of the Posts and Telegraphs Consultative Committee of Bihar Circle has been held after the 9th February, 1968 and that a member of the Committee has complained to him in writing in this regard; and
 - (e) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I, K. Gujral): (a) Regional Posts and Telegraphs Advisory Committees, and not Consultative Committees, have been set up in all the Posts and Telegraphs Circles, not in all the States.

- (b) and (c): Yes,
- (d) and (e): A meeting of the Regional P & T Advisory Committee of Bihar Circle was held on the 6th December, 1968. In this connection a complaint was received from a Member of Parliament and he has been apprised of the position.

Difficulties in Getting Telephone Connections

- 5112. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of Communications be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that the difficulties faced by common people in getting telephone connections have increased as a result of reserving fifty per cent telephones under 'own Your Telephone' scheme out of the quota allotted by Government for installation of telephones in various big cities;
- (b) if so, whether the Telephone Consultative Committee of Patna has in one of its meetings unamimously adopted a resolution requesting Government to change the aforesaid rule and provide facilities to the common people;
- (c) whether it is also a fact that Government have brought about a change in the said rule; and
- (d) if so, the details thereof and the time by which Government propose to enforce it?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) 'Own Your Telephone' scheme initially introduced in 1949 was further extended to all stations having an equipped capacity of one thousand line and above with effect from 1-1-1968 and 50% connections were reserved for being provided under the OYT scheme at all new stations. This has resulted in a reduction of the quota reserved for 'General' category.

- (b) No.
- (c) and (d): The position was reviewed in July, 1968 taking into account the response to the scheme at the new stations and the representations and suggestions received from various quarters including some of the Telephone Advisory Committees. It was decided that if at any station the OYT waiting list is current and it is likely to remain current fo a period of three months, the Heads of Circles, on their own authority, can

release the capacity to non-OYT applicants. The revised instructions have come in to force with effect from 5-9-1968.

पश्चिम बंगाल में भ्रनाज का उत्पादन तथा समाहार

- 5113. श्री जयोतिर्मय बसु: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) 1967-68 में पिश्चम बंगाल में खाद्यान उत्पादन का पुनरीक्षित अनुमान क्या था और कुल उत्पादन में चावल का अंश कितने मीट्रिक टन था ;
- (ख) 1968-69 के लिये पश्चिम बंगाल में खाद्यान (रबी और खरीफ दोनों फसलों में) का अनुमानित उत्पादन कितना है और कुल उत्पादन में चावल का अंश कितनी मीट्रिक टन होगा;
- (ग) वर्ष 1968-69 और 1969-70 में देश में कितने मीट्रिक टन चावल खरीदा जायेगा;
- (घ) क्या सरकार ने मारत के खाद्य निगम के द्वारा पश्चिम बंगाल में बड़े उत्पादकों के समूचे फालतू स्टाक को खरीदने की कोई योजना बनाई है;
 - (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; भ्रीर
- (च) 1969-70 के लिये सरकार की पश्चिम बंगाल में खाद्यान की खरीद के बारे में क्या नीति है ?
- खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्ना साहिब शिदे)। (क) अद्यतन अनुमान इस प्रकार हैं:—

अनाज ••••• • 53.75 लाख मीटरी टन चावल ••• • 52.08 लाख मीटरी टन

- (ख) अभी इस प्रकार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता हैं।
- (ग) खरीफ मौसम 1968-69 में चावल की अधिप्राप्ति अभी शुरु हुई हैं श्रौर 30-11-68 तक चावल के हिसाब से धान सहित लगभग 33,800 मीटरी टन चावल अधिप्राप्त किया गया है। फसल वर्ष 1969-70 के लिए कोई आंकड़े बताना अभी सम्भव नहीं है।
- (घ) और (ङ): फसल मौतम 1968-69 के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नई ध्रिधप्राप्ति नीति के अन्तर्गत उत्पादकों पर क्रिमिक लेवी (ग्रेडेड लेवी) है और लेवी की राशि में वृद्धि जोत के आकार में वृद्धि के साथ-साथ होती जाती है।
- (च) फसल वर्ष 1969-70 के लिए अधिप्राप्ति विषयक नीति 1969 के अन्त में बनाई जाएगी।

मेहसाना (गुजरात) की दूध सागर डेरी द्वारा दिल्ली को दूध की सप्लाई

5114. श्री रा० कृ० ग्रमीन: श्री म० ला० मोंधी:

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में मेहसाना की दूध सागर डेरी का इरादा दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई करने का है; और
 - (ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और
- (ग) इससे उन व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिये किस सीमा तक सहायता मिलेगी जिन्होंने दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के टोकन लेने के लिये ग्रावेदन पत्र दिये हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्ना-साहिब शिन्दे): (क) जी हां।

- (ख) मेहसाना दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने दिल्ली दुग्ध योजना को इस समय प्रति दिन 30,000 लिटर और आगामी कुछ समय में प्रतिदिन 80,000 से 1,00,000 लिटर पूर्ण-दुग्ध सम्मरण करने का प्रस्ताव रखा है। विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।
- (ग) इससे प्रतीक्षा-सूची को निपटाने में अवश्य ही सहायता मिलेगी, परन्तु केवल प्रबन्ध पूरे हो जाने के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट होगी।

Panchayat Raj Schemes in Chhota Nagpur

- 5115. Shri Bhola Nath Master: Will the Minister of Food and Agriculture be plea sed to state:
- (a) whether it is a fact that the Panchayat Raj Scheme has proved a failure in the Adivasi area of Chhota Nagpur;
 - (b) whether old Panchayats are still working there; and
 - (c) if so, the steps being taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (c) In all the five districts of Chhota Nagpur Division, namely, Ranchi, Hazaribagh, Dhanbad, Singhbhum and Palamau, Gram Panchayats have been established under the Bihar Panchayat Raj Act, 1947. The Full-fledged three tier Panchayati Raj system has recently been introduced in the two districts of Ranchi and Dhanbad. Within their limitations, the Statutory Panchayats, which have held the field longer, have given a satisfactory enough account of themselves; their performance is reported to be in no way inferior to Panchayats elsewhere in the non-tribal areas. Their contribution particularly during the last famine and drought has been good. As for the higher-tier bodies in the two districts, their experience, in the view of the State Government, already justifies extension of the set up throughout the State. This, the State Government propose to do, including general elections to the Panchayats also, last constituted in 1965, after the coming mid-term poll in the State.

श्रादिवासियों के लिये ऋग की सुविधाएं

- 5116. श्री अ॰ सि॰ सहगल: क्या समाज कल्याए। मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या उनका ध्यान इस बात की स्रोर दिलाया गया है कि आदिवासियों को ऋण देने की सुविधा के लिए केवल 1 लाख रुपये की राशि मन्जूर की गई है न कि 2 लाख रुपये की जिसका उल्लेख संसद में किया गया था: और
 - (ख) शेष 1 लाख रुपये की राशि कब दे दी जायेगी?

समाज कत्यारा विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेरा गुह): (क) ग्रीर (ख): 22 जुलाई, 1968 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर की ओर ध्यान आमन्त्रित किया जाता है।

Wheat Procurement in Bulandshabr

- 5117. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- a) whether it is a fact that the purchase of wheat at Governmental level was stopped in Bulandshahr on the 30th June, 1968 by the Government of Uttar Pradesh and the Food Corporation of India:
- (b) whether it is also a fact that over 4,000 transport bills worth about Rs. 5 lakhs of Purchase Agencies appointed by Government in Bulandshahr have not been paid so far; and
 - (c) if so, the reasons for deferring and payments?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b): No, Sir.

(c) Does not arise.

Distribution of Cows mong the Flood Affected People of Jalpaiguri

- 5118. Shri Sharda Nand: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that a large number of milch cattle had died in Jalpaiguri as a result of the recent floods there; and
- (b) if so, the number of cows supplied by the Central Government during the months of August and September, 1968 for free distribution among the people of Jalpaiguri?

The Minister of State in the Ministry of food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) No cow was supplied by the Central Government free of cost to the people of Jalpaiguri during the months of August and September. 1968.

Non-delivery of a Money Order in Hindi

- 5119. Shri Hukam Chand Kachwal: Will the Minister of Communications be pleased to state:
- (a) whether attention of Government has been drawn to the news-item published in Daily Swadesh dated the 10th November, 1968 to the effect that a Money Order sent to Barabati Raffle, Orissa from Nagda village of Madhya Pradesh was returned to the sender only because it was written in Hindi;
- (b) whether it is also a fact that it was also written to the sender that further action be taken in English otherwise correspondence done in Hindi would be thrown into Waste-Paper basket;
 - (c) if so, the reaction of Government in this regard; and
 - (d) the action proposed to be taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Development of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) to (d): The matter is being looked into.

Postal Stamps issued in the Map of India Series.

5120. Shri Sharda Nand : Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Andaman, Nicobar Laccadive Islands were shown only in some of the fourteen postal stamps with Indian map issued by Government in 1957;
- (b) if so, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by Government against the officers responsible for this lapse; and
 - (c) if no action is proposed to be taken, reasons therefor?

The Minister of State in the Development of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

- (b) The Map of India was only symbolically reproduced on these stamps The printing of these stamps has however, since been discontinued.
 - (c) Does not arise.

सैटलमेंट अफसर की मृत्यु

- 5121. श्री घीरेन्द्र नाथ देव: क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार ने मार्च, 1968 में चीफ सैटलमेंट कमिश्नर के कार्यीलय के सैटलमेंट अफसर, श्री जे० एन० वली की असामायिक मृत्यु के बारे में घटनास्थल पर कोई जांच कराई है;
- (ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो उनकी मृत्यु के समय उनके साथ थे;

- (ग) क्या यह सच है कि वे सब व्यक्ति मुख्यालय छोड़ने के लिये आवश्यक अनुमित प्राप्त किये बिना ही दिल्ली से बाहर चले गये ;
 - (घ) जांच के क्या परिगाम निकले हैं;
 - (ङ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और
 - (च) इनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?
- श्रम, रोजगार तथा पुतर्वात मन्त्रालय में उर-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाएा) : (क्.) श्री जे० एन० वली की मृत्यु की परिस्थितियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस अधि-कारियों द्वारा जांच की गई थी।
- (ख) अधिकारी की मृत्यु सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, में हुई थी। उसकी मृत्यु के समय जो व्यक्ति उसके पास उपस्थित थे, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- (ग) प्राप्त सूचना के ग्रनुसार, श्री जे० एन० वली, 9 मार्च, 1968 को नई दिल्ली से 6 व्यक्तियों के साथ उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में जमना खस नामक स्थान के लिये रवाना हुये थे।

इन 6 व्यक्तियों में से पांच कार्य पर लगे सरकारी, पदाधिकारी हैं और छठा व्यक्ति सेवा निवृत हुआ पदाधिकारी है। उनमें से चार ने 9 तथा 10 मार्च, 1968 की छुट्टियों के अन्तर्गत मुख्यालय छोड़ने की आवश्यक आज्ञा ले ली थी।

- (घ) मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरुप हुई है और इसमें कोई घोखा नहीं हुआ है।
 - (ङ) और (च): प्रक्त नहीं उठता।

त्रिपुरा में प्लाईवुड का कारखाना

- 5122. श्री किरित विक्रम देव बर्मन: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 9 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10275 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार द्वारा दिये गये मार्ग दर्शन के अनुसार त्रिपुरा में प्लाईवुड कारखाने का पुन्रीक्षित करार का प्रारूप त्रिपुरा प्रशासन के इस बीच प्राप्त हो गया है;
- (ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित करार तथा सम्बन्धित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा उस परियोजना पर कितनी लागत क्षायेगी तथा उसके अन्तर्गत बनाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का कितना-कितना उत्पादन हो सकेगा; और
 - (ग) क्या प्रारूप करार को अन्तिम रूप देने के लिये आवश्यक मंजूरी दे दी गई है ?

खाद्य, कृषि, साधुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री श्रन्ना-साहिब शिन्दे): (क) जी हां। (ख) सक्षेप में, परिशोधित करार त्रिपुरा संघ क्षेत्र के उदमपुर, बेलोनिया और सबरूम नागरिक उप-प्रभागों के सरकारी वनों से 31 वर्ष तक एक निश्चित घेरे से ऊपर की 23 विभिन्न विशिष्ट इमारती किस्म के 8495 घन मीटर प्लाई के कुन्दों की प्रति वर्ष निकासी के ग्रिधकार के लिये हैं। विभिन्न कोटि की इमारती लकड़ियों के लिये विभिन्न स्वामित्व प्रस्तावित किये गये हैं, जिसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि इन दरों को प्रत्येक तीन वर्ष उपरान्त पट्टादाता की इच्छा पर संशोधित किया जा सकता है, किन्तु प्रत्येक संशोधन के समय इन दरों को पूर्व संशोधित दर से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। पट्टादाता की इष्टि में यदि पट्टोदार ने पूर्व करार की शर्तों को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण किया हो तो पट्टादाता की इच्छा पर पट्टो को आगामी अवधि के लिये भी बढ़ाया जा सकता है।

पट्टे दार प्लाईवुड संयन्त्र और आरे की मिल की स्थापना के लिये यन्त्रों की व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर होने की तिथि के 12 मास के अन्दर करेगा।

(ग) परिशोधित करार का प्रारूप 27 नवम्बर, 1968 को ही प्राप्त हुआ है और वह भारत सरकार के विचाराधीन है।

Payment for the Construction of Election Booths in U. P. During General Elections, 1967

- 5123. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of Law be pleased to state:
- (a) the District-wise, Tehsil wise and Circle-wise number of Lekhpals who have been paid the expenditure incurred on constructing the booths in U.P. during the General Elections in 1967 and the number of Lekhpals who have not so far been paid this amount; and
- (b) the date by which payment would be made to such of those Lekhpals who have not so far been paid this amount?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem): (a) and (b): The information is being collected.

दिल्ली में महिलाग्रों का श्रनेतिक पण्य

- 5124. डा॰ सुज्ञीला नायर: क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि दिल्ती में सिद्दीपुरा थाने के निकट सराय रोहिल्ला, लोका-शेड क्वाटरों में महिलाओं का अनेतिक पण्य किया जाता है ;
- (ख) त्या यह भी सच है कि यह कार्य कुछ पुलिस अधिकारियों (सिद्दीपुरा) की सांठगांठ से किया जाता है;
 - (ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और
- (घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तया सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है !

समाज कल्यारण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेखु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (घ) प्रदन नहीं उठते।

घोथी पंचवर्षीय योजना में वाि जियक फैसलों की वृद्धि

- 5125. श्री हिम्मतसिंहका: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सहकारी सिमितियों, उद्योगपितयों तथा वाणिज्य संघ द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में क्रियान्विति के लिये उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चौ नी पंचवर्षीय योजना में वाणिज्यिक फसलों के संवर्धन के लिए बनाई गई योजना के अन्तर्गत अनेक पैकेज प्रोग्राम हैं; और
 - (ख) यदि हां, तो इन पैकेज प्रोग्रामों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिष्ठ शिन्दे): (क) जी हां, कपास, मूंगफली, पटसन, तम्बाकू, लाख, काली मिर्च, काजू ग्रीर नारियल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें विभिन्न राज्यों के सर्वाधिक ससाधनों वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ताकि निर्यात/ग्रायात एवजी के लिये इनकी ग्रधिक मात्रा उपलब्ध हो सके।

(ख) कार्यक्रमों की विस्तृत रूप-रेखा तैयार की जा रही है।

Agricultural Produce Market Committee, Bulandshahr

5126. Shri Ram Gopal Shalwale:

Shri Yashpal Singh:

Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Agricultural Produce Market Committee Act, 1964 provides for the representation of Kacha Arhatis on Agricultural Produce Market Committees;
- (b) whether it is also a fact that Kacha Arhatis have not been given due representation in Bulandshahr Agricultural produce Market Committee;
- (c) whether it is a also fact that Kacha Arhati Sangh has demanded the removal of the person who has been nominated as their representative and to nominate two other representatives; and
 - (d) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes.

(b) No.

- (c) The Secretary, Kacha Arhati Sangh, Bulandshahr in his letter of November 30, 1968 has requested for accepting the resignation of the person representing the commission agents, and not for his 'removal'. No proposal has been received from the Kacha Arhati Sangh for nomination of two other representatives. The Kacha Arhati Sangh has, however, requested for nomination of any other suitable person as their representative.
- (d) Nece sary enquiries are being made in the matter by the State Government and appropriate action will be taken by them in accordance with the provisions of the Adhiniyam.

Sale of Maize by Farmers in U.P.

5127. Shri Yashpal Singh: Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the U.P. Government have imposed restrictions on the sale of maize by the farmers in the open market in Bulandshahr District;
- (b) whether it is also a fact that Government themselves are also not purchasing maize from them; and
- (c) if so, the reasons for which restrictions have been imposed on the sale of maize by the farmers in the open market when Government are not making any purchases from them?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) It has been reported by the U.P. Government that no such restriction has been imposed.

- (b) Both the State Government and the Food Corporation of India entered in U.P. Markets including Bulandshahr to make purchases of maize. While the purchase operations of F.C.I. is continuing the State Government have recently withdrawn themselves from the market.
 - (c) Does not arise.

रुई विकास परिषद्, बम्बई

5128. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी: श्री लोबो प्रभु:

क्या लाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बम्बई में रुई विकास परिषद की स्थापना कब की गयी थी, इस पर कितना ब्यय किया गया और इसकी अब तक की क्या उपलब्धियां हैं;
- (ख) भारतीय केन्द्रीय रूई सिमिति के समाप्त किये जाने के बाद वाि ज्यक पैमाने पर रूई की किन-किन नई किस्मों का विकास किया गया है और इन्हें देश के किन-किन मागों में उगाया जा रहा है;
- (ग) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में हई सम्बन्धी अनुसन्धान और विकास पर कितन! व्यय किया गया है ; और

(घ) क्या आयामी बर्षों में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार की कोई विशेष योजनाएं हैं ताकि देश की विदेशी हुई पर निर्भरता को कम किया जा सके और, यदि हां, तो वे क्या हैं?

खाडा, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रानासाहिक शिन्दे): (क) कपास विकास परिषद् की स्थापना 19 मई, 1966 को की गयी थी। इस पर अभी तक 19,953 रुपये व्यय किये जा चुके हैं। परिषद् एक परामर्श-दात्री संस्था है श्रीर इसने कपास की मूल्य तीति सहित इसके विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कई लामदायक सुभाव प्रस्तुत किये है।

(ख) मारतीय केन्द्रीय कपास समिति के उपरान्त जो कि केवल ढाई वर्ष पूर्व ही समाप्त हुई थी वाशिज्यिक स्तर पर किसी भी नई किस्म को विकसित नहीं किया गया है; किन्तु निम्न नई किस्मों को जो पहले ही विकसित की गयीं थी, अब सामान्य खेती करने के जिसे निर्मुक्त कर दी गई है:-

नई किस्म का नाम राज्य जिसमें खेती करने के लिये निर्मुक्त कर दिया गुग्रा है।

(1) एम सी यू-4 मद्रास (ग्रीष्म कालीन कम्बोडिया ट्रैक्ट)

(2) एम सी यू-5 मद्रास (शरद कालीन कम्बोडिया ट्रैक्ट)

(3) सुजाता (को-पूसाएजिपशन) मद्रास

(4) विजय मैसूर (घटाप्रसा परियोजना क्षेत्र)

(5) हैम्पी मैसूर (तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र)

(6) अगवीश (वी: 1007) महाराष्ट्र (विद्रभ क्षेत्र)

(7) जे० 34 पंजाब

- (ग) इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाओं झ समा प्रद्रन पर स्थानी जायेगी।
 - (घ) जी हां। इसमें निम्न योजनायें सम्मिलित हैं:-
 - (L) पैके कार्यक्रमों के आधार पर कपास की सघन कृषि,
 - (2) न्यूबिस भौर प्रामारभूत बीजों का उत्पादन,
 - (3) बड़े प्रमाने पर पौच संरक्षण आन्दोलन का संगठन,
 - (4) विभिन्त प्रकार के प्रदर्शन भूखण्डों का संगठन
 - (5) शीच संरक्षस द्यायों के प्रदर्शन का संगठन घोर
- (6) राष्ट्रीय प्रदर्शनों का संगठन इनके अतिरिक्त, क्रमास के इंटपहुन करने वाले सभी प्रमुख राज्य कपास विकास की समन्वित योजनाओं को कार्स क्रमाई उहे हैं।

ग्रखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संस्था की मान्यता का रद्द किया जाना

- 5129. श्री रा० कु० सिंह: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या मारत के जीवन बीमा निगम ने अखिल मारतीय बीमा कर्मचारी संस्था की मान्यता को रद्द करने का निर्णय किया है;
- (ख) क्या इस प्रकार की कार्यवाही कर्मचारियों के अधिकारियों के विषद्ध होगी; और
- (ग) यदि हां, तो मान्यता रद्द किये जाने की कार्यवाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जीवन बीमा निगम ने अखिल भारतीय कीमा कर्मचारी संस्था की मान्यता को रद्द कर दिया है।

(ख) और (ग): इस संस्था को अनुशासन संहिता के अघीन मान्यता दी गई थी भीर इस संस्था द्वारा संहिता के कुछ उल्लंघन किए जाने के कारण संहिता में निर्घारित प्रक्रिया के अनुसार इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई।

गिर दोरों की संख्या में कमी

- 5130. श्री क॰ प्र० सिंह देव: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि गिर शेरों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है और हाल की गए। ना में इनकी संख्या 177 पाई गयी थी जबकि पांच वर्ष पूर्व इनकी संख्या 290 थीं ;
 - (ख) यदि हां, तो इतके क्या कारण हैं; और
- (ग) गिर शेरों की नस्ल को समाप्त होने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्ये-बाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) यह सच है कि गिर शेरों की संख्या में कमी हुई हैं। शेरों की संख्या जून, 1968 की गणना के अनुसार 177 है जबकि इसकी तुलना में 1955 में (पांच वर्ष पूर्व नहीं) उनकी संख्या 290 थी फिर मी, यह बतलाया जाता है कि पहली शेर गणना अप्रत्यक्ष गणन—उपाय अर्थात उनके पग चिन्ह के द्वारा की गई थी जिसको बड़ा कच्चा और मोटा (लगमग) उपाय समका गया है, जबकि वर्तमान गणना प्रत्यक्ष गिनने के उपाय से अर्थात शिकारों पर एकत्रित हुये शेरों की वास्तविक गणना से की गयी है, जो कि तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय एवं यथार्थ है।

(ख) प्राकृतिक कारणों के द्वारा हुई मृत्युओं की वजह से संख्या में कमी के अति-रिक्त 1963-68 के दौरान निम्न विणित विभिन्न कारणों की वजह से 27 शेरों की कमी हुई:-

चिड़ियाघरों को बाहर				•
भेजे गये या	दुर्घटना से मृत्यु	विष दिये या		
राज्य से बाहर भेजे गये		गोली से मारे हुये	कुल कमी	
12	4	11	27	-

- (ग) गिर शेरों की संख्या को बनाये रखने के लिये गुजरात सरकार ने अघोलिखित उपाय अपनाये हैं:-
 - (1) 18-9-1965 से अपने गिर बनों का 1265.01 वर्ग किलो-मीटर (488.42 वर्ग मील) का क्षेत्र एक व्रन्य प्राणि शरण स्थान में निर्मित कर दिया है।
 - (2) शेरों की संख्या में किसी भी बाधा को रोकने के लिये शरण-स्थान के क्षेत्रों में समस्त नस्लों के शिक'र पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
 - (3) जब शेर लोगों के पशुओं कं मार देते हैं तो उन पशु-स्वामिओं को बदले की भावना से शेरों को विष देने से रोकने के लिये, राज्य सरकार ने उनको नगद रूप में क्षति पूर्ति देने के लिए एक उपबन्ध बनाया है।
 - (4) गिर-शरण स्थान के विकास के लिये राज्य सरकार समस्त सम्भव वित्तीय सहायता देती है। इस शरण-स्थान के विकास के लिये, जिसमें जीवजन्तुओं के कल्याण के लिए जल सुविधायें प्रदान करना, सड़कों की मरम्मत आदि उपबन्ध सम्मिलित हैं, 1968-69 वर्ष के दौरान 1,90,000 रुपये की धन राशि मंजूर की गई है।

भ्रब्ट ग्रायरण के ग्राषार पर निर्वाचन लड़ने के लिए ग्रम्पथियों को विवर्जित करना

- 5131. श्री डी॰ एन॰ पाटोबिया: क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या न्यायालय में भ्रष्ट आचरणों के साबित हो जाने के आधार पर अम्यियों को निर्वाचन लड़ने से विवर्जित करने के लिए निर्धाचन विवि में कोई कालावधि विहित की गई है;
- (ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा कोई विधान पुरःस्थापित करने का है ; और
 - (ग) यदि हां, तो कब ?

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्रों (श्री मु० यूनुस सलीम): (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क में अधिकथित है कि जो व्यक्ति धारा 99 के अधीन किसी भीदेश द्वारा किसी भ्रब्ट आवर्रण का दोषी ठहराता गया है वह उस तारीख से, जिसकी वह भादेश प्रभावशील होता है, छः वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशों से ग्रायातित उर्वरकों का बिहार में बिना बिके पड़ा रहना

- 5132. श्री बाबूराव पटेल: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय खाद्य निर्देशक द्वारा ग्रंमरीका, रूस, फ़ाँस और पौलैंड से आयातित 3.50 करोड़ रुपये के मृत्य का रसायनिक उर्वरक बिहार के विभिन्न गीदामी में एक वर्ष से अधिक समय से बिना बिका पड़ो है;
- (ख) क्या यह सच है कि बिहार के 156 डिपुओं में 7 लाख से अधिक उर्वरक के बोरे बिना बिके तथा उपेक्षित हालत में पड़े हैं और केवल पटना जिने में ही एक लाख से अधिक बोरे बिना बिके पड़े हैं;
- (ग) उर्वरक के आयात के क्या कारण हैं और इतने बोरे न बेचने के क्या कारण हैं और सरकार को कितनी राशि की हानि की संभावना है;
- (घ) उर्वरकी की बेचने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और यह कब तक बिक बाने की संमावना है; और
 - (ड) यदि नहीं, ती इसके क्या कारण है ?

साद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रन्ता साहिब शिन्दे): (क) से (ङ): बिहार राज्य से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही समा पटल पर रख दी जायेंगी।

विशासापटनम की पहाड़ियों में काफी बागान के लिए भूमि

- 5133. श्रीविक नरसिम्हा रावः क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
- (क) क्या यह सर्च है कि विशासापटनम की चिन्तापितन तथा पाडेरू पहाड़ियों को काफी बागानों के लिये नियत कर दिया गया था ;
- (ख) क्या सरकार का विचार यह भूमि काफी बागानों के लिये गिरीजनों को देने का है जो कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहते हैं ;
- (ग) यदि हां, तो प्रत्येक गिरीजन को कितने एकड़ जमीन देने की प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ; और
 - (ब) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामृदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) काफी विकास के लिए विशाखापटनम में 5,600 एकड क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा पट्टे पर दिया जाना है।

(ख) से (घ): राज्य सरकार द्वारा कबीलों को पट्टे पर देने के लिए उपयुक्त क्षेत्र आरक्षित रेक्खा जाएगा। 25 एकड़ क्षेत्र से अधिक रोपण के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा निश्चित की गई शनों पर कबीले-मेजदूर लगाए जाएगें। एक एकड़ तक की पट्टे वाली भूमि रखने वेंग्ले को सिक्योरिटी डिपोजिट की अदायगी की छूट होगी।

मनीपुर विक्स मार्केटिंग कोम्रापरेटिव सोसायटी

- 513 । श्री एन० मेघचन्द्र: क्याखाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृषा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सब है कि मनीपुर एपेक्स मार्किटिंग की आपरेटिंक सोसाइटी लिमिटेड ने व्यक्तियों और समितियों को सोसायटी के लिये घान की खरीद तथा सप्लाई के लिये कई वर्षों तक अग्रिम घन दिया और बहुत से व्यक्तियों ने जिन्होंने इन प्रकार घन लिया था, न तो घन बार्षिस दिया और नहीं किसी ग्रन्य रूप से उसे चुकाया;
- (स) यदि हां, तो उन व्यक्ति में और समितियों की सूबी क्या है जिन पर बह राशि बाकी है जीर प्रत्येक को कितना-कितना घन देना है; और
 - (ग) बकाया धन को वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यकाही की गई है?

खाड, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (थी एम॰ एस॰ गुरुपदस्वामी): (क) 1961-62 से 1964-65 तक की अविधि में मनीपुर एपेक्स को आ-परेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि॰ ने व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों, जो मनीपुर एपेक्स को आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी की सदस्य हैं को एपेक्स मार्केटिंग सोसायटी के लिए धान सथा चावल की खरीद तथा सप्लाई करने हेतु 2,83,588 13 रु॰ (दो लाख तिरासी हजार पांच सौ अठासी रु॰ तथा तेरह पैसे) की कुल धन राशि दी। अधिकाश सहकारी समितियों तथा व्यक्तियों, जिन्हें अग्रिम धन दिया गया था, ने उन्हें दिए गए अग्रिम धन के बदले में एपेक्स मार्केटिंग सोसायटी को धान तथा चावल सप्लाई किए, किन्तु 11 समितियों तथा 7 व्यक्तियों के कुछ थोड़े से मामलों में कुछ धन अभी बकाया रहता है।

(ख) व्यक्ति सदस्यों तथा सहकारी सिमतियों, जो एपेक्स मार्केटिंग सोसायटी की सदस्य हैं, की सूची उनसे बकाया राशियों सहित नीचे दी गई है।

समितियां	क चै०
(1) हेरोक पार्ट-1 सर्विस कोआपरेटिव सोसायटी लि०	76.66
(2) लंगथाबल 'सर्विस कोश परेटिव सोसायटी लि॰	864.23
(3) थाउबल लाज साइज्ड कोग्रापरेटिव सीसायटी लि॰	1838.67
(4) लम्लाई सिविस कोआपरेटिव सोसायटी लि॰	63.82

(5) मोयरंग लाजं साइज्ड कोआपरेटिव सोसायटी लि०		3194.39
(6) मोयरंग प्राइमरी मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि॰		1843.45
(7) मायांग इम्फाल पैडी हस्कर्स सोसायटी लि॰		2843.45
(8) फाउगाकचाव इखाई सर्विस कोआपरेटिव सोसायटी लि	•	676.97
(9) लम्शांग लार्ज साइज्ड कोआपरेटिव सोसायटी लि॰		1623.46
(10) टेन्था खुनाउ कोआपरेटिव सोसायटी लि॰		500.00
(11) टेन्था कोआपरेटिव सोसायटी लि॰		1000.00
•	योग [े]	14525.10
ःय क्ति		
I. श्री डब्ल्यू खोमे सिंह, कौंगखाम		361.70
2. श्री ठा० घोमचा सिंह, केशमपत		979.25
3. श्री ए ॰ ब्राकचं द सिंह		276.15
4. श्री ए॰ टोम्बा सिंह		500.00
5. श्री एल इबोचा सिंह		66.17
6. श्री कुलचंद्र सिंह		72.42
7. श्री एम • इबोम्बा सिंह		8.57
	योग	2264.26
9	हुल योग	16,789.36
•	_	

(ग) चूक करने वालों के विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली के लिए कार्यवाही मांग मोटिस आदि जारी करके आरम्भ की गई थी। उचित कानूनी कार्यवाही जिसमें पंच निर्णय भी शामिल है, के बारे में विचार किया जा रहा है।

Income-tax Tribunal Bench in M P.

- 5135. Shri Ram Avtar Sharma: Will the Minister of Law be pleased to state \$
- (a) whether it is a fact that there is no bench of Income-tax Tribunal in Madhya Pradesh though it is a big State;
 - (b) if so, the reasons therefor; and
- (c) whether Government propose to set up a bench of Income-tax Tribunal there and if so, by when and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem): (a) There is no Bench of the Income-tax Appellate Tribunal in Madhya Pradesh.

(b) It is not that every State has a Bench of the Tribunal. At present all appeals and applications from the Rewa Division of Madhya Pradesh are heard and determined by the Allahabad Bench, those from the Gwalior Division by the Delhi Benches and those from the remaining areas by the Bombay Benches of the Tribunal.

(c) A proposal in this regard is under active consideration and a decision in the matter will be taken as early as possible.

हस से ट्रैंटरों का श्रायात

- 5136. श्री बृजराज सिंह कोटा: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृषा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय तथा वाशिज्य मन्त्रालय के बीच मतभेद होने के कारण सोवियत संघ से ट्रेक्टरों का आयात नहीं हो रहा है;
 - (ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और
- (ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा दिये गये ग्राश्वासन के बावजूद अब भी ट्रेक्टरों का आयात क्यों नहीं किया जा रहा है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

- (ख) प्रश्न नहीं होता।
- (ग) रूस से ट्रैक्टर आयात करने के बारे में बातचीत रूसी सप्लायरों के साथ काफी आगे बढ़ चुकी है, जिसे शीघ्र ही ग्रन्तिम रूप दिये जाने की आशा है। ठेका किये जाने के परचात् कुछ ही महीनों में आयात शुरू होने की आशा है।

हरिजनों के साथ व्यवहार

- 5137. श्री बाबूराव पटेल: क्या समाज कल्यारा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी के जन्म स्थान पोरबन्दर में सवर्गे हिन्दुओं तथा हरिजनों के लिये पानी के पृथक-पृथक नल हैं;
- (ख) यदि हां, तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के बावजूद इन नलों को अलग-अलग बनाये रखने के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या रतलाम मध्य प्रदेश में हरिजनों को अपनी मूं छें ऊपर की श्रोर कर के रखने की अनुमति नहीं दी जाती; और
- (घ) हरिजनों की सामाजिक स्थिति तथा उनके साथ व्यवहार में कोई प्रशंसनीय सुघार किये बिना कब तक उनका उत्पीड़न केवल राजनीतिक प्रचार के लिये ही किया बाता रहेगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (हा० (श्रीमती) फूलरेखु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

- (ग) पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसा प्रतीत होता है।
- (घ) आक्षेप अनुचित अथवा न्याय विरुद्ध है।

विश्व बैंक के प्रध्यक्ष के साथ कुषि के सम्बन्ध में चर्चा

- 5138. श्री शिव चन्द्र भा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री राबर्ट मेकनामारा ने अपने हाल ही के नई दिल्ली के दौरे के दौरान उन से बातचीत की थी; और
 - (ख) यदि हां, तो कृषि के विकास के हिन्टकीएं से क्या बातचीत हुई ?

क्षाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्ना-साहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रक्त ही नहीं होता।

सस्ते तथा प्रधिक उत्पादकता हलों को इस्तेमाल में लाना

- 5139. श्री शिव चन्द्र भा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृश्य करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि समूचे देश में प्रयोग में लाये जाने वाले लकड़ी के वर्तमान हल से अधिक उत्पादन नहीं होता है ;
- (ख) यदि हां, तो क्या किसी सस्ते और अधिक उपज देने वाने हल को प्रयोग में लाने की कोई योजना है;
 - (ग) यदि हां, तो कब और उसका ब्योरा क्या है ; और
 - (घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं?
- साह्य शिल्डे): (क) जी हां, लकड़ी के हल को 'मोडल्ड-बोर्ड' हल के समान क्षमतापूर्ण नहीं माना जाता है।
- (ख) और (ग): बहुत से देसी औजार निर्माताओं द्वारा निर्मित लोहे के सस्ते और अच्छे हल बाजार में पहले से ही उपलब्ध हैं। अनुमान है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात बादि राज्यों में इस प्रकार के लगभग 25 लाख हल पहले ही प्रयोग किये जा रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार के हलों का काफी अधिक संख्या में प्रयोग किया जा रहा है।
 - (घ) प्रकल ही नहीं होसा।

मधुबनी डाक घर (बिहार)

5140. श्री शिव चन्द्र भाः वया संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) क्या यह सच है कि मधुबनी डाकघर का वर्तमान भवन काफी बड़ा नहीं है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि डाक विभाग ने इसके लिये दो प्लाटों का पहले ही अर्जन कर लिया है; और
 - (ग) यदि हां, तो उन में से किसी एक प्लाट पर नया भवन कब बनाया जायेगा?

संसद-कार्यतथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क): जी हां।

- (ख) जीहां।
- (ग) इन भूखंडों में से एक पर इमारत के निर्माण के लिए कार्यवाई चल रही है। इस परियों जना की मंजूरी दी जा चुकी है और शेष औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद निर्माण-कार्य शुरू किये जाने की संभावना है।

मजदूर संघों की सदस्यता

- 5141. श्री शिव चन्द्र भ्याः नया श्रम तथा पुनर्जास मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि:
- (क) इस समय आई॰ एन॰ टी॰ यू॰ सी॰, ए॰ आई॰ टी॰ यू॰ सी॰, एच॰ आई॰ एम॰ एम॰, एम॰ एम॰ पी॰ तथा यू॰ पी॰ यू॰ सी॰ के पृथक कितने सदस्य हैं;
- (ख) क्या गत दो वर्षों में इनकी संख्या में कोई वृद्धिया कमी हुई है; इसके क्या कारण हैं;
- (ग) उक्त प्रत्येक मजदूर संब संगठन के प्रधान को प्रतिमास कितना वेतन तथा भक्ते मिलते हैं ; और
- (घ) यदि इन को किसी अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के कोई विदेशी आर्थिक सहायता मिलती है तो उसकी वार्षिक राशि क्या है?

अम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) 31 दिसम्बर, 1966 की उपलब्ध अंतिम प्रमाणित सदस्य-संख्या नीचे दी गई है:-

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेंस	1,405,465
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	432,852
हिन्द मजदूर सभा	433,015
संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस	93,454

एच० एम० पी० की सदस्य संख्या मालूम नहीं है, क्योंकि उसकी सदस्य संख्या की जांच महीं की गई है।

- (ख) 'चूं कि 31 दिसम्बर, 1966 के बाद की ग्रविध की जांच नहीं की गई है, अतएव सूचना उपलब्ध नहीं है।
 - (ग) और (घ): सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

भारतीय केन्द्रीय कपास समिति का पुनर्गठन

- 5142. श्री लोबो प्रभु: नया खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;
- (क) भारतीय केन्द्रीय कपास सिमिति का कब, क्यों श्रीर किस की सलाह पर विघटन किया गया था;
- (ख) जो विकास कार्य भारतीय केन्द्रीय कपास समिति द्वारा किये जा रहे थे उनको अब कौन सा निकाय कर रहा है और उसे अब तक कितनी सफलता मिली है; और
- (ग) क्या सरकार का विचार भारतीय केन्द्रीयकपास समिति का पुनः गठन करने का जिससे कपास के विकास की और विशेष तथा सकेंद्रित ध्यान दिया जा सके जैसा कि पहले दिया जाया करता था ?
- खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) द्वितीय भारतीय श्रमरीकी दल की सिफारिशों पर भारतीय सरकार ने निश्चय किया कि जिन समितियों को जिनमें भारतीय केन्द्रीय कपास समिति भी सम्मिलित है समाप्त कर देना चाहिये और समितियों द्वारा किये जाने वाला श्रनुसन्धान कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य में सम्मिलित कर देना चाहिये, जिसे समुचितरूप से पुनर्ग- ठित एवं शक्तिशाली बनाना चाहिये, जिससे की देश की आवश्यकताओं के श्रनुष्प इसे एक राष्ट्रीय कृष अनुसंधान कार्य क्रम के विकास करने तथा उसके प्रशासन करने के योग्य बना दिया जाये। तदनुसार भारतीय केन्द्रीय कपास समिति को 31 मार्च, 1968 को समाप्त कर दिया गया था।
- (ख) भारत सरकार ने कपास के विकास एवं विपण् ने लिए उसे परामर्श देने हेतु भारतीय केन्द्रीय कपास समिति की समाप्ति पर भारतीय कपास विकास परिषद की स्थापना की है। परिषद के परामर्श पर भारत सरकार ने देश में कपास के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिये विशेषतः लम्बे तन्तु वाली किस्मों के लिये निम्नलिखित योजनायें प्रारम्भ कर दी हैं:
 - (i) सघन उपायों के द्वारा क्षमतापरक क्षेत्रों में प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये (कपास का पर्कंज कार्यक्रम) आक्ष्यासित जल सण्लाई वाले क्षेत्रों में कपास के अधिकतम उत्पादन के लिये योजना;
 - (ii) कपास के न्यूक्लियस और आधारभूत बीज के उत्पादन के लिये योजना:
 - (ii) समुद्र-द्वीपीय कपास के विकास के लिये योजना।
 - (ग) जी नहीं।

कारलानों के मुख्य निरीक्षकों का सम्मेलन

5143. श्रीक०प्र० सिंह देव: श्रीसीताराम केसरी:

नया श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कारलानों के मुख्य निरीक्षकों के हाल ही में हुए सम्मेलन का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है;
- (ख) यदि हां, तो कारखानों के मुख्य निरीक्षकों द्वारा की गई सिफारिश की मुख्य मुख्य वातें क्या हैं ; और
 - (ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुवर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख): शायद आशय मई 1958 में राष्ट्रीय श्रम अयोग द्वारा बुलाये गये कारखानों के मुख्य निरीक्षकों के सम्मेलन की रिपोर्ट से है। सिफारिशें आयोग के पास की गई हैं, सरकार के पास नहीं। वे मुख्यतः कारखाना निरीक्षकों के संगठन, कार्य करने की स्थितियों, औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारणों, उनकी संख्या कम करने के उपायों और निरीक्षणों आदि के बारे में हैं। आयोग ने इस विषय में एचि रखने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के विचार जानने के लिए इन सिफारिशों को प्रकाित किया है।

(ग) यह आज्ञा की जाती है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग यथा समय इस विषय पर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगा। तब तक सम्मेलन द्वारा आयोग को की गई सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

भिक्षावृति का उन्मूलन

- 5144. श्री क० प्र० सिंह देव: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृता करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि वृद्ध जन सम्मान समिति नामक कल्याण संस्था ने देश में मिक्षा वृति को समाप्त करने के लिए सरकार को एक योजना प्रस्तृत की है;
 - (ख) यदि हां, तो समिति द्वारा दिये गये सुभावों की मुख्य मुख्य बातें क्या है ;
 - (ग) क्या सरकार ने इन सुभावों पर विचार किया है; और
 - (घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिकिया है ?

समाज कल्याम विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेगु गुहा): (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ): प्रक्त नहीं उठते।

संवैधानिक उपबन्धों के निर्वचन के पुनिश्लोकन के लिए (मजीनरी) ध्यवस्थातंत्र का मुजन

- 5145. श्री देवक नन्दन पाटोदिया: नया विधि मंत्री यह बताने की कृषा करेगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि इण्डियन सोसाइटी आफ इन्टरनेशनल बार ने उच्चत्तम स्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा संत्रिधान के विभिन्न उपबन्धों के समय-समय पर किये गये निर्वचनों के पुनर्ति तोकत के तिए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बारे में महासभा द्वारा किये

गए पुनर्विलोकन के आधार पर संविधान में आवश्यक संगोधनों का सुफाव देने के लिए स्थायी मशीनरी बनाने का सुफाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुयूनुस सलीम): (क) जी हां।

(ख) सुभावों पर सरकार द्वारा सम्यक्तः विचार किया जाएगा ।

पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी

- 5146. श्री ज़ुगल मंडल: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
 - (क) पश्चिम बंगाल में इस समय कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ; और
- (ख) उन्हें रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?
- श्रम, नियोजन तना पुनर्वास मंत्रालय में उप मत्री (श्री स० चु० जमीर): (क) इस विषय में जो सूचना उपलब्ध है वह पश्चिम बंगाल के रोजगार कार्यालयों के चालू रिजस्टर में दर्ज रोजगार चाहने वाले उम्मीदवारों की संस्था के बारे में है जोकि 31.10 1968 को 4.35,192 थी।
- (ख) पिंचम बगाल के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं में सिम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगारों के लिए अधिकाधिक रोजगार अवसर प्राप्त होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में नलकूप लगाना

- 5147. श्री जुगल मंडल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार ने चौथी पंचयर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में नलकूप लगाने की कोई योजना बनाई है;
 - (ख) यदि हां, तो उसका व्यीरा क्या है; और
- (ग) 1968-69 में नलकूप लगाने के लिये कुल कितने घन की व्यवस्था की गई है सथा नलकूप लगाने के लिये किसानों को व्यक्तिगत रूप से दी जाने ाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाओं का व्योरा क्या है ?
- खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना साहिब शिन्दे)): (क) जी हां।
- (ख) पश्चिम बंगाल राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी ग्रन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अविधि में 1,000

गहरे नलकूपों, 20,000 कम गहरे नलकूपों और 30,000 फिल्टर पाइन्टों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। उपरोक्त लक्ष्यों की सिफारिश खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सह-कारिता मंत्रालय के केन्द्रीय कार्यकारी दल ने की है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष की अविध में गहरे नलकूपों का योजना के लिये 175.00 लाख रुपये और कम गहरे व फिल्टर पाइन्टों के लिये 50.00 लाख रुपये का बजट में उपबन्ध किया गया है भीर कृषकों को फिल्टर पाइन्टों की खुदाई के लिये 1500 रूपये तक ऋगा दिया जाता है।

पश्चिमी बंगाल की चीनी तथा खण्डसारी का नियतन

- 5148. श्री जुगल मण्डल : नया खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बनाने नी कृपा करेंगे कि :
- (क) जनवरी, 1968 से नवम्बर, 1968 तक पश्चिमी बंगाल को प्रतिमास चीती तथा खण्डसारी का कितना कोटा अलाट किया गया ; और
- (ख) पश्चिम बंगाल को जनवरी से दिसम्बर 1967 तक दिये गये मासिक चीनी के कोटे की तुलना में यह कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ता-शाहिब शिन्दे): (क) और (ख): पश्चिमी बगाल को जनवरी, 1967 से दिसम्बर, 1967 तक और जनवरी, 1968 से नवम्बर, 1968 तक आवंटित चीनी का मासिक कोटा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2789/68] 1967 और 1968 के वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल अथवा अन्य किसी राज्य को खण्डसारी चीनी का कोई मासिक कोटा आवटित नहीं किया था।

उत्तर प्रदेश में खण्ड बीज फार्म

- 5149. श्री काशीनाथ पाष्डेय: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में ग्रब तक कितने खण्ड बीज फार्म स्थापित किये गये हैं;
 - (ख) प्रत्येक जिले के किन-किन खण्डों में ऐसे फार्म खोले गये हैं ; और
- (ग) इस प्रकार स्थापित किये गये प्रत्येक फार्म में, जिलावार कुल कितने एकड़ भूमि में फसल पैदा की जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रम्ना-साहिब शिन्दे): (क) से (ग): पूछी हुई जानकारी का एक विवरण समा-पटल पर रखा बाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2790/68]

उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

5150. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितने स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं ; और
- (ख) वर्ष 1968-69 में कितने स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है तथा वे कहां-कहां पर खोले जायेंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) 175 इसमें 1968-69 में अब तक खोले गए 6 स्वचालित एक्सचेंज भी शामिल हैं।

(ख) 1968 69 के क्षेष भाग के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर 16 और स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किये जाने की सम्भावना है:

1.	बुलन्दशहर	9.	कोरा
2.	चर्रा	10.	नकुर
3.	चरखारी	11.	पिसवाह
4.	देहरादून	12.	पोवायां
5.	डल्ला	13.	पुन्हाना
6.	गंज डुंडवारा	14.	रीना
7.	हमीरपुर	15.	सदाबाद
8.	जहानाबाद	16.	सिद्धौली

उत्तर प्रदेश को चीनी की श्रावश्यकता

5151 श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अन्तूबर और नवम्बर 1968 के लिये केन्द्रीय सरकार से कितनी चीनी मांगी थी तथा केन्द्रीय सरकार ने इन महीनों के लिये उत्तर प्रदेश का कितना कोटा निर्धारित किया था; और
- (ख) केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त महीनों में वास्तव में कुल कितनी चीनी की सप्लाई की थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्ना-साहिब शिन्दे): (क) और (ख): उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त, 1968 में अपने 10,603 मीटरी टन के मासिक कोटे के स्थान पर 21,000 मीटरी टन लेवी चीनी के मासिक कोटें के लिए कहा था। उनकी इस मांग को लेवी चीनी की सीमित उपलब्धि के कारण नहीं माना जा सका। जून से नबम्बर तक के महीनों में उत्तर प्रदेश को चीनी का आवंटन इस प्रकार किया गया था:

		(मीटरी टन)
जून,	1968	10,739	(क)
जुलाई,	1968	10,739	(ক)
अगस्त,	1968	17,719.4	(ख)
सितम्बर,	1968	10,739	(布)
ग्रक्तूबर,	1968	10,739	(क)
नवम्बर,	1968	10,739	(क)

- (क) 136 मीटरी टन भेषजीय यूनिटों को आवंटन के लिए शामिल है।
- (ख) 6,980.4 मीटरी टन त्यौहारों के लिए ग्रौर 136 मीटरी टन भेषजीय यूनिटों को आवंटन के लिए शामिल हैं।

कांडला उर्वरक परियोजना के स्थापना स्थान का परिवर्तन

- 5152. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि कांडला के बदले अहमदाबाद में उर्वरक परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया गया है;
- (ख) क्या उपरोक्त निर्एाय इस आधार पर किया गया है कि वहां इस परियोजना के लिए पर्याप्त नेप्था नहीं है और कारखाने की शोघन शाला को गैस पर ही आश्रित रहना पड़ेगा; और
- (ग) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय किस प्रकार अन्य उर्घरक कारखानों के विकास को प्रभावित करेगा जो कि नैफ्था पर आधारित किए जाने हैं ?
- खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० पुरुपदस्वामी): (क) से (ग): अभी कुछ दिन पहले, संकेत मिले हैं कि कलोल । नावागाम क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस, जिसका उर्वारकों के विनिर्माण के लिए लाभदायक रूप से उपयोग किया जा सकता है, उपलब्ध है। यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या कांडला के प्रस्तावित उर्वारक संयंत्र को नैफ्था अथवा प्राकृतिक गैस पर आधारित किया जाना चाहिए और क्या परियोजना के एक भाग को गैस क्षेत्रों के निकट ले जाना चाहिए।

Part-Time Employees at Milk Depots of Delhi Milk Scheme

- 5153. Shri Nihal Singb: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that the employees working in the Milk depots of Delhi Milk Scheme put in only 1 hours work daily;
- (b) if so, whether it is also a fact that these employees have to devote half an hour extra for accounts work; and

(c) whether Government propose to fix full two hours' duty for these employees and if not, the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b) The staff at Milk Depots of D.M.S. are required to work for $2\frac{1}{2}$ hours including $1\frac{1}{2}$ hours for distribution of milk and I hour for preparation of accounts and deposit of cash.

(c) Does not arise.

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुग्नों के कर्मचारियों के वेतन

- 5154. श्री निहाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्व योजना के दूव डिपुओं के कर्मचारियों को गत दस वर्षों से वही वेतन मिल रहा है जबकि महंगाई मत्ता गतप्रतिगत बढ़ गया है; और
- (ख) क्या सरकार का विचार उनके वेतन बढ़ाने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रत्नासाहिब जिन्दे): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना की दरें अन्य प्रमुख योजनाओं की दरों की तुलना में अधिक भ्रच्छी हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

	दिल्ली	बम्बई	कलकता
हिपो मैनेजर	50)	40)	40)
हिपो असिस्टेंट	25)	30)	20)

Minor Irrigation Schemes for Rajasthan

5155. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

whether Government have made special allocations during 1968-69 for the minor irrigation schemes in Rajasthan in view of the continuous famine and drought conditions there;

- (b) whether the State Government have asked for any special allocation for implementing their minor irrigation schemes; and
- (c) if so, the details thereof and whether the request has been met in full and if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c) The Planning Commission has approved an outlay of Rs, 2250 lakhs for the Minor Irrigation Programme of Rajasthan Government for 1968-69. The State Government has, however, budgetted an amount of Rs. 199.0 lakhs which is expected to be fully utilised.

No specific request has been received from the Government of Rajasthan for any special allocation during the current financial year for the minor irrigat on schemes. However, on the basis of the recommendations of the Central Team of officers which visited Rajasthan during October 1968 to assess the situation created by drought, the Government of India has decided to adopt a ceiling of expenditure of Rs. 640.0 lakks for 'Relief' items and Rs. 256.0 lakks for 'Loan' item for purposes of Central assistance during 1968-69. The above amounts include inter-alia Rs. 15.0 lakks for deepening of existing wells under 'Relief' and the following items under 'Loan' which fall under the purview of 'Minor Irrigation' programme.

(i) Cost of sinking 60 tubewells

Rs. 85.00 lakbs

(ii) Electrification of 32 tubewells within one mile of existing lines.

Rs. 6.0

(iii) Construction of Balancing reservoirs near existing tubewells and dug-cum-bore wells.

Rs. 15.0 ,,

Total

Rs. 106.00 lakhs

Expansion of means of Communications

5156. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) the steps taken by Government to make good the shortage of the means of Communications in Rajasthan, to open Post Offices to provide telephone lines and to open Public Call Offices in hilly and desert areas of the said State so as to enable the residents of these backward areas to benefit from these means of communications; and
- (b) the proposals being considered by Government to be taken up next year to bring about improvement in the means of Communications in Rajasthan?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b): Care is taken to see that all areas of Rajasthan are covered in the schemes for expansion of postal facilities. Special attention is paid to areas relatively lacking in postal facilities such as Jodhpur, Barmer, Jaisalmer, Jalore, Nagaur, Bikaner, Churu, Sriganganagar, Jhunjhunu and Sikar districts of Rajasthan State:

Barmer district, Jaisalmer district and Taranagar and Dungargarh tehsils of Churu district have been treated as 'very backward' by the Post and Telegraph Deptt, for the expansion of postal facilities. Under this policy post offices can be opened up to a loss of Rs. 1,000/- per annum per office and in exceptional cases even up to an enhanced limit of loss of Rs. 2,500/-per annum per office.

As part of normal expansion of postal facilities in the country, 903 post offices were added in these areas during the period from 1-4-61, to 30-11-68 During the same period 1,193 villages were given the facility of delivery of mails daily and 356 villages, which were receiving delivery of mails at an interval of more than a week were given better frequency of delivery.

Telecommunications schemes are normally sanctioned only if they are remunerative. But, however, with a view to progressively providing facilities in remote areas, the Department provides Public Call Offices and combined offices. (Telegraph Offices) at certain categories of stations based on administrative importance, population project importance, proximity to the border and remote areas, on limited loss basis subject to certain ceilings. Hilly and desert areas, as such, do not qualify for provision of telecommunication facilities on loss basis unless the stations in such areas fit in the present policy outlined above.

Subject to fulfilment of departmental standards and availability of funds and stores, it is proposed to open 134 post offices, 45 Public Call Offices and Telegraph Offices and one Telephone Exchange with a capacity of 600 lines during the next year in Rajasthan. It is also proposed to expand the capacity of existing telephone exchanges by 4,000 lines during the same period in Rajasthan.

Coaxial cable schemes for Beawar to Jodhpur, Jodhpur to Bikaner via Nagaur and micorwave link between New Delhi and Jaipur via Alwar are under execution. Jodhpur is expected to be linked through the coaxial system very soon.

Agricultural Farm Suratgarh and Jetsar Rajasthan

- 5157. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) the amount invested so far in Government Agricultural Farms at Suratgarh and Jetsar in Rajasthan and the number of Officers and Employees working there; and
 - (b) the commodities produced there and the annual income therefrom separately?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The amount invested by Government in the Suratgarh and Jetsar Farms up to 30.6.1967 is as follows:

Suratgarb	-	Rs.	4,95,48,933
letsar	_	Rs.	99,26,315

The number of employees at the two farms is as follows:

Class	I	-	9
Class	II	-	8
Class	Ш	-	432
Class	IV	-	178

(b) The figures of income and expenditure are not maintained commodity-wise at the farms. However, the rearly income of the two farms ever since they started is as follows:

Year	Suratgarb	Jetsar
	(in rupees)	
1956-57	4,27,523	-
1957-58	4,51,084	-
1958-59	26,12,929	-
1959-60	31,83,371	-
1960-61	41,42,827	-
1961 -62	40,78,884	-

1962-63		46,86,181	-
1963-64		46,65,098	-
1964-65		50,87,761	2,82,279
1965-66		30,68,461	2,68,710
1966-67		7 6,9 9,651	6,68,638
	Total	4,04,03,770	12,19,627

Accounts for the year 1967-68 have not yet been finalised.

Master Plan for 'Grow More Food' Campaign

- 5158. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of Food, and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether Government propose to prepare a Master Plan to lay stress on the implementation of 'grow more food' compaign on a wider scale; and
 - (b) if so, the details in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooprention (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b): A new Strategy of Agricultural Development has been adopted since 1966-67 for achieving self-sufficiency in foodgrains. The main steps taken under the New Strategy are: High Yielding Varieties Programme, Multiple Cropping, Minor Irrigation for intensive cultivation, organised provision of inputs like fertilisers and pesticides, timely and liberal credit facilities including institutional finance, farmer's education and training and intensification of research. The new Strategy has been adopted by all the States in the country to the extent feasible in the conditions and resources of each. The efforts for raising foodgrains production are proposed to be further intencified under the Fourth Five Year Plan.

Lease of Plots in Etah (U. P.)

- 5159. Shri M. A. Khan: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that the lease of plots of lands Nos. 501,506 and 304 in Village Mahadpur, Katra Pargana Sauron, District Etah, Uttar Pradesh, which was in the name of Rao Mahendra Man singh has been cancelled by the Court.
- (b) whether it is also a fact that in spite of the lease having been cancelled by the Court, Rao Mahendra Man Singh is organising Anemati fair on the said plots which is resulting in a less of lakes of rupees to the Gram Samaj; and
- (c) whether it is also a fact that the information to the said effect has been sent through a telegram and a representation to the District Magistrate and if so, the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c): The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

हरियाएगा में बूचड़लाना खोलने के विरुद्ध प्रदर्शन

5160. श्री प्रजुंन सिंह भदीरिया: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 29 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रकृत संख्या 6580 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कुंडली गांव के बूचड़खाने के विरुद्ध आन्दोलन के बारे में हरियाणा सरकार की रिपोर्ट सभापटल पर न रखने के क्या कारण हैं; और
- (ख) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों को उनके द्वारा लिखे गये पत्रों के बावजूद हरियाणा सरकार की रिपोर्ट नहीं दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री श्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) 14 मार्च 1968 को दिये गये आश्वासन को पूरा करते हुये हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी की एक प्रतिलिपि 30 अगस्त 1968 को समा पटल पर रख दी गई थी। उसी का हवाला 29 अगस्त 1968 के प्रश्न संख्या 6580 के उत्तर के माग (ख) में दिया गया है।

(ख) रिपोर्ट की प्रति मांगने के बारे में संसद सदस्यों से इस विभाग को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुये है।

मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के निर्वाचन ग्रधिवेशन

- 5161. श्री के ॰ हल्दर : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) पश्चिमी बंगाल के कांग्रेसी नेताओं ने हाल ही में मिदनापुर जिले में अनेक अधिवेशन सशस्त्र पुलिस और बेतार-यानों की सहायता से किए;
- (ख) यदि हां, तो क्या स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन अभियानों के संदर्भ में ऐसे अधिवेशनों का किया जाना उचित है ?
 - (ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की जानी प्रस्थापित है ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मु० युनुस सलीम): (क) से (ग) इस मामले में न तो इस मंत्रालय को और न निर्वाचन आयोग को ही कोई जानकारी प्राप्त है।

गांधी शताब्दी के दौरान समाज कल्याग कार्यक्रम

- 5162. श्री शिवचन्द्र भा: क्या समाज कल्याएा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार ने गांघी शताब्दी की अविध में समाज कल्याण सम्बन्धी कोई व्यापक योजना बनाई है;
 - (ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और
 - (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेगा गुह): (क) से (ग) समाज कल्याग विभाग ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना के लिये भी सुभाव दिए हैं। 1969-70 की सामान्य वार्षिक योजना के अतिरिक्त गांधी शताब्दी वर्ष के लिए कोई विशेष कल्याग योजना तैयार नहीं की गई है।

Harmful Effects of Potatos on Human Beings

- 5 63. Shri Yashwant Singh Kushwah: Will the Minister of Food and Agricelture be pleased to state:
- (a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by Dr. Peak, appearing in newspapers, to the effect that Potato is a poisionous and harmful edible commodity for human being as it contains saline;
 - (b) the reaction of Government thereto; and
- (c) the steps being taken by Government to avoid its adverse effects on the potato cultivation in the country?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b): Yes, Sir. But, perhaps, the Hon'ble Member is referring to solanine content and not saline. The solanine content of potatoes is normally not such as to cause any toxicity; the chances, if any, of toxicity are also eliminated by avoiding consumption of sprouted and immature potatoes and by proper cooking. Therefore, so far as we are aware, the potato tuber, as such, is not harmful in human dietary.

(c) Does not arise.

Agro-Based Industries

- 5164. Shrì Onkar Lal Bohra: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) the number of Agro-based industries in the country in the Co-operative Sector; and
- (b) the nature of assistance granted to them by the Central Government and the Department of Cooperation during the last five years and the number of those functioning efficiently?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) As on 30th June 1963, there were in all 1572 agricultural processing units in the cooperative sector.

(b) In order to enable the state governments to contribute to the share capital of cooperative processing units and to sanction loans for meeting block capital requirements central assistance has been provided through the National Cooperative Development Corporation to the state Governments in the form of loans. Managerial subsidy is also granted for such processing units. The National Cooperative Development Corporation has sanctioned during the last five years a sum of Rs. 24.29 crores to the state Governments.

Out of 1572 cooperative processing units organised, 1088 have been installed and the others are in various states of installation. The performance of cooperative sugar factories and other processing units which are in operation and have completed their gestation period has been generally satisfactory.

Telephone Exchange Building at Mughal Saraji

5165. Shri Nihal Singh: Will the Minister of Communications be pleased to state?

- (a) whether it is a fact that a Telephone Exchange building is being constructed at Mughal Sarai in District Varanasi;
 - (b) if so, when the building would be completed; and
 - (c) the reasons for the slow progress in this regard?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

- (b) The building work is likely to be completed by end of June, 1969.
- (c) The commencement of work was delayed due to (i) the site being water-logged and
 - (ii) some structures needing demolition.

Telegraphs Facilities to Villages and Small Towns

5166. Shri Nihal Singh: Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) whether Government propose to extend telegraph service to the villages and small towns which the common people could utilize in times of Emergency; and
- (b) if so, the population of such villages to which the said service is proposed to be extended?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b): With a view to extend telegraph service progressively to undeveloped areas it is the policy of the Government to provide telegraph facility even if such provision results in loss at certain categories of stations based on administrative importance, consideration of population, remote-ness of locality and special importance like tourist & pilgrim centres agricultural projects etc According to this policy it is permissible to provide telegraph facility at places with a population of over 5000 provided the loss in each case does not exceed Rs. 2,000/- per annum subject to a total ceiling limit laid down for the 5 year period 1966-71. Accordingly telegraph facility is being extended to villages and small towns which fulfil the requirements of this standared of population in a phased programme.

Telegraph and Telephone Facilities near Mughal Sarai

- 5167. Shri Nihal Singh: Will the Minister of Communications be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that there is no telegraph or telephone service on the road between Mughal Sarai and Chakia, a distance of 30 Kilometers and the road between Janpad, Varansi and Mirzapur; and
- (b) if so, whether Government propose to extend telephone service on both these places soon?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a): There is no telegraph or Telephone service on the road between Mughal Sarai and Chakia. However, between Varanasi and Mirzapur facilities in the shape of Public call office and combined (Telegraph) Office exist at Ramnagar and Chunar

(b) There is no proposal under consideration to provide telecommunication facility at any station between Mughalsarai and Chakia. But there is a proposal under examination in respect of Narainpur (a Block Headquarters station) between Varanasi and Mirzapur.

समाज कल्याए सम्बन्धी श्रनीयचारिक समिति

5168. श्री सिद्धय्या : क्या समाज कल्याए मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 30 अगस्त, 1968 को समाज कल्याए। सम्बन्धी अनौपचारिक समिति की बैठक में संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचि। आदिम जातियों के लियं आयुक्त को अवगत कराया गया था;
 - (ख) यदि हां, तो कब और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (ग) उसके सुभावों/सिफारिशों की क्रियान्वित के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

समाज कल्यारा विभाग में उप मंत्री (श्रीमती फूलरेरा, गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) बैठक के कुछ समय पश्चात ही उन्हें मौखिक सूचना दे दी गई थी। औपचारिक ससूचना 7-11-1968 को भेजी गई। आयुक्त ने इस संदर्भ में कुछ सुभाव या सिफारिशें नहीं भेजी हैं। अतः सरकार द्वारा तुरन्त कोई चदम उठाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

धनुसूचित जाति तथा धनुस्चित धादिम जाति धायुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों की समाध्ति

5169. श्री सिद्धय्या : क्या समाज कल्याएा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्षेत्रीय कार्यालयों को समाप्त किये जाने से पहले अनुस्चित जातियों तथा अनुस्चित आदिम जातियों के लिये आयुक्त की राय ली गई थी;
 - (ख) यदि हां, तो कब; और
 - (ग) उनके बन्द किये जाने के क्या कारण हैं?

समाज कल्याए विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती डा॰ फूलरेए गुह) :(क) हां, श्रीमान ।

- (ख) फरवरी से अप्रैल, 1967 के बीच हुई ध्रनेक बैंठकों में।
- (ग) 20 जुलाई, 1967 को लोक समा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 6163 की ओर ज्यान आकर्षित किया जाता है।

भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, इज्जत नगर

5170. श्री चं ॰ चु॰ देसाई : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि इज्जत नगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान के कुछ अनुसंघान सहायकों को अन्तिम रूप से स्वीकृति मिलने तक तदर्थ आघार पर सेलेक्शन ग्रेड दे दिया गया है;
- (ख) क्या कुछ अनुसंघान सहायक इस सेलेक्शन ग्रेड की पाने के अधिकारी 1968 में ही हो गये थे;

- (ग) क्या उन अनुसंधान सहायकों को दिया गया सेलेक्शन ग्रेड अभी तक भी निय-मित नहीं किया है; और उससे होने वाले वेतन लाभ की बकाया राशि भी उन्हें नहीं दी गई है; श्रीर
- (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा उसे कब नियमित किया जायेगा और बकाया का भुगतान किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिद्धे): (क) जी, हां।

- ं(ख) जीहां।
- (ग) न अभी तक नियमित किया गया है और नहीं कोई बकाया राशि भ्रदा की मई है।
 - (घ) यह मामला विचाराघीन है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में ध्रादिवासी युवतियों की नीलामी

- 5171. श्री नंजा गौडर : वया समाज कल्याएा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान मद्रास और मदुराई से प्रकाशित होने वाले 13 अक्टूबर, 1968 के एक तामिल दैनिक "धिनामिए।" में छपे एक लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीए। लोगों की एक भीड़ में आदिवासी युवतियों का नीलाम किया गया;
- (ख) क्या यह सच है कि सूखे के दिनों में वर्षों के लिये देवताओं को प्रसन्न करने के लिये हाल में बेलों के स्थान पर आदिवासी युवतियों को जोता जाता है; और
 - (ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिकिया है?

समाज कल्याग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेग, गुह): (क) से (ग) यह लेख, जो स्थानीय सभा से अपिरचित व्यक्ति द्वारा लिखा गया, सुनी हुई बातों पर आधारित प्रतीत होता है। ऐसे कार्यों से तथाकथित सम्बन्ध रखने वाली आदिम ज तियों तथा स्थानों के नामों का भी वर्णन नहीं किया गया है। ऐसे बयानों का सत्यापन सम्भव नहीं है।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Training Institutes

- 5172. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:
- (a) the number and percentages of employees belonging to the Scheduled Castes. Scheduled Tribes and others category-wise, in each Central Training Institute, in the country;
- (b) whether the reserved quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each Institute has been filled up as per Home Minisiry's orders; and
 - (c) if not, the action taken so far or proposed to be taken to fill the same?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation Shri S. C. Jamir): (a) to (c): Recruitment to Class III and Class IV posts in the Central Training Institutes for Instructors is made by the Principals of the Institutes themselves and the requisite information in respect of employees holding these posts, is being collected and will be placed on the table of the Lok Sabha during the next Session.

As regards Class I and Class II Gazetted posts in the Institutes, reservation is not made for the individual Institutes, as such, but for the Department of Labour and Employment as a whole.

Agricultural Produce Marketing Society, Bulandshahr

5173. Shri P. L. Barupal: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

whether it is a fact that Chai man of the Agricultural Produce Marketing Society, Bulandshahr, has tendered his resignation;

- (b) whether it is also a fact that the Assistant Agricultural Produce Marketing Officer, Meerut, has received the resignation directly from him;
- (c) whether it is also a fact that the Agricultural Produce Marketing Society has passed a resolution unanimously to the effect that the said resignation may be forwarded to it for consideration;
- (d) if so, the steps taken by Government to ensure that the said society gets the resignation letter back soon; and
- (e) the justification for the said resignation letter being received directly by the Assistant Agricultural Produce Marketing Officer?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (e): Information in this regard which was called for from the State Government of Uttar Pradesh is still awaited and will be placed on the Table of the House when received from the State Government of Uttar Pradesh.

पंजाब में दुग्ध संयंत्र

- 5174. श्री रा० कृ० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार ने पंजाब में तीन दुग्ध संयंत्र लगाने की योजना को स्वीकृति दे दी है;
 - (ख) यदि हां, तो प्रत्येक संयन्त्र पर कितना खर्चे ग्राने का अनुमान है; ग्रीर
 - (ग) क्या इसके लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी सहायता दे रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रश्नासाहिक शिन्दे) (क) से (घ) पूछी गई जानकारी पंजाब सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही समा पटन के पटन पर रख दी जाएगी।

भ्रन्दमान तथा निकंबार द्वीप समूह में स्वदेश लौटे हुए लोगों को बसाने के लिये विकास निगम

- 5175. श्री रा० कृ० सिंह : क्या श्रम तथा पुतर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार की श्रीलंका और बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों के पुनर्वास के लिये अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास निगम बनाने की योजना है; श्रीर
 - (ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?
- श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा॰ रा॰ चव्हाएए): (क) और (ख) 16 सितम्बर, 1968 को त्रिवेन्द्रम में पुनर्वास बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें अन्दमान विकास निगम बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। यह निश्चयं किया गया था कि बोर्ड की एक उप-समिति इस प्रस्ताव पर विचार करेगी भ्रीर बोर्ड के विचार के लिये विस्तृत ब्यौरा तैयार करेगी। इस विषय पर बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने के उपरांत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

भारत के खाद्य निगम का ग्राध्यक्ष

- 5176. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार ने भारत के खाद्य निगम के रिक्त ग्रध्यक्ष पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का निर्णय कर लिया है;
- (ख) यदि हां, तो क्या इस पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की पर्याप्त व्यावहारिक वाशाज्यक अनुभव प्राप्त हैं जो खाद्य व्यापार संगठन के कार्य के सुधार के लिये आवश्यक होता है; और
 - (ग) यदि नहीं, तो किस आधार पर नियुक्ति की गई है ?
- खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी, हां। श्री शाहनवाज खां को मारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- (ख) जी हां। भारत सरकार में उप-मन्त्री के पद पर एक लम्बी अविध तक कार्यं करने के अलावा श्री शाह नवाज खां कृषि विभाग में उप मंत्री के रूप में और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में अध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुके हैं। विशेषकर बाद के दो पदों पर रहते हुए उन्होंने खाद्य तथा कृषि प्रशासन सम्बन्धी पर्याप्त अनुमव तथा ज्ञान प्राप्त किया है।
 - (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा में भू-सुधार कार्य

5177. श्री किरित विक्रम देव बमन : क्या स्नाध तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) त्रिपुरा में भू-सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है;
- (ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में भू-सुधार कार्य की गति बहुत ही धीमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) त्रिपुरा में भू-सुधारों की शीघ्रता से क्रियान्वित के लिये कौन सी कार्यवाही की जा रही है और इस प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

खाद्ध, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है ग्रीर यथाशीच्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पटमोहना कोयला खान के प्रबन्धकों द्वारा श्रम ग्रधिकारी को रजिस्टर दिलाने से इन्कार करना

5178. डा॰ रानेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि पाटमोहना कोयला खान के प्रबन्धकों ने नीमनपुर श्रम प्रवर्तन अधिकारी और आसनसोल के सहायक श्रम आयुक्त को मजूरी के भुगतान आदि से सम्बन्धित स्थायी रजिस्टरों को दिखाने से मना कर दिया है;
 - (ख) कौन-कौन से रजिस्टरों को उन्होंने दिखाने से इन्कार कर दिया है; और
 - (ग) क्या प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं। प्रबन्धकों ने रिकार्ड पेश करने के लिए केवल समय मांगा और रिकार्ड निरीक्षण के लिए उपलब्ध हो गया है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को हब्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पाटमोहना कोयला खान के प्रबन्धकों द्वारा श्रीद्योगिक सम्बन्ध विभाग के साथ श्रसहयोग

5179. डा॰ रानेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि पाटमोहना कोयला खान के प्रबन्धक औद्योगिक सम्बन्ध संस्था से बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं; और
 - (ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अभ तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (५०) जी नहीं।

(ख) ऊपर (क) को हिन्दे में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्रनुस्चित जाति तथा श्रनुस्चित श्रादिम जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां 5180. श्री प्र० रं० ठाकुर: क्या समाज कल्याए। मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के मैट्रिक से ऊपर वाली कक्षाओं के उन छात्रों को कोई छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती, जिनके माता-पिता और संरक्षकों की आय सभी स्त्रोतों से 500 रुपये प्रति मास से अधिक होती है और 500 रुपये की इस अधिकतम सीमा में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के भत्ते भी सम्मिलित हैं;
- (ख) यदि हां, तो अनुसूचितं जाति/ग्रादिम जाति के आवेदक पर लागू होने वाले जीविका-साधन जांच के अन्तर्गत परिभाषित आय के स्त्रोतों का ठीक-ठीक ब्यौरा क्या है;
- (ग) अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के मामले में इस जीविका-साधन जांच में परिवर्तन न करने के क्या कारण हैं जबिक राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां योजना तथा राष्ट्रीय ऋग्ण छात्रवृत्तियां योजना के अन्तर्गत जीविका-साधन जांच को इस प्रकार से परिवर्तित किया गया है कि उसमें वेतनभोगी वर्ग की आय में दैनिक मत्ते इत्यादि सम्मिल्त नहीं होते और सैनिक क्लों में दी जाने वाली छात्रवृत्तियां के लिए भी जीविका-साधन जांच में इसी प्रकार का परिवर्तन हाल ही में किया गया है; और
- (घ) अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों पर लागू होने वाली इस कठोर जांच को 'उदार' किस हब्टि से कहा जाता है ?

समाज कल्याग विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेगा गुह): (क) हां, श्रीमान । केवल अनुसूचित जातियों के लिए । अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आजकल कोई जीविका-साधन जांच निर्धारित नहीं है ।

- (ख) 'आय' का मतलब सब स्त्रोतों से होने वाली पूर्व के वर्ष की कुल आय है, जिसमें वेतन तथा सब मत्तों सम्मिलित हैं।
- (ग) और (घ) छात्रवृत्तियां प्रदान करने की शर्तें परियोजनाओं के अनुसार मिन्न हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां/राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियां मुख्यतः गुण-आधार पर दी जाती हैं और छात्रवृत्तियों की संख्या भी सीमित है किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को दो जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या असीमित है। और किसी जीविका साधन ज च के बिना दी जाती हैं। चिकित्सा और इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का एक बार फेल होना (इस प्रयोजन के लिए) माफ कर दिया जाता है। 500 रुपये प्रति मास की उच्चतम सीमा राष्ट्रीय व्यक्तिगत आय से बहुत ऊपर निश्चित की गई है।

बिहार में मतदाता

- 5181. श्री बाल्मीकि चौघरी: क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) वर्ष 1967 के साधारण निर्वाचन की तुलना में आगामी मध्याविध मतदान के लिये बिहार में मतदाताओं की क्या संस्था है;
- (ख) इस लगमग दो वर्षों की कालाविध के दौरान मत देने के हकदार वयस्कों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) बिहार में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में मतदाताओं की सूचियों में हुई प्रतिशत वृद्धि साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में हुई प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कितनी है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम): (क) से (ग) जानकारी संगृहीत की जा रही है।

प्रधिक दूध देने वाले पशुर्यों का संरक्षण

- 5182. श्री सोताराम केसरी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:
- (क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास मंडल ने बहुत दूध देने वाले पशुओं के संरक्षण तथा दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक योजना का प्रस्ताव पेश किया है;
 - (ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और
 - (ग) क्या ऐसी ही परियोजनायें अन्य राज्यों में मी स्थापित की जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): (क) गुजरात सरकार के अवैतिनिक सलाहकार (डेरी और पशुपालन) डा० वीक कृरियन ने भारत सरकार को सूचित करते हुये गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

- (ख) प्रस्ताच का ब्यौरा निम्न प्रकार है: --
 - (1) गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य दूध के उत्पादन और विपरान का
 - (2) गुजरात और महाराष्ट्र की डेरियों में दूध की निश्चित और अधिकाधिक की पूर्ति के लिये गुजरात और महाराष्ट्र की दोनों सरकारों के लिये सबसे अधिक कारगर कदम यही होगा कि इस समस्या का समाधान सहकारिता के स्तर पर किया जाये।
 - (3) दोनों राज्यों के लिये उपयुक्त होगा कि पशु विकास और डेरी विकास की समांकलित योजना के लिये वे राष्ट्रीय डेरी विकास मंडल से परामर्प करें।
- (ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंचायत राज प्रशिक्षरा केन्द्र

- 5183, श्री सीताराम केसनी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि:
 - (क) देश में राज्यवार पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

- (ख) इस योजना के आरम्भ होने से लेकर अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है; और
- (ग) क्या कुछ राज्यों ने ये केन्द्र बन्द करने का निश्चय किया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री 'श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) से (ग) राज्यों। केन्द्र शासित क्षेत्रों से जानकारी की प्रतीक्षा है श्रीर प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिनौले के तेल के उत्पादन के लिए बिनौलों का प्रयोग

5184. श्री सीताराम केसरी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों के दौरान बिनौले के तेल का उत्पादन करने के लिये कितनी मात्रा में बिनौलों का प्रयोग किया गया?

खाद्य, कृषि. सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे): पिछले पांच वर्षों की अविध में बिनौलों की निम्नलिखित मात्रा का तेल निकाला गया है:—

वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टनों में)
1963	2.40
1964	2.95
1965	3.10
1966	5.20
1967	6.00

Allegations against Block Development Officer, Jhanjarpur (Bibar)

- 5185. Shri Lakhan Lal Kapur: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that a Member of Darbhanga District Congress Committee, Shri Misri Prasad Verma vide his letter dated the 9th April, 1968 and Shri Devendra Jha, Joint Secretary, District Praja Socialist Party vide his letter No. 2.06/67/68, dated the 1st May, 1968 had drawn the attention of the then Bihar Chief Minister towards the serious allegations against the Block Development Officer of Jhanjharpur and many Mukhias and they had demanded enquiry and action against them; and
 - (b) if so, the action taken by Government in this matter so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) and (b): Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House on receipt.

Sale of Milo in Blackmarket by a Block Development Officer in Bihar

5186. Shri Lakhan Lal Kapur: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Block Development Officer, Jhanjarpur Block, District Darbhanga, Bihar and milo from Government godown in black market as reported to by the "Searchlight" dated the 18th September, 1968 and that the said paper had demanded an enquiry by the Bihar Government into this matter;
- (b) whether it is also a fact that the Joint Secretary of the Darbhanga Praja Socialist Party had addressed letter to the Adviser to the Government of Bihar, in this connection on the 19th September, 1968; and
 - (c) if so, the action so far taken by the Government of India thereon?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (c): Information is being collected from the State Government and on receipt will be laid on the Table of the House.

राजभाषा (विद्यायी) मायोग

5187. श्री स० ग्र० ग्रगड़ी: श्रीराजधेखरन:

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अंग्रेजी कानूनों का अनुवाद करने के लिये राजभाषा (विधायी) आयोग की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा कल की गई थी;
 - (ख) इस आयोग द्वारा प्रतिवर्ष कौन-कौन से अधिनियमों का अनुवाद किया गया;
- (ग) स्थापना से अब तक प्रत्येक वर्ष आयोग पर कुल कितनी रकम खर्च की गई है;
- (घ) इस समय कातूनों के कितने पृष्ठों का अनुवाद होना शेष है तथा इसमें कितन। समय लगने और कितना व्यय होने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम): (क) राजभाषा (विधायी) आयोग का गठन, संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (6) के श्रनीन निकाले गए तारीख 27 धप्र ल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसरण में 8 जून, 1961 को किया गया था।

- (स) आयोग द्वरा हर एक वर्ष में अनूदित अधिनियमों के नाम दर्शित करने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (उपाबन्ध)। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी॰ 2791/68]
- (ग) आयोग के गठित होने से लेकर उस पर हर एक वर्ष उपगत कुल व्यय निम्ने लिखित है:---

वर्ष	रकम
1961-62	1,85,535 ₹0
1962-63	5,33,003 হ৹
1963-64	6,66,559 ₹€
1964-65	9,22,924 হত
1965-66	9,37,509 হ৹
1966-67	8,78,500 रू०
1967-68	16,74,538 ₹0
1968-69	13,04,000 रु० (ग्रायोग के बजट ग्रनुदानों में सम्मिलित उपबन्ध) ।

(घ) केन्द्रीय अधिनियमों के लगभग 11,400 पृष्ठों का अनुवाद होना बाकी है अनुवाद पूरा करने में लगभग 5 वर्ष लगेंगे। इस 5 वर्ष की कालाविध के दौरान आयोग पर सम्पूर्ण रूप में उपगत किया जाने वाला प्राक्कलित व्यय लगभग 70,00,000 रु॰ होगा।

Complaints regarding late Delivery of Telegrams and Mouey Orders in Pauri Garhwal

5188. Shri Ram Charan:

Shri J. Sunder Lal:

Shri Sharda Nand:

Will the Minister of Communications be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. '031 on the 22nd August, 1968 and state:

- (a) whether the Posts and Telegraphs Department of Uttar Pradesh have since received any complaint to the effect that telegrams, Money Orders and letters are not delivered in time in District Pauri Garhwal and are delivered as late as 20 to 25 days after: and
 - (b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard 7

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) No.

(b) Does not arise.

Lack of Postal Stationery in Delchouri Post Office, Pauri Garhwal

5189. Shri Ram Charan:

Shri J. Sunder Lal:

Shri Sharda Nand 1

Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that envelopes, stamps, inland letters and postcards are not available for months together in Delchcuri Post Office of Pauri Garhwal; and
 - (b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard 7

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) No.

(b) Does not arise.

Conversion of Delchouri (Pauri Garhwal) Branch Post Office into Sub-Post Office

*5190. Shri Ram Charan:

Shri J. Sunder Lat:

Shri Sharda Nand:

Will the Minister of Communications be pleased to state:

- (a) whether Government propose to convert Delchouri Branch Post Office of Pauri-Garhwal into Sub-Post Office because this Post Office is the centre of many patties; and
 - (b) if so, by when and if not, the reasons therefor and complete details thereof?

The Minister of State in the Department for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b): Branch Post Offices are upgraded into sub post offices provided departmental standards on the minimum work hours and maximum permissible limit of loss on upgrading are fulfilled. No proposal for upgrading Delchouri Branch Office into a sub post office had been received so far. Its case for upgrading will be taken up for examination.

दिल्ली की श्रौद्योगिक प्रशिक्षरा संस्थाश्रों में श्राश्-लिपि पाठ्यक्रम के लिये दाखिला

- 5191. श्री वेखी शंकर शर्मा: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि दिल्ली की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थायों में, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा जारी किये गये तथा विशेषज्ञ समिति अर्थात् राष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्वीकार किये गये नियमों के अनुसार देखिये ज्ञापन संख्या एन०सी०टी०-33(17)/61-62 दिनांक 15 मार्च. 1963 (परिशिष्ट 11)-आशुलिपि पाट्यक्रम में दाखिला नहीं दिया जा रहा है; और
 - (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर): (क) और (ख) 1963 में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आणुलिपि पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। जिसके अधीन पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों की पूर्व-प्रवेश लिखित परीक्षा ली गई थी। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की पूर्व-प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने में प्रशासनिक कठिनाइया पैदा होती थीं अतः दिल्ली प्रशासन ने रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा निर्धारित सिद्धान्त के लक्ष्य और प्रयोजन हो ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को बाद में परिशोधित कर दिया।

श्राशु-लिपि प्रशिक्षकों की पदोन्नति

- 5192. श्री वेणी शंकर शर्मा: क्या श्रम तथा पुनर्वांस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या ५ ह सच है कि दिल्ली की विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नियुक्त आशुलिपि प्रशिक्षकों के लिये पदोन्नति के कोई साधन नहीं हैं तथा जिन्होंने 6 से 8 वर्ष की सेवा पूरी करली है उन्हें भी अब तक पदोन्नत नहीं किया गया है;
- (ख) क्या अन्य व्यवसायों के प्रशिक्षकों को उच्चतर वेतनक्रम में सुपरवाइजर इन्स्ट्रक्टर और फोरमैन इन्स्ट्रक्टरों के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है;
- (ग) यदि हां, तो दिल्ली की विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले आशुलिपि व्यवसाय के प्रशिक्षकों को लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं;
- (घ) क्या आशुलिपि प्रशिक्षकों के लिये पदोन्नित के साधनों के बारे में सरकार विचार कर रही है; और
 - (ङ) यदि हां, तो उनके ध्रगले पद का वेतनमान क्या होगा ?

श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स॰ चु॰ जनीर): (क) जी नहीं। दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में काम कर रहे आशुलिपि अनुदेशकों के लिये पदोन्नित का एक माध्यम उपलब्ध हैं। बहरहाल इस व्यवसाय में कुछ अनुदेशकों ने 6 से 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और वे अभी तक पदोन्नत नहीं किये गये हैं।

- (ख) जीहां।
- (ग) से (ङ) पदोन्नित के प्रयोजन के लिए, रुपये 210-425 के वेतनक्रम में आजु-लिप अनुदेशकों को इतर-तकनीकी कर्मचारी होने के कारण, वेतनक्रम रुपये 180-280 और रुपये 210-380 में इंजीनियरिंग और इतर-इंजीनियरिंग व्यवसाय के दूसरे अनुदेशकों के साथ, संयोजित नहीं किया गया है। किन्तु आशुलिप अनुदेशकों के लिए दिल्ली प्रशासन के अधीन लिपिक-वर्गीय सेवा ग्रेड-1 में रुपये 210-530 और रुपये 350-25-575 के वेतनक्रम में आशुलिप के पद पर पदोन्नत होने का माध्यम मौजूद है।

दिल्ली के रोजगार केन्द्रों के माध्यम से मरे गये स्टेनोग्राफरों के पव

- 5193. श्री वेशी शंकर शर्माः क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) दिल्ली में गैर-सरकारी तथा सरकारी कार्यालयों ने वर्ष 1965-66;1966-67 तथा 1967-68 में वर्षवार तथा श्रेणीवार स्टेनो-टाइपिस्टों/जूनियर स्टेनोग्राफरों तथा सीनि- यर स्टेनोग्राफरों के पदों के लिये कितने रिक्त स्थानों की सूचना स्थानीय रोजगार केन्द्रों को दी; और
- (ख) उपयुंक्त श्रीणयों की प्रत्येक श्रीणी में उपयुंक्त वर्षों में कितने कितने रिक्त स्थान दिल्ली रोजगार केन्द्रों के माध्यम से भरे गये ?

भम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स॰ चु॰ जमीर): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 2792/68]

ग्रीद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाग्रों के ग्रध्यापकों को दीर्घावकाश का लाभ

- 5194. श्री वेग्गी शंकर शर्माः क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि दिल्ली पोलिटेकनिक्स के दो वर्षीय पाठ्यक्रम की शिक्षा देने वाले अध्यापकों को प्रतिवर्ष ग्रीष्टमकालीन तथा शीतकालीन छुट्टियां भिलती हैं जबकि दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को ये छुट्टियां नहीं मिलती हैं यद्यपि ये दोनों संस्थाएं दिल्ली प्रशासन के नियन्त्रणाधीन हैं और दोनों के पाठ्यक्रमों की अवधि एक समान है; और
 - (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर): (क) ग्रीर (ख) पोलिटेकनिवस में काम करने वाले कर्मचारियों पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये नियम लागू होते हैं जिनके अनुसार उन्हें ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन छुट्टियां मिल सकती हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर श्रम, नियोजन एवं पुनर्वास मंत्रालय द्वारा बनाये नियम लागू होते हैं जिनके अनुसार नियमाधीन अवकास उन्हें मिल सकता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उद्देश्य दस्तकारी का प्रशिक्षण देना है जिसमें प्रत्येक व्यवसाय के लिए निर्धारित अल्पकालिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणियों को गहन पाठचर्या का बिना रोक-टोक प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। अतः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणिथयों को कारखाने जैसे वातावरण में काम करना पड़ता है और उनके प्रशिक्षण का एक बड़ा भाग श्रमालय (शाप पलोर) में होता है। इसलिये दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन छुट्टियों की ब्यवस्था नहीं की गई है।

नई दिल्ली स्थित कालकाजी बस्ती में कार्य करने के लिये भारत सेवक समाज को संविदा

- 5195. श्री प्र० रं ठाकुर : क्या श्रम तथा पुनर्जास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या यह सच है कि जुलाई 1962 में मारत सेवक समाज को कालकाजी नई दिल्ली के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित बस्ती की भूमि को समतल आदि करने का ठेका दिया गया था;
- (ख) यदि हां, तो सरकार ने इस ठेके को रह किये जाने से पूर्व और बाद इस संस्था को कुल मिलाकर कितना धन दिया;
 - (ग) क्या बस्ती के विकास के लिये इस घन को अनावश्यक समक्ता गया है;

- (घ) यदि हां, तो क्या इस घन को बस्ती के विकास के लिये किये गये कुल व्यय में से घटा दिया गया है ताकि वास्तविक विकास व्यय का हिसाब लगाया जा सके और उसके अनुसार ही राशि अलाटियों से वसूल की जा सके; और
 - (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारगा हैं?
- श्रम, रोजगार तथा पुनर्वांस मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीदा० रा० चव्हारा): (क) जी, हां।
- (ख) मारत सेवक समाज को दिये गये 5.73 लाख रुपये की राशि के कार्य में से समाज ने लगभग 2.32 लाख रुपये का कार्य ही किया था। समाज को अदा की गई वास्तविक राशि केवल 2,32,072 रुपये थी।
 - (ग) जी, नहीं।
 - (घं) प्रश्न नहीं उठता।
- (ङ) चूं कि समाज को दी गई राशि बस्ती में किये गये विकास कार्य के मूल्य का निरूप्त करती है इसलिये बस्ती पर किये गये कुल विकास व्यय में से इस राशि को निकालने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

भौद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दिल्ली के कर्मचारियों के लिये क्वाटर

- 5196. श्री वेएगी शंकर शर्मा: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के नियंत्रणाधीन काम करने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के कर्मचारियों के लिये क्वाटर बनाने के हेतु नई दिल्ली की सनलाइट कालोनी में एक प्लाट नियत किया गया है;
 - (ख) यदि हां, तो कितने क्वाटर बनाने का विचार है; और
 - (ग) वे क्वाटर कर्पचारियों को दिये जाने के लिये कब तक तैयार हो जायेगी ?
- श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स॰ चु॰ जमीर): (क) जी हां।
 - (ख) अड़सठ।
 - (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्वाटर बन जाने की संभावना है।

Import of Tapioca into Pondichery from Kerala

- 5196.-A. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether Government are aware that licences were issued to some parties for importing Tapioca into Pondicherry from Kerala at the instance of the erstwhile Minister of Public Works Department in Pondicherry;

- (b) whether it is a fact that Tapioca imported from Mahe for Pondicherry did not reach Pondicherry but was disposed of at Salem itself in the blackmarket;
- (c) whether it is a fact that when the Chief Secretary of Kerala Government was apprised of the said blackmarketing he wrote to the Government of Pondicherry to cancel the said licences and consequently Shri Mamak, the Secretary of the Civil Supply Department wrote to the erstwhile Development Minister, Shri Sanmugham that since the permit in question was issued in accordance with the order of D.M., the letter of Kerala Government for cancellation of licences should therefore be seen by the D. M.; and
 - (d) if so, whether Government would institute an enquiry into the whole affair ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d): Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का ओर ध्यान दिलाना CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम बंगाल में निर्वाचन समाप्तों में नाडबड

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल): श्रीमान, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:

"पश्चिम बंगाल में निर्वाचन सभाग्रों में गडबड ग्रीर पत्थरों फेंका का जाना।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हारा): सरकार को यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि 9 दिसम्बर 1968 को जब श्री हुमायून किबर मिदनापुर के ओल्ड जेल मैदान में हुई चुनाव समा में भाषण दे रहे थे तो कुछ गुण्डों ने हुँउस सभा में विस्फोटक पदार्थ फेंक कर गड़बड़ पैदा कर दी। जब श्री हुमायून किबर भाषण दे रहे थे तो उनके निकट एक पटाखा फटा और उनके मुंह पर चोट आयी और खून बहने लगा। तब उन्हें मिदनापुर अस्पताल में दाखिल किया गया तथा बाद में कलकत्ता के एक ग्रस्पताल में ले जाया गया। मारतीय विस्फोटक-पदार्थ अधिनियम की घारा 6 (3) तथा मारतीय दंड संहिता की घारा 148, 149, 326 और 307 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इस मामले की जांच की जा रही है।

ऐसा मी पता लगा है कि कुछ अन्य सभाओं में मी गड़बड़ की गई थी। अग्रेतर ब्यौरा राज्य सरकार से प्राप्त किया जा रहा है।

आगामी आम चुनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न राजनीतिक दलीं द्वारा की जाने वाली समाओं में गड़बड़ पैदा करने के ऐसे प्रयासों की सरकार कड़ी निन्दा करती है। ऐसे सभी

प्रयासों को कुवलने के लिये सरकार दृढ़ संकल्प है। वह बंगाल तथा अन्य राज्यों में निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रूप से चुनाव कराने के लिये हर सम्भव कार्यवाही करेगी। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे सामान्य राजनीति जीवन को प्रस्तव्यस्त करने के ऐसे प्रयासों की वह दिल से निन्दा करें तथा निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से चुनाव सम्पन्न करने के लिये शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखने वे लिये राज्य के अधिकारियों को पूर्णकृप से सह-योग दें।

श्री क० प्र० सिंह देव: एक ऐसा समय था जब बंगाल में देशभक्त पैदा हुआ करते थे परन्तु आज वह एक ऐसा स्थान बन गया है जहां ऐसे लोग हैं जिन्हें सविधान के प्रति कोई आदर नहीं है। ऐसे तत्व लोगों को अपने माषण तथा अभिव्यक्ति के मूलभूत अधिकार का प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं। अतः मैं गृह-मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है?

श्री यशवन्त राव चन्हागः मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे मकता क्योंकि इस सारे मामले की जांच की जा रही है। मैं इस समय किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे खराबी हो सकती है। इसके साथ ही साथ मैं सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना करूंगा कि वे शान्तिपूर्ण चुनाव के लिये आवश्यक वातावरण बनाये रखे।

श्री कि प्रविह देव: माननीय मंत्री ने मेरा प्रश्न ध्यान से नहीं सुना है। मैं जानना चाहता था कि क्या मंत्री महोदय ने इस बात का पता लगाया है कि बंगाल में कुछ लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चन्हारा: कुछ चीजें स्पष्ट ही होती हैं जिनका पता लगाने की कोई श्रावश्यकता नहीं होती ।

श्री समर गुह् (कन्टाई): मैं सभी राजनीतिक दलों को, विशेषकर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दलों को चेतावनी देता हूं कि यदि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसात्मक घटनायें होती रही तो मध्याविध चुनाव सम्पन्न करने में बड़ी बाधा पड़ेगी। उन्हें रोकना प्रत्येक राजनीतिक दल का कर्त्तं व्य है।

भ्रष्यक्ष महोदय: गृह कार्य मंत्री ने भी यही कहा हैं इसे दुहराने की क्या आव-श्यकता है।

श्रीसमर गुह: मैं यह विरोधी दल की ओर से कह रहा हूं।

श्री बलराज मधीक (दक्षिण दिल्ली): इन लोगों के चिल्लाने से पता चलता है कि यह सब कुछ इन्होंने ही करवाया है।

श्री जि॰ मो॰ बिस्वास (बांकुरा): हम ने तो श्री मधोक को कटक में देखा था। हम ने वहां देखा था कि उन्होंने अल्पसंख्यक लोगों की सम्पत्ति कैसे लूटी थी। रांची में उन्होंने बहुत से लोगों को मारा है। हमें धर्म आती है कि वे लोग इस समा में हमारे साथ है।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore): By the Speeches made by these people in Calcutta it appears that these things are taking place on account of Jan Sangh. I think an enquiry should be made in this regard.

श्राध्यक्ष महोदय: किसी व्यक्ति अथवा किसी दल का नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री समर गुह: कुछ दिन पहले मार्क्सवादी साम्यवादी दल के एक प्रमुख सदस्य श्री हरिकृष्णा ने राज्यपाल से शिकायत की थी कि जब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से गाड़ी में हावड़ा जा रहे थे तो कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें धम ही दी थी। इसी प्रकार कुछ दिन पहले जब पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री पी० सी० सेन बर्दबान जिले में चुनाव सभा में भाषण देकर वायस आ रहे थे तो उनकी कार पर पत्थर फैंके गये और वह घायल हो गये। वैसे ही बांरानगर में सी० पी० एम० के एक व्यक्ति की छूरा मारा गया था। इन सब बातों को देखते हुयं मैं पश्चिम बंगाल के सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही का जवाब हिंसात्मक कार्यवाही में दिया जायेगा। जिससे पश्चिम बंगाल में लोकतन्त्रात्मक ढ़ंग से चुनाव नहीं हो सकेंगे। अतः मैं गृह मन्त्री से पूछता चाहता हूं कि यदि सार्वजनिक सभा में किसी राजनीतिक दल द्वार। कोई हिसात्नक कार्यवाही की गई तो क्या वह उसके लिये कड़ी कार्यवाही करेंगे क्योंकि वे लोग लोकतन्त्र के शत्रु हैं।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करेगी। साथ ही साथ मैं यह भी चानना चाहता हूं कि यदि न्यायालय में यह सिद्ध हो जाये कि एक दल ने दूसरे दल के इश्तिहार फाड़ लिये है अववा दूसरे दल की चुनाव सभा में गड़बड पैदा की है अथवा दूसरे दल के किसी सदस्य को धनकी दी है तो क्या सरकार उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी ग्रीर उसके चुनाव को अवंध घोषित करेगी।

श्री यशवन्त राव चव्हाएा: जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है मैं पहले ही कह चुका हं कि इस मामले में कड़ी कार्यवाही करने का विचार है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है यह सुभाव तो विशेष कार्यवाही करने के लिये है।

श्री रा० बदग्रा (जोरहाट): यह एक बात तो निश्चित ही है कि इस देश की लोक-तंत्रात्मक प्रक्रिय को अस्तव्यस्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्री हमायूं क आहर के अलावा कई अन्य व्यक्तियों पर भी हमला किया गया है। एक अथवा दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। अतः मैं यह जानना चाहता हं कि ऐसे कौन से राजनीतिक दल है जिन्होंने ऐसी कार्यवाही न करने की घोषणा की है ?

श्री यद्मावन्त राव चव्हारा: मैंने स्वयं कहा है कि मैं ऐसी घटनाओं की निन्दा करता हं इसके साय ही साथ मैं अन्य राजनीतिक दलों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे भी ऐसी घटनाओं की निन्दा करें।

श्री चपला कान्त मट्टाचार्य (रायगंज): माननीय गृह मन्त्री ने अपने वक्तव्य में श्री हुमायूंन कबिर का उल्लेख किया था। मैं उनके बारे में सही स्थित बताना चाहता हूं। श्री हुमायून किवर के साथ तीन अन्य व्यक्तियों को भी गहरी चोट आई थी। उनमें से श्री पी॰

सी० सेन तो अब भी बुखार से पीड़ित है। माननीय गृह मन्त्री को इस सारे मामले का पता लगाना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन है कि अब तो उम्मीदवारों पर चुनाव समाओं में केवल हमला ही किया जाता है फिर चुनाव आने पर मतदाताओं को धमकी दी जायेगी और उसके बाद मत पेटियों को नष्ट कर दिया जायेगा। कलकत्ता में पहले ही ऐसे इश्तिहार लगाये जा चुके हैं कि चुनाव नहीं होने दिये जाने चाहिये। यह कार्यवाही ऐसे दलों द्वारा की जा रही हैं जिनको चुनाव में विजय प्राप्त होने की शंका है। अतः हमें ऐसी सब बातों से सावधान रहना चाहिये।

श्री जि॰ मो॰ बिस्वास: आशंका तो माननीय सदस्य के दल को है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्वर); श्री अतुल्य घोष के निर्देश पर मैसर्स खैतान ब्रादर्स को एक लाख ऐसी मतदान पेटियां बनाने का ठेका दिया गया है जिनमें आसानी से हेराफेरी की जा सके।

ग्रध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं। उन्हें अब अन्य सदस्यों को भी बोलने का ग्रवसर देना चाहिये।

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य: मुक्ते श्रीमती रामादेवी का तार आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पौली बर्धवान में जानबूक्त कर घातक हमला किया गया है जिसमें मेरे समेत लगभग कांग्रेस के चालीस कार्यकर्त्ता घायल हो गये हैं तथा पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अतः श्राप तुरन्त हिदायतें भेजे अतः चुनाव होना सम्भव नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि चुनाव सभाएं शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मतदान पेटियों आदि की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हारा: यह बड़े दुख की बात है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री पी० सी० सेन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी छोड़ा नहीं गया है और उन पर भी प्रहार किया गया है। इन सभी मामलों की जांच की जा रही है। हम हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं कि चुनाव समार्थे शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न की जा मके। परन्तु इसके लिये हमें सभी राजनीतिक दलों के सहयोग की जरुरत है।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) यदि उन्हें सभी दलों का सहयोग प्राप्त हो जाये तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री यद्यवन्तराव चव्हारा: माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। मुक्ते उनका सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। यही काररा है कि मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं।

डा॰ सुशीला नैयर (फासी): उन्हें उनका सहयोग कभी नहीं मिलेगा।

भी यशवन्तराव चव्हारा: तब हम देखेंगे कि चुनाव के दौरान शान्ति बनी रहे।

मतदान केन्द्रों पर शांति बनाये रखने का काम हमने चलती फिरती पुलिस को सौंप दिया है। हम हर सम्भव प्रयत्न करेंगे कि मत पेटियों में हेरफेर न हो।

सभा पटल पर रखे गये पत्र PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तार-यंत्र ग्रधिनियम श्रादि के श्रन्तर्गत श्रधिसूचना

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भ्रन्ता-शाहिब शिन्दे): श्री इ० कु० गुजराल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:--

- (एक) मारतीय तार-यन्त्र अधिनियम, 1885 की घारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत मारतीय तार-यन्त्र (आठवां संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 9 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1961 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1962 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या-एल० टी० 2769/68]

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य की समीक्षा तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्ना-शाहिब शिन्दे): श्री प्र० च० सेठी की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

- (एक) वर्ष 1967-68 के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पिएायां। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2770/68]

उड़ीसा चावल (वहन नियम्त्रण) संशोधन प्रादेश

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्ता-शाहिब शिन्दे): मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के षन्तर्गत उड़ीसा चावल (वहन नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2140 में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2771/68]

धातुयुक्त खानें (संशोधन) विनियम, कोयला खानें विनियम ग्रादि के ग्रन्तर्गत ग्रधिसूचनार्ये

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्रीं (श्री स॰ चु॰ जमीर) : मैं निम्त-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

- (1) (एक) खान ग्रधिनियम, 1952 की घारा 59 की उप-घारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—
 - (क) घातुयुक्त खानें (संशोधन) विनियम, 1968, जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1555 में प्रकाशित हुए थे।
 - (ख) कोयला खानें (दूसरा संशोधन) विनियम, 1968, जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के मारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1556 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1968 के मारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2168 में प्रकाशित हुआ था।
 - (ग) कोयला खानें (तीसरा संशोधन) विनियम, 1968, जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1558 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2169 में प्रकाशित हुआ था।
 - (दो) उपयुंक्त अधिसूचनाओं को समा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी॰-2772/68]
- (2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की घारा 95 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) चौथा संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2113 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2773/68]

- (3) 27 सितम्बर, 1968 को नार्थ सालनपुर खान में घातक दुर्घटना सम्बन्धी जांच रिपोर्ट की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल॰ टी॰-2774/68]
- (4) जेनेवा में जून, 1968 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 52 वें सत्र में भारत सरकार के प्रतिनिधि-मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2775/68]

ग्रत्यावश्यक वस्तु ग्रिधिनियम ग्रादि के ग्रन्तगंत ग्रिधिसूचनायें

वाशिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शकी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्रों का एक-एक प्रति सभा-पदल पर रखता हूं।

- (1) ध्रत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की घारा 3 की उप-घारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—
- (एक) सूती कपड़ा (नियन्त्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4138 में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) सूती कपड़ा (नियन्त्रण) पांचवां संशोधन, आदेश, 1968, जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के मारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ग्रो० 4139 में प्रकाशित हुओ था । [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2776/68]
- (2) इलायची बोर्ड के वर्ष 1967-68 के कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।
- (3) रबड़ बोर्ड की वर्ष 1967-68 की गतिविधियों पर वार्षिक प्रातवेदन की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2777/68]

संसदीय ग्रीर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन ग्रादेश में कतिपय शुद्धियां ग्रीर संशोधन करने वाली भारत के राजपत्र में प्रकाशित ग्रिषस्चनायें

विधि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मु॰ यूनस सलीम): मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति समा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2778/68]

(एक) एस० ओ॰ 4303 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के मारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा गोवा, दमन ग्रीर दीव संघ राज्य क्षेत्र सम्बन्धी संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 में कतिपय शुद्धियां तथा संशोधन किये गये।

(दो) एस॰ ओ॰ 4306 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य सम्बन्धी ससदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 में कतिपय शुद्धियां तथा संशोधन किये गये।

विधेयक पर राय OPINIONS ON PRICE

श्री श्र० त्रि० शर्मा (मंननगर) : मैं एक पत्र समा-पटल पर रखता हूं जिसमें मारत के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् के गठन, सम्पूर्ण मारत के लिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सा रिष्ट्र रखने तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, जो समा के निदेश से 9 अगस्त, 1968 को इस पर राय जानने के लिए परिचालित किया गया था, रायें दी गई हैं।

याचिका समिति committee on peritions

कार्यवाही सारांश

श्री स॰ च॰ सामन्त (तामलुक) : मैं याचिका समिति की 37 वीं से 42 वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव:--- मुक्ते राज्य समा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :--

(एक) कि लोक समा द्वारा 10 दिसम्बर, 1968 को पास किये गये खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1968 से राज्य सभा भ्रपनी 17 दिसम्बर, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है। (दो) कि लोक समा द्वारा 9 दिसम्बर, 1968 को पास किये गये बीमा (सशोधन) विधेयक 1968 से राज्य समा अपनी 17 दिसम्बर, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

प्राक्कलन समिति ESITIMATES COMMITTEE

63 वां प्रतिवेदन

श्री पें० बेंकटा सुब्बया (नन्दपाल): मैं वित्त मन्त्रालय-विदेशी सहायता का उपयोग के बारे में प्राक्कलन सिमिति के 11 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन सिमिति का 63 वां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

याचिका समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री स॰ घ॰ सामन्त (तामलुक): मैं याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन पुरस्थापित करता हं।

साध्य

भी स॰ च॰ सामन्त (नामलुक) : मैं याचिका समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति समा-पटल पर रखता है।

रुस के शिष्ट मण्डल की यात्रा के बारे में वक्तव्य STATEMENT RE: VISIT OF SOVIET DELEGATION

भौद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फलरहीन भ्रली भ्रहमद): मैं इस्त की वैदेशिक आर्थिक सम्बन्धों के लिए राज्य समिति के सभापति, श्री स्वचकीव के नेतृत्व में इस के शिष्टमण्डल की यात्रा के बारे में वक्तव्य समा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2779/68]

नियम ³⁷⁷ के अन्तर्गत मामला MATTER UNDER RULE 377

श्री ही० ना॰ मुकर्जी (कलकता-उत्तर पूर्व): मैं आपकी अनुमित से अत्यावश्यक सेवाएं संघारण विध्यक के तीसरे वाचन के दौरान हुई घटना के लिए नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठा रहा हूँ। कल की घटनाओं का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। टाइम्स आफ इन्डिया ने लिखा है कि संसद कार्य मन्त्री तथा उपाध्यक्ष के बीच गर्मागर्मी हुई। परन्तु पेट्रियट ने अधिक सख्त शब्दों का प्रयोग का लिखा है कि संसद कार्य मन्त्री डा० राम सुमग सिंह तथा उपाध्यक्ष महोदय जो कि पीठासीन थे के बीच मुठभेड़ हुई।

जिस समय यह घटना घटी मैं समा में उपस्थित था। संसद कार्य मन्त्री ने जिनके उपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, कहा था कि 'आप प्रतिदिन अध्यक्ष के विनिर्णय में परिवर्तन कर देते हैं। हमें निर्धारित समय-सीमा पर दृढ़ रहना चाहिए। यदि हम इस अवस्था पर 'मुख बन्द' लागू करते है तो यह उचित नहीं होगा। मैं इस अवस्था में 'मुख बन्द' लागू नहीं करूंगा।

धी रगाधीर सिंह (रोहतक) : डा० रामसिंह ने जो कुछ कहा था वह ठीक था।

श्री ही । ना । मुकर्जी: डा । राम सुमग सिंह ने उपाध्यक्ष महोदय से आगे कहा कि इसमें क्या गलत है ? तब हमें समापन प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा।

उपाघ्यक्ष महोदय ने तब उत्तर दिया था कि मुभे कोई आपती नहीं है। मैं इस अवस्था में वाद-विवाद बन्द नहीं करूंगा। तत्परचात् डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि आप निर्धारित समय-सीमा का पालन करें। इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि क्या इस अवस्था में 'मुख-बन्द' लागू करना उचित है। उन्होंने यह भी कहा कि वह 'मुख-बन्द' लागू नहीं करेंगे।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उपाध्यक्ष महोदय तीसरे वाचन की अवस्था पर 'मुख-बन्द' लागू करने को तैयार नहीं थे और वह आधे घंटे के लगभग समय बढ़ाने को तैयार थे । मेरी भावना है कि सरकार में बहुमत की शक्ति है परन्तु उसे इस देव की शक्ति का प्रयोग करते सम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

ग्राध्यक्ष महोदय : श्री मुकर्जी द्वारा असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है । इसमें उत्ते जित होने की कोई बात नहीं है ।

श्री ही । ना अपकर्जी : मैं केवल यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि संसद – कार्य मन्त्री के मेरे विचार में ऐसी बात कही जिससे पीठासीन का अपमान होता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि तीसरे वाचन के समय गृह-कार्य मन्त्री भी उपस्थित थे और श्री स॰ मो॰ बनर्जी ने कहा था कि ''मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह-कार्य मन्त्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे क्योंकि वह इस समय समा में उपस्थित हैं। उस पर श्री चव्हाण ने कहा था कि "निश्चय ही मैं उत्तर देने को तैयार हूँ।" तब फिर अन्त में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य मन्त्री श्री शुक्ला को बुलाया गया था। इस पर श्री श्रीवास्तव नायर ने कहा था कि हमें आश्वासन दिया गया था कि गृह—कार्य मन्त्री उत्तर देंगे। इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि 'यह उचित नहीं है। मैं किसी को बुला सकता हूं। इसको मामला मत बनाइये। इस पर श्री कान्तन नायर ने फिर कहा कि इसके पीछे श्री चव्हाए। का ही दिमाग है। उन्हें ही उत्तर देना चाहिए। इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने केवल इतना कहा कि ''मैंने श्री शुक्ला को बुलाया है। गृह—कार्य मन्त्री यहां है। यदि वह चाहें तो अन्त में कुछ जब्द इसमें शामिल कर सकते हैं।

मेरा कहना यह है कि जब सभा में इस प्रकार का मामला हो जिसके लिए बार-बार समय बढ़ाना पड़ा हो, तो यदि सम्बन्धित मन्त्री सभा में उपस्थित हों तो उनको ही उत्तर देना चाहिए। परन्तु गृह-कार्य मन्त्री कल उपस्थित थे परन्तु उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर नहीं दिया। इससे समाचार 'इन्डियन एक्सप्र स ने लिखा है कि श्री चन्हाण कुछ असन्तुष्ट थे। इस देश की संसदीय परम्पराओं के लिए यह एक बुरी बात है। मुफे आशा है कि आप इस बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे।

प्रध्यक्ष महोदय: मैंने भी समाचार पत्रों को पढ़ा है। एक बार नहीं बिल्क इसके लिये दो बार समय बढ़ाना पड़ा था। इससे ससद कार्य मन्त्री पर भी बोभ पड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति सनाव की स्थित से गुजरा है। अतः मैं नहीं चाहता कि अब जबिक विधेयक पास हो गया है गलतफहमी बनी रहे। सायंकाल आठ बजे भी गृह-कार्य मन्त्री उपस्थित थे श्रीर उन्होंने आधे घंटे की चर्चा का उत्तर भी दिया था। सभी इस बात से संतुष्ट थे कि उन्होंने अच्छा उत्तर दिया है। कभी-कभी सभी उत्ते जितं हो जाते है। हम सब मानव हैं। अतः गांधीजी के प्रारा त्यागने के स्थान के बारे में एक बात उठायी गई थी वया माननीय मन्त्री इस बारे में कुछ कह रहे है?

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): माननीय सदस्य ने कार्यवाही की अशुद्ध प्रति से कल वाक्य पढ़कर सुनाये हैं। मैं नहीं जानता कि इस में कुछ आपत्तिजनक है। स्वयं उपाध्यक्ष महोदय ने मुभे बार-बार कहा कि वाद-विवाद को कम किया जाना चाहिए। परन्तु जब वह पीठासीन हुए तो उन्होंने समय बढ़ाने को ठीक समभा। हम सब ने वचन दिया था कि विधेयक के लिए 7 घंटे का समय अलाट किया जाये परन्तु जैसाकि स्वयं आपने कहा यह वाद-विवाद 34 घन्टे तक चला।

भी स॰ मो॰ बनर्जी (कानपुर): 34 घन्टे नहीं 24 घन्टे।

हा॰ राम सुभग सिंह: मैं इसे स्वीकार करता हूं। किसी भी ईमानदार प्रेसमैन को अपने समाचार ऐसी रिपोर्टी पर आधारित नहीं रखने चाहिए और नहीं किसी माननीय सदस्य को ऐसे तुच्छ मामले समा में उठाने चाहिए। (ग्रन्तर्वाधायें)।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हारा) : मैं कभी भी नाराज नहीं था। यही एक मूल नियम मैंने इस सभा में सीखा है। मैंने यही ठीक समभा कि जिस मन्त्री ने यह विधेयक बनाया है वही इस पर हुए वाद-विवाद का उत्तर थें। यही कारण है कि मैंने वाद-विवाद का उत्तर नहीं दिया। मैंने उपाध्यक्ष महोदय को एक नोट दिया था जिसमें मैंने बताया था कि यदि मैं वाद-विवाद का उत्तर देता हूँ तो यह मेरे साथ के प्रति उचित नहीं होगा। मैं तभी हस्तक्षेप करूं गा यदि मेरे साथी चाहें।

श्री मुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : माननीय संसद कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि उपाध्यक्ष महोदय ने उन्होंने निजीक्प से समय निर्धारित करने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि चर्चा हो रही है और हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। परन्तु पीठासीन ने एक अलग तरीके से व्यवहार किया। यह बहुत बारचर्यजनक है।

श्री हेम बरुश्रा (मंगलदायी): क्या मैं यह निवेदन करूं कि उपाध्यक्ष महोदय को, जिनके विरूद्ध गम्भीर आरोप हैं, त्याग पत्र देना चाहिए ?

भारतोय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

भी तन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्) ! मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"िक यह सभा मारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन करने तथा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय बजट सन्न (1969) के अन्तिम दिन तक बढ़ाये।"

म्राध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"िक यह सभा मारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर सिमित का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय बजट सत्र (1969) के अन्तिम दिन तक बढ़ाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा The Motion was adopted

महात्मा गान्धी की मृत्यु के बारे में RE: DEATH OF MAHATMA GANDHI

श्रध्यक्ष महोदय: समाचार पत्रों में इस बारे में मतभेद उठ खड़ा हुआ है कि महातमा गांघी की मृत्यु बिड़ला हाउस के बाग में अथवा भवन के अन्दर हुई थी। कुछ सदस्य पहले ही अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं। मैं इस समय उसकी अनुमित नहीं दे रहा हूं। इस अस्वस्थ मतभेद को सभा के समक्ष नहीं लाना चाहिए।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में RE. QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Rabi Ray (Puri): In a judgement which has appeared in the papers it is said that Shri Madhu Limaye has been kept in jail illegally. He can not attend the meetings of the House for this illegal imprisonment. I want to quote the judgement of justice Grover.

श्रध्यक्ष महोदय: मैं ने गृह कार्य मन्त्री को वक्तब्य देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद वह इस पर विचार करेंगे। हमने सभा में जो प्रक्रिया बनाई हुई है हम उसका अनुपरण करेंगे।

Shri Rabi Ray: It should be done before the House is adjourned to-morrow.

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि क्या यह सम्भव होगा। कल इस मत का अन्तिम दिन है। मैं नहीं समक्षता कि निर्णय की प्रति प्राप्त करना, उस पर वक्तव्य देना तथा फिर उस पर चर्चा करना कल सम्भव होगा। मैं ने तथा गृह- कार्य मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि वह इसको पहेंगे।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याहन भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थिगत हुई। The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fouteen of the clock.

लोक समा मध्याहन भोजन के पश्चात 2 बजकर सात मिनट पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seven minutes past Fouteen of the clock.

्र उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए } Mr. Deputy Speaker in the Chair

कैन्द्रीय स्रकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापिस लेने के सम्बन्ध में केरल सरकार के कठिन निर्णय के बारे में RE: KERALA GOVERNMENT'S REPORTED DECISSION TO WITHDRAW CASES AGAINST CENTRAL GOVER NMENT EMPLOYEES.

श्री स॰ मो॰ बनर्जी (कानपुर): मुके एक निवेदन करना है। आपने आज के समा॰ धार्पत्रों में पढ़ा होगा कि केरल सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर बलाये जाने वाले सभी मुकदमों को वापिस ले रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष महोदय ने इसको उठाने की अनुमति नहीं दी थी।

थी स॰ मो॰ बनर्जी: उन्होंने स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचना को रद्द कर दिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं... (अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अन्तर्गत भी इसको रह कर दिया गया था।

श्री स॰ मो॰ बनर्जी: मै आपका घ्यान समाचारपत्रों में छपे निम्नलिखित समाचार की ओर दिलाना चाहता हुं:

कि केरल सरकार ने लोगों तथा सम्पत्ति पर हुए गम्भीर मामलों को छोड़ कर केन्द्रीय कर्मचारियों की 19 सितम्बर की हड़ताल से उत्पन्न होने वाले शेष सभी मामलों को न्यायालय की अनुमति से वापस देने का निर्णय किया है।

यह निर्णय राज्य मन्त्रिमंडल की बैठक में लिया गया था और प्रेस सम्नेलन में मुख्य-मन्त्री श्री नम्बूपरीपाद द्वारा घोषित किया गया है।

केरल सरकार के इस निर्णाय पर नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है।

मैं केवल यह चाहता हूं कि संसद कार्य मन्त्री इस पर ध्यान दें तथा हमारी वास्तविक भावनाओं के बारे में उनको सूचित करें क्यों कि उसमें राज्य सरकार की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय: वह इस पर ध्यान देंगे। जहां तक सहानुभूति का सम्बन्ध है उनकी सहानुभूति कर्मचारीयों के साथ है।

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा॰ राम सुभग सिंह): जैसा कि आपने स्वयं कहा अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति नहीं दें थी । परन्तु मैं आपके आदेश का पालन करूंगा ।

श्री कः नारायग्रात्व (बोव्बिली): इसमें केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के महत्वपूर्ण सिद्धांत अन्तर्ग स्त हैं। यह स्थिति ऐसी है जिसमें अध्यादेश का उल्लंघन किया गया है।

श्रध्यक्ष महोदय: संसद कार्य मन्त्री जो कुछ कहना चाहते थे उन्होंने कह दिया है। अब मामले को समाप्त समभा जाना चाहिए।

श्री स॰ मो॰ बनर्जी: हम इन महत्वपूर्ण मामलों को उठाना चाहते हैं वयों कि सभा का समय समाप्त होने वाला है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Our sympathies are with government employees. All Government employees except those who were engaged in violence should be reinstated. I also do not want that instructions of the Central Government should be

violated but the Central Government should himself give directive to release and reinstate the government employees except those involved in violence.

उपाध्यक्ष महोदय: जैसा मैंने बताया माननीय मंत्री ने इस बात को ध्यान में रख लिया है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य): मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। जोकि मामला मी सभा में उठाया जाता है आप मंत्री महोदय को उसे ध्यान में रखने को कहते हैं इस प्रकार समय का कोई कार्य नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय सदस्य की बात को भी ध्यान में रख लिया है। कुछ मामले माननीय सदस्यों के दिलों को उत्तेजित कर रहे हैं। सदस्य उन मामलो को यहां पर उठाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि सरकार भी बहुत से मामलों को उठाने के लिये उत्सुक हैं। जो कुछ कहा गया है माननीय मंत्री ने उसको ध्यान में रख लिया है।

श्री रा॰ ढो॰ भण्डारे: मैं अनेक समस्याओं को उठाना चाहता हूँ। आशा है कि ग्राप मुभे उनको उठाने की अनुमित देंगे।

उपाच्यक्ष महोदय: अब हमें नागालैंड विधान सभा (प्रतिनिधित्व में परिवर्तन) विधेयक पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़): चण्डीगढ़ में कोई भी हिसात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। अतः वहां के सरकारी कर्मचारियों पर चलाये जाने वाले मुकदमों को वापस ले लिया जाना चाहिए।

नागालैण्ड विधान सभा (प्रतिनिधिःव में परिवर्तन) विधेयक LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NAGALAND (CHANGE IN REPRESENTATION) BILL.

उपाध्यक्ष महोदय: इस विधेयक पर किसी का मतभेद नहीं है। अतः इसको समय से पूर्व समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Atleast one hour should be granted for this. I was a member of the delegation who visited Nagaland. I should be given five minutes to speek on this Bill.

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-तन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि नागालैंड की विधान सभा में परिवर्तन करने के लिए और उस प्रयोजनार्थ नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 में तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में पारिमाणिक संशोध्यन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाय।" श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री इस विदेयक पर आगे कार्यवाही नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इस विदेयक के विरुद्ध हूँ।

इस विदेयक का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना है तथा नागालेंड विधान समा में सदस्यों की सख्या को बढ़ाना है। संविधान के अन्तगंत नागालेंड के राज्यपाल को वह शक्ति हैं। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 371 क (2) की ओर दिलाना चाहता हूं। इस अनुच्छेद के अन्तगंत नागालेंड के राज्यपाल को त्यू सांग जिले की शान्ति, प्रगति तथा अच्छी सरकार बनाने के लिए विनियम बनाने का अधिकार है। अतः मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक अनावश्यक है और इसका अर्थ समा के समय का अपव्यय करना है।

इस विधेयक का तात्पर्य नागालैंड विधान समा के सदस्यों की संख्या की बढ़ाना है। संविधान के अनुच्छेद 170 में यह दिया गया है कि किसी भी विधान सभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 170 क में नागालैंड प्रशासन के बारे में दिया गया है कि उसमें साठ के स्थान पर 46 सदस्य हो सकते हैं।

अब इस विधेयक के द्वारा नागालैंड विधान सभा के सदस्यों की संख्या 52 की जा रही है। अतः इस विधेयक से संविधान के उपबन्ध का उल्लंघन होता है। अतः संविधान में संशोधन किये बिना इस विधेयक को इस सभा द्वारा पास नहीं किया जा सकता। अतः सरकार को पहले संविधान में संशोधन करने का विधेयक प्रस्तृत करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नागालैंड के बारे में कुछ विशेष उपबन्ध किये गये हैं। जब नागालैंड को राज्य का दरजा दिया गया था तब राज्यपाल को कुछ विशेष जिम्मेदारियां दी गई थी।

श्री रा॰ ढो॰ भण्डारे (बम्बई-मध्य) : इनको संविधान में दिया गया है। उपबन्ध (ज) के अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या अभी भी 60 ही है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री श्रीनिवास मिश्र जी का कहना यह है कि क्या इस संवैधानिक उपबन्ध में इस साधारण विधान से संशोधन किया जा सकता है ?

श्री रा० ढो० मण्डारे : जपबन्ध के अनुसार यह संख्या 46 से कम नहीं हो सकती। परन्तु इसमें बढ़ाई जा सकती है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: नागालैंड सरकार ने भारत सरकार को एक पत्र लिखकर नागालैंड विधान समा में त्यूनसांग जिले के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कहा है वहां से 6 के स्थान पर 12 सदस्यों को लिए जाने के लिए कहा गया है। यह प्रार्थना विधान समा द्वारा पास किये गये संकल्प पर आधारित है।

संविधान के अनुच्छेद 371 क के खण्ड (2) में नागालैंड के त्यूनसांग जिले के लिए मागालैंड के बनने के दिन से 10 वर्ष तक विदोष सुरक्षोपाय करने के लिये राज्यपाल को अधिकार दिने गये हैं। राज्यपाल प्रादेशिक परिषद की सिफारिश पर इन को और अधिक

अवधि के लिए बढ़ा भी सकता है। नागालैंड राज्य ग्रधिनियम, 1962 की धारा 11 की उप-धारा (1) में त्यूनसांग जिले के लिए छ: स्थान रखे गये हैं ये स्थान प्रादेशिक परिषद के सदस्यों को अपने से भरना है। इस अवधि के पश्चात त्यूनसांग जिला अपनी जनसंख्या पर आधारित 20 सदस्य विधान सभा में भेज सकता है। उक्त अवधि में प्रतिनिधित्व को इस कारण कम रखा गया था क्योंकि वहां के लोग चुनाव की आधुनिक प्रथाश्रों से पूरी तरह परि-चित नहीं थे और क्योंकि चुनाव प्रादेशिक परिषद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होते थे।

त्यूनसांग जिले को अब नागालेंड विधान सभा की कायंवाही में पर्याप्त अनुभव हो गया है। अतः यह महसूस किया गया कि उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया जाये। विधेयक का उद्देश्य उनकी संख्या को 6 से बढ़ाकर 12 करना है। ये अतिरिक्त स्थान भी प्रादेशिक परिषद के सदस्यों में से ही भरे जायेंगे। त्यूनसांग जिला अन्ततः 20 और सदस्य भेजने का अधिकारी होगा। प्रादेशिक परिषद की सिफारिश जब तक राज्यपाल विधान सभा के किसी अधिनियम को त्यूनसांग जिले पर लागू करने का अनुदेश न दे तब तक वह अधिनियम लागू नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि इस समय त्यूनसांग जिले पर नागालेंड विधान सभा का क्षेत्रा— धिकार आशिक रूप से है। अतः उनके प्रतिनिधित्व को ग्रमी सीमित रखना ही उचित है। इस विधेयक का प्रमाव वर्तमान सभा के विघटन तक नहीं होगा। इसका ग्रयं यह है कि इस विधान के पास होने के पश्चात नागालेंड विधान सभा कोहिमः माराकचंग जिलों के प्रतिनिधि तथा संविधान के अनुच्छेद 371 क में उल्लिखित प्रादेशिक परिषद के सदस्यों द्वारा त्यूनसांग से चुने गये 12 सदस्यों पर आधारित होगी।

में विधेयक को प्रस्तृत करता हूं।

उपाष्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि नागालैंड की विधान सभा में प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने के लिए और प्रयोज-नार्थ नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 में तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में पारिमाणिक संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री रंगा (श्रीकाकुलम): मैं सिद्धान्त रूप में इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि ये चुनाव भारत सरकार तथा चुनाव आयोग द्वारा शान्तिपूर्वक ढंग से, सन्तोषजनक रूप से तथा अहिसा से हों और लोगों का ग्रपने मनाधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक अवसर दिया जाये। नागालण्ड सरकार तथा उसके मंत्रियों ने भी हमें आक्वासन दिया था कि चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में कराये जायेंगे ताकि वे लोगों को बता सकें कि नागालेंड के लोग लोकतन्त्र में तथा विधान समा मण्डन में विश्वास रखते हैं जोकि हमारे सविधान द्वारा वहां पर स्थापित किया गया है। हमें यह भी बताया गया है कुछ शक्तियां नहीं चाहती कि चुनाव हों। कुछ समय पूर्व उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। उप-चुनाव में ऐसी शक्तियां सफल नहीं हुई थी। यदि अब ये शक्तियां अपने हथियारों द्वारा लोगों को चनाव में मत डालने आने से रोकती है तो चुनाव आयोग तथा सिविल सरकार का यह कर्त्व य है कि जहां कहीं आवश्यकता हो वे सेना के सहयोग से मत डालने आने वाले

लोगों को संरक्षण दें। मुक्ते आशा है कि सरकार लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देने के लिए सभी लोकतन्त्रात्मक तथा शान्तिपूर्ण ढंग अपनायेगी।

मैं यह भी कहूँगा कि नागालेंड के अब अधिकांश लोग भारत को अपनी मातृभू मि मानने को तैयार हो रहे हैं यद्यपि वे नागालेंड को अपना घर मानते हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करंगा कि वह नागालेंड सरकार से मिलने वाले सुभावों पर आवश्यक कार्यवाही करे। मुभे विश्वास है कि नागालेंड मन्त्रिमण्डल भारतीय राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है परन्तु वह इसके साथ साथ अपने लोगों की भावनाओं को भी सन्तुष्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में वह अपने लिए पृथक राज्यपाल चाहते हैं। उनकी इस मांग को स्वीकार न करने के कोई कारण नहीं हैं।

वे विधि व्यवस्था पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहते हैं। हो सकता है कि इस के लिए अभी समय ठीक न हो और चुनाव से पूर्व यह समय हो भी नहीं सकता। वे लोग इसके लिए पूरी तरह सक्षम हैं परन्तु वहां की विशेष स्थिति को तथा सीमाक्षेत्र के नाते तथा वहां गड़बड़ को देखते हुए विधि व्यवस्था को पूरी तरह उनके हाथ में नहीं दिया जा सकता। उनको इस बारे में धंयं से काम लेना चाहिये। राज्यपाल को उन्हें अपना मार्गदर्शक तथा मित्र समफना चाहिये।

Shri Madau Limaye (Monghyr): I have a point of order. There is a convention for the last 1-2 years to fix time for discussion under rule 193. But no time has been indicated on today's order paper. May I take it that discussion on my motion regarding steel deals is being suppressed. (interruptions)

श्री ए० ढो॰ भण्डारे (वम्बई-मध्य): जब बहस चल रही है तो आप इसकी अनुमित

उपाध्यक्ष नहोदय: जब किसी बिषय पर चर्चा की जा रही हो तो आप समा के समक्ष सम्बद्ध विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठा मकते हैं। जहां तक कार्य सूची का प्रश्न है आप उसके बारे में चर्चा के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। दूसरे कार्य में मन्त्रणा समिति कभी मी इस बात का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करती कि अमुक समय पर अमुक विषय पर चर्चा की जानी चाहिये।

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभाग मिह): मै इस बहस के लिये सहमत हो गया हूं परन्तु कार्य सूची संसद-कार्य सचिवालय द्वारा तैयार नहीं की जाती।

Shri Madhu Limaye: But please let me know the decision of the Business Advisory committee. I want to know whether it was decided that it would be taken up after the other business of the house is over.

Dr. Ram Subhag Singh: We will convey your objection to the hon, speaker.

Shri Madhu Limaye: My motion must be taken up after the motion of Shr prakash Vi. Shastri. It is always taken up at 5.00 p, m.

उपाध्यक्ष महोदय: वर आपके निवेदन पर स्थिगत किया गया था। हम इसके लिए समय निकालने का प्रयास करेंगे। हम इस पर पांच बजे विचार करेंगे, इस समय नहीं।

Shri Randhir Singh: The people of Nagaland are peace loving. It is not true that the people of Nagaland are revolutionists I wish for the success of the peace mission. That area needs a great deal of improvement. There are only three roads. Arrangements for doctors, Post and Telegraph offices should be made there immediatly because that area is adjacent to the border.

Some of their areas have gone to Assam, Manipur etc. Those areas should be given back to them.

Their demand to appoint a separate Governor should carefully be considered.

उपाण्यक्ष महोदय: यह सामान्य चर्चा नहीं है और मैं इस पर एक मिनट भी वृद्धि नहीं कर सकता। (अन्तर्बोधाएं)

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं सरकार की ओर से सभा को यह आक्वासन देता हूं कि स्वतन्त्र और न्यायोचित चुनाव के लिये यथा मम्भव कार्य-वाही की जायेगी और इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में हों। (अन्तंबाधाए) राज्य सरकारों द्वारा दिये गये सब सुभाव विचारधीन हैं (अन्तंबाधाए)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि नागालैंड की विधान समा में प्रतिनिधित्व में परि-वर्तन करने के लिए और उस प्रयोजनार्थ नागालैंड राज्य ग्रिधिनियम, 1962 में लोक प्रतिनि-धित्व अधिनियम, 1950 में पारिए॥मिक संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुन्रा The motion was adopted

कुछ माननीय सदस्य + +

उपाध्यक्ष महोदय: सब सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लें। जब तक आप स्थान ग्रहण नहीं करें। मैं किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमित नहीं दूंगा। कार्य मन्त्रणा सिमिति ने इसके लिये समय निर्धारित किया है। हमने सभा का कार्य 8 बजे तह समाप्त करना है। यदि सभा इस विषय पर समय में वृद्धि करना चाहती है तो उस बारे में आवश्यक कार्यवाही मन्त्री महोदय कर सकते हैं। मैं जिस्मेवारी लेने के लिये तैयार नहीं हूं।

डा॰ राम सुभग सिह: मुभे कोई आपत्ति नहीं है। आप यदि चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं।

+ कार्यवःही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्री कृष्णमूर्ति को पहला अवसर दूंगा। यदि संशोधन ग्रनौप-चारिक है तो कठिन।ई नहीं होगी और उन्हें दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): In my opinion instead of speeches the suggestions of the hon. Members in the form of questions should be allowed.

The Minister should note those suggestions and he should give a reply to them.

उपाध्यक्ष महोदय: यदि इस सुभाव का पालन किया जाये तो यह एक अच्छा सुभाव है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द): आपने मन्त्री महोदय से उत्तर देने के लिये कहा था और उस पर मत विभाजन भी किया गया था। क्या आप उसे समा की कार्यवाही से निकाल देगे ?

उपाध्यक्ष महोदय: जी नहीं, अब खण्डों पर चर्चा करेंगे:

श्री लोबो प्रभु: मैं अपने संशोधन संख्या । और 3 प्रस्तुत करता हूं।

नागालैण्ड के पांच वर्ष बाद भी हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। हमारा पूर्व नागालैण्ड से सम्बन्ध नहीं है।

हमारा केवल तुएन सांग जिले से सम्बन्ध हैं। इस जिले में कोई सीधा चुनाव नहीं हुआ है। वहां सरकार को 10 वर्ष के अन्दर अवश्यक परिवर्तन के अधिकार दिये गये हैं। वहां का वातावरए। बहुत अच्छा हो गया है अतः वहां लोगों में सीधा चुनाव करने के लिये विश्वास किया जान। चाहिये। यदि सरकार तुएनसांग जिले को दूसरे दो जिलों के समान लाना चाहती है तो उसे वहां अप्रत्यक्ष चुनावों की व्यवस्था करनी चाहिय। यदि ऐसा सब 12 स्थानों के लिये नहीं होता तो कम से कम उन स्थान के लिये किया जाना चाहिये जो स्थान सरकार बढ़ा रही है। सरकार को यह बताना चाहिये कि ऐसा नहीं करने के क्या कारए। हैं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: तुएन सांग जिले के निवासियों के अनुरोध पर ही यह विशेष प्रबन्ध किया गया है। ऐसी व्यवस्था 10 वर्ष या उससे अधिक समय के लिये की गई है। 10 वर्ष के परवात् वहां सीधे चुनाव किये जायेंगे। ऐसा केवल सीमित समय के लिये है। उसके पश्चात तुएन सांग जिले के निवासियों का समान दर्जा होगा, स्तर होगा और वे शेष नागालैण्ड की मांति अपने सदस्यों का चुनाव करेंगे।

संशोधन संख्या 1 भीर 2 मतदान के लिये रखे गये भीर भस्वीकृत हुए।
The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोद्य: प्रकृत यह है ''कि खण्ड 2 विधेयक का अ'ग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुन्ना The motion was adopted खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया। Glanse 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये। Clauses 3 to 5 were added to the Bill.

खण्ड 1, श्रिषिनियमन सूत्र तथा विघेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये। Clause 1, the Enacting formula and the Title were added in the Bill.

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बी० कृष्णमूर्ति (कडुलूर): नागालेंड के दौरे से हमने अनुमान किया कि नागालेंग्ड मारत का अभिन्न अंग है। आज राज्य को भारी किठनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य का कोई पृथक राज्यपाल नहीं है और राज्य को कातून और व्यवस्था के बारे में अधिकार नहीं दिये गये हैं। सरकार द्वारा 1956-57 में की गई सौनिक कार्यवाही के कारण अभी भी नागालैंड के नागरिक सरकार के प्रति विद्रोही हैं। हमें ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये कि राज्य सरकार को विद्रोही नागाओं सहित सब लोगों का समर्थन प्राप्त हो सके। राज्य सरकार को कानून और व्यवस्था के अधिकार देकर हमें राज्य सरकार की शक्ति को बढ़ाना चाहिये उनके लिये अलग राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिये। मनीपुर और आसाम से जुड़े हुए क्षेत्रों को नागालैंड राज्य में शामील किया जाना चाहिये।

भारत सरकार को नागालैंड के 20,000 बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी दिलाने की जिम्मेवारी लेनी चाहिये। निराशा के कारण ये बेरोजगार व्यक्ति विद्रोही हो गये हैं। इन बेरोजगार व्यक्ति विद्रोही हो गये हैं। इन बेरोजगार व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा प्रयत्न किये जाने चाहिये। सरकार तब ही विद्रोही नागाओं और बेरोजगार युवकों के मन को जीतने में सफल होगी। यह समस्या राज्य सरकार को अधिक अधिकार देकर हल की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की हर तरह से सहायता करनी चाहिये।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): The people of Nagaland are peace loving. If some of the people have become hostile it is because of our enemies being active there and due to the propoganda of christianity among them. It is, therefore, necessary that development work may be carried on in that State so that it may be brought at par with the rest of the country. Means of Communications should be developed there and improvement in education should be made in the State. Their boundry problem should be solved. Hostile elements are still there. Government should exercise vigilance against anti-national elements.

One of the main problems in the State is of Tribals, which should be solved. The peace mission has only created complications. Pakistan and China are doing great harm to us on our borders. More and more improvement should be made in Nagaland. In addition to it we should be very careful about hostile elements.

Shi Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Nagaland is Switzerland of India. Entry into Nagaland is still restricted. During the last three years only (hree Cabinet Ministers visited Nagaland. It is necessary to obtain for visiting Nagaland. The Government should withdraw this permit restriction and Nagas should be provided all facilites for development.

In principle, every State should have a separate Governor. But this cannot be done in case of Nagaland till the situation in Nagaland becomes normal. Government of India should immediately appoint a Commission to settle the border dispute between Nagaland and Assam.

It is wrong to believe that all the people of Nagaland are with us. There is an extremist section in Nagaland which believes in violence and wants to set up an independent state. Our Security Forces have done a praise worthy work there, but it is not merely a military problem but it is a political problem also and we have to settle it at political level as well. There should be exchange of people. That is the only way to solve the problem.

The role of Peace Mission is very dangerous. It tries to equate the security forces with the underground Nagas. It is not fair and Government should bid farewell to this Mission. Government should have direct talks with the State Government and every effort should be made to make it more and more effective. With these words I support the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे नागालैंड के एक ही दौरे के आधार पर शान्ति मिशन के कार्य की आलोचना न करें।

Shri Kanwar I al Gupta: You may have your own opinion but you hould come down to your seat before expressing your opinion.

उपाध्यक्ष महोदय: जब माननीय संदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हों तो वह इस बात का घ्यान रखें कि वह कोई ऐसी बात न कहें जो आगे जांकर भूठी साबित हो।

भी रा० बरूग्रा: (जोरहाट) नागाओं को लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में आस्था है। उनकी प्रतिक्रियाओं को अपने स्तर से जांचना गलत होगा।

यह विध्यक लोकतन्त्रीत्मक भावना के अर्नुकूल है। पिछले कुछ महीनों में नागालिंग्ड की स्थिति में सुधार हुआ है मुक्ते आशा है कि आगे भी इसकी स्थिति में ग्रीर सुधार होगा। अतः सरकार को उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये जो भारत के साथ एकता के लिये प्रयास कर रहे हैं।

सीमा विवाद को अधिक तूल नहीं दिया जाना चाहिये। यह मामला श्रासाम और नागालैंण्ड सरकार के बीच का है और दोनों राज्यों में मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है और वह दिन दूर नहीं जबकि दोनों राज्यों का यह मामला हल हो जायेगा।

जहां तक संचार व्यवस्था का सम्बन्ध है सरकार को इस और ध्यान देना चाहिये कि आसाम और नागालैण्ड और नागालैण्ड और शेष मारत के बीच संचार सुविधाओं में शीझ सुघार हो अन्यथा एकीकरण की सभी बातें और आन्तरिक कठिनाइयों को दूर करने की सभी बातों का महत्व नहीं रह जाता।

मैं सरकार को इस विधेयक को प्रस्तुत करने लिये बधाई देता हूँ और आशा करता हूं कि नागालंग्ड सरकार को अपने नागरिक की भलाई के लिये भारत सरकार पूरा सहयोग प्रदान करेगी।

Shri S. M. Joshi (Poona); I support this Bill whole-heartedly The Security Forces in Nagaland are doing a praise worthy job. They must be congratulated for handling the situation so well.

There is a feeling in Nagaland that we consider them to be outside India and it is why we do not visit them. This feeling should be removed by arranging frequent visits to that State. In that case they will feel that we are taking great interest in them It is correct that Nagaland is Switzerland of India. We should give full support to that State. It is also necessary to strengthen the hands of the State Government. The Central Government should consult only the State Government and none ele.

Shri Chandrajeet Yadav (Azamgarh): I welcome the Bill. I agree with Shri S. M. Joshi that we should familiarise ourselves with the feelings of the people of Nagaland. Since it has been a neglected area for quite a long time it is necessary that to undertake development works there. After independence we have tried to respect their feelings. It is not fair to doubt the loyalty of the christians and Muslims. They are two essential parts of our culture. Doubting their loyalty will create only bitterness. Nagas should be given the assurance that we consider them to be a part of our country and we want to solve their problems through peaceful means. This is the only way to win their hearts.

श्री मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर): यदि सरकार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करती है जिसके अन्तर्गत तुएनसांग के लोग विधान सभा के लिये अपने प्रतिनिधि निर्वाचित कर सकते हैं और उनके लिये विधान सभा में 20 स्थान हो, तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह विधेयक उचित दिशा में है।

भारत सरकार ने नागालैण्ड की जनता की मदद बड़ी देरी से की है। सरकार को नागालैंड की समस्याओं पर विचार करते समय मनीपुर की जनता की इच्छाओं को भी इयान में रखना चाहिए क्योंकि वह पड़ीसी राज्य है। जब एक भाग को राज्य का दर्जा दिया जाता है तो दूसरे माग को उससे वंचित नहीं किया जा सकता।

श्री रा० ढो० भंडारे पीठासीन हुए Shri R. D. Bhandare in the Chair

कुछ माननीय सदस्यों ने नागलेंड और मनीपुर का भी दौरा किया। उन्होंने मनीपुर के लोगों की इच्छाएं और आकांकाओं के विरुद्ध बातें भी की । यह बात अपूचित है। मनीपुर की जनता ने राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिये आन्दोलन आरम्भ कर दिया है। अतः विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह कहूंगा कि सरकार को पूर्वी प्रदेश की समस्या को समूचे रूप से विचार करना चाहिये, अलग अलग से नहीं। श्री शिव नारायए (बस्ती): में विधेयक का समर्थन करता हूं। हम नागालैंड में लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम नागालैंड की जनता को सब लोकतात्रिक अधिकार देना चाहते हैं। इस आश्रय से कि वे सभा की कार्यवाही में भाग ले सके उनके प्रतिनिधियों की संख्या छः से बढ़ाकर बारह की जा रही है। मुभे आशा है कि सरकार नागालैंड के राज्यपाल को यह बतायेगी कि वह उन्हें समानता का दर्जा दे और उन्हें सभी लोकतांत्रिक अधिकार दे।

श्री क० लकप्पा: (तुमकुर) नागालैंड देश का सामरिक महत्व का माग है अतः इसकी पूरी तरह से रक्षा को जानी चाहिये। सरकार द्वारा सामरिक महत्व के स्थानों की रक्षा न किये जाने के परिएगामस्वरूप सरकार को विदेशों के दबाव में आना पड़ता है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की उचित तरीके से रक्षा की जानी चाहिये। इसके लिये हमें नागालैंड से उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना चाहिये। वहां पर सड़कों का विकास नहीं किया गया है। वहां पर डाक-खाने तक भी नहीं खोले गये हैं।

विद्रोही नागा नेता भारत के विरुद्ध नहीं था। वह समूचे दल को इकट्ठा रखना चाहता था लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। भारत सरकार मामले की जांच करने और वहां की जनता की रक्षा करने में असफल रही। हिमालयवर्ती क्षेत्र के लिये सरकार को बृहद परियोज-नाएं तैयार करनी चाहिये। ऐसा करना हमारे समस्त देश के हित में होगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): It appears to be very irrelevant to keep Nagaland still under Ministry of External Affairs. When all the States are under the Ministry of Home Affairs, I do not see any reason in keeping it still under the Ministry of External Affairs. It should be transferred to the Home Ministry.

Several years have passed since Government sent army to Nagaland for establishing peace, but it has not been successful in establishing peace in that area. It appears that army has not been given free hand. Government should not show any leniency to anti-national elements and the army should be given full authority to deal with them.

So far as the question of the name of this State is concerned, its name should be changed from 'Nagaland' to 'Naga Pradesh'. Foreign Missionaries are engaged in antinational propaganda in that area. The people in that area are mostly uneducated. In order to keep their feelings alive it is necessary that institutions like Arya Samaj and Rama Krishna Mission are allowed to function there. Restrictions should be imposed on the propagation of anti-national feelings.

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (सुरेन्द्रपाल सिंह): मैं चाहता हूं कि अधिक से प्रिधिक माननीय सदस्य नागालैंड का दौरा करें ताकि वे वहां की समस्याओं को समक्त सकें। नागालैंड के लोग भी उनके दौरों का स्वागत करेंगे क्योंकि वहां के लोग अपने को अकेला अनुभव करते हैं। सरकार की नीति सदा शान्ति पूर्ण और मित्रता पूर्ण और नागालैंड की जनता के हृदय को जीतने की रही है। लेकिन हमारी नीति के विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया हैं। लेकिन यह खुशों की बात है कि हमारी नीति किसी सीमा तक ठीक सिद्ध हो चुकी है। हमारी इसी नीति के ही कारण कुछ सीमा तक शान्ति तथा स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई है और इसी के परिणागस्त्ररूप नागा जनता में फिर से राजनीतिक विचार उत्पन्न

हो गये हैं। नागा समस्या को हल करने के लिये यह उचित दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है।

यह भी कहा गया है कि हमें राज्य सरकार की मांगों पर विचार करना च हिये ग्रीर उसके हाथ मजबूत करने के लिये हमें सहयोग प्रदान करना चाहिये। वास्तव में हमारी यही नीति रही है। हम नागालैंड सरकार के हाथ मजबूत करना चाहते हैं और उनकी सहायता के लिये यथासम्भव कार्य करना चाहते हैं ताकि वे लोग अनुभव करें कि वह उनकी सच्ची और प्रतिनिधि सरकार है और जो कुछ भी किया जाना है वह केवल उनके द्वारा ही किया जाता है।

राज्यपाल की अलग नियुक्ति और सीमा निर्धारण आदि के प्रश्नों के बारे में निर्ण्य लेने का यह उपयुक्त समय नहीं है। इस समय वहां स्थिति असाधारण हैं और इस क्षेत्र में शान्ति नहीं है। जैसे ही वहां सामान्य स्थिति और शान्ति स्थापित होगी इन समस्याओं पर विचार किया जायेगा।

नागालेंड में विकास और वहां के लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के बारे में भी सवाल उठाया गया था। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि इस क्षेत्र में नागाओं के लिए कुछ विशेष कार्यवाही की जानी चाहिये।

गत बीस वर्षों में अनेक योजनाएं बनायी गयी हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि योजना आयोग से मिल चुके हैं। वितीय आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। लोगों को रोजगार देने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। हमें आशा है कि कुछ वर्षों के बाद हम सकल हो जायेंगे।

जहां तक आन्तरिक मामलों का प्रश्न है उन पर विचार हो रहा है। हम विचार कर रहे हैं कि लोगों के वहां पर जाने की शर्तों को उदार बनाया जाये। कठिनाई उस समय उत्पन्न होती है जब लोग वहां जाकर शोषणा करने लगते हैं। वहां के लोग पिछड़े हुए हैं। बाहर के लोगों के वहां बस जाने से वहां के लोग उन्नति नहीं कर सकेंगे। ऐसा मय वहां के लोगों के मन में है। इसलिये यह व्यवस्था है और यह अस्थायी तौर पर है। कुछ वर्षों में जब नागालेंड का विकास हो जायेगा, तो यह शर्ते हटा दी जायेंगी। अब भी हम लोगों के वहां जाने पर लगे प्रतिबन्धों को कम करने पर विचार कर रहे हैं।

कुछ समय पूर्व नागालेंड में कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों ने गड़बड़ की थी। अब वे वहां नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि बहां के सभी ईसाई देशद्रोही हैं। वैसे वहां पर अब भी चार पांच धर्म प्रचारक है। उन्हें राज्य सरकार के कहने पर वहां रहने दिया गया है। वे राजनैतिक गतिविधियों में व्यस्त नहीं है। वे ईसाई हैं, इसलिये उन्हें देशद्रोही कहना गलत है। सुएनसांग के विधायकों के चयन के बारे में वर्तमान व्यवस्था अस्यायी व्यवस्था है। इसमें उचित समय पर परितंन कर दिया जायेगा। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने प्रश्न किया है कि नागालेंड के मामले अभी तक वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अधीन क्यों है। यह प्रश्न अनेक बार पूछा गया है। वास्तव में नागा लोगों की यह मांग थी और सरकार ने इसे स्वीकार

किया था। वैसे अब स्थिति में ब्रन्तर हो गया। नागालैण्ड की सरकार सभी केन्द्रीय मन्त्रालयों से अलग से व्यवहार करती है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Shri Lal Bahndur Shastri has given an assurance to this effect in the House.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: यह मामला विचाराधीन है। इस मामले में हमें राज्य सरकार को सहमत कराना है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: नागालैंड के नाम का प्रश्न भी उठाया है। इस बारे में हमें इसको अधिक महत्व नहीं देना चाहिये। वहां के लोगों ने इसी नाम की मांग की थी। जैसे मद्रास का नाम वहां के लोगों की इच्छा के अनुसार तिमलनाडु रख दिया गया है।

मुभे प्रसन्तता है कि सदस्यों ने वहां पर तैनात सुरक्षा सेना के कार्य की सराहना की है। इस सम्बन्ध में एक करार के ग्रन्तर्गत राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त हैं। जब करार का उल्लंघन होता हैं, सुरक्षा दल उचित उपाय करता है। गैर-कानूनी गतिविधियों को दबाने का उन्हें पूरा अधिकार है।

समापति महोदय : प्रश्न यह है:--

'कि विधेयक को पारित किया जाये'

प्रस्ताव स्वीकृत हुन्ना। The Motion was adapoted

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

वागिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:--

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में अंग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य रंग रोगन, एल्यूमिनियम, और मोटर गाड़ियों के बारे में प्रश्लक आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को लागू करना है। प्रश्लक आयोग के अन्य कामों में व्यस्त होने के कारण उसकी सिफारिशें प्राप्त नहीं हो सकी थीं। आयोग की इन तीन उद्योगों पर रिपोर्ट, सरकार का संकल्प तथा जारी की गयी अधिसूचनाएं पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं। माननीय सदस्यों ने इनका अध्ययन कर लिया होगा। प्रशुल्क आयोग की स्थापना 1952 में प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत की गयी थी। इस आयोग का मुख्य कार्य संरक्षण और मुख्य सम्बन्धी जांच तथा पुनरीक्षण

करना है। यह उद्योगों का संरक्षण करता है। आयोग संरक्षित उद्योगों के कार्य पर निगरानी रखता है और देखता है कि वे उद्योग अपना कार्य ठीक प्रकार से करें। यह संरक्षित उद्योगों के उत्पादों की किस्म न घटे, उनके मूल्य न बढ़े आदि बातों का भी ध्यान रखता है। इसे व्यापक राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना होता है।

अब में सम्बन्धित उद्योगों का संक्षेप में उल्लेख करू गा। रंगरोगन एक ऐसा ही उद्योग है। इसे 1955 प्रथम बार संरक्षण दिया गया था। यह 10 वर्ष के लिये था। 1964 में इसे 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया और फिर इसे एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया। इस उद्योग में तैयार रंगरोगन और आधे तैयार रंगरोगन आते हैं। देश में तैयार माल से अधिकाश उपभोक्ता सन्तुष्ट हैं। उद्योग देश की मांग को पूरा करने की स्थिति में है और अन्य देशों की प्रतियोगिता का भी सामना करने में समर्थ है। आयोग ने शिफारिश की है कि संरक्षण की अविध 31 दिसम्बर, 1968 के बाद बढ़ायी न जाये। परन्तु इसके बारे में समय-समय पर निरीक्षण जारी रहना चाहिये।

श्राघे तैयार रंगरोगनों को संरक्षण देने की प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की है। इस बारे में आयोग ने कीमतें न बढ़ाने की भी सिफारिश की है। सरकार ने संरक्षण सम्बन्धी आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। इस सम्बन्ध में विधेयक में उपबन्ध किया जा रहा है। यह संरक्षण 31 दिसम्बर, 1971 तक करने का प्रस्ताव है।

एल्यूमिनियम उद्योग को 1949 में पहली बार संरक्षण दिया गया था। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा। अन्तिम जांच 1964 में किया गया था। आयोग ने अब तीन वर्ष के लिये संरक्षरण भवधि बढ़ाने की सिफारिश की है। सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है।

मोटरगाड़ी उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग ने प्रथम रिपोर्ट 1953 में दी थी। तब ही से यह एक सुरक्षित आयोग चला आ रहा है। परन्तु समय समय इस में संशोधन होता रहा है। आयात पर कड़े प्रतिबन्धों की नीति के फलस्वरूप गत वर्षों में मोटर गाड़ियों का आयात बहुत कम हुआ है। निर्यात बढ़ गया है।

प्रशुल्क आयोग ने अपनी वर्तमान रिपोर्ट में सहायक पुर्जी आदि पर आरंतगातमक दरों के हटाने ग्रीर मोटर गाड़ी उद्योग को संरक्षण जारी रखने की सिफारिश की है। इस बारे में समय समय पर जांच की सिफारिश की मवी है। सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है:

इन उद्योगों के बारे में आयोग ने कुछ और भी सिफ रिशें की हैं। उन पर किये गये निर्मायों को संकर्त्पों में घोषित कर दिया गया है। इसे सभा पटल पर रख दिया गया है और सम्बन्धित मन्त्रालय कार्यवाही कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ में विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

सभावित महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

थी शिववनद्र भा (मधुबनी): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक को 15 मार्च, 1969 तक जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

Shri Pan a Lal Barupal (Ganganagar): Sir, I want to draw your attention to a difficulty being faced by us. We are find ng it difficult to get emergency passes for gallery for our guests who come from outside. We are asked to perform many formalities before passes are given to us. It is a general complaint of members. It should be looked into.

Mr. Chairman: I will convey it to the hon. Speaker.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी): मेरे विचार में प्रशुल्क आयोग एक फजूल निकाय बन कर गृह गया है। वास्तव में वित्त मंत्रालय पूरा नियंत्रण रखते हुए हैं। यही मंत्रालय आयात श्रीर निर्यात पर नियन्त्रण करता है। मैं प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं हूँ। प्रशुल्क आयोग वस्तु प्रों के मूल्य पर नियन्त्रण रखता हैं। परन्तु आप देखेंगे कि वस्तुओं के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वया इस प्रकार का संरक्षण ठीक है। माननीय मंत्री ने बताया नहीं कि आयोग ने कैसे और किन उद्योगों की कीमतों को कम स्तर पर बनाये रखा है? मोटरगाहियों के बारे में तो कीमतें चार गुना तक बढ़ गयी है। इस मामले में प्रशुल्क आयोग अपने कार्य में असफल रहा है।

मैं प्रशुलक अयोग को समाप्त करने की मांग नहीं करता परन्तु मैं तो चाहता हूं कि इसका ठीक प्रकार से उपयोग होना चाहिये। मेरा दल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा चाहता है और प्रशुलक ग्रायोग का भी यही उद्देश्य होना चाहिये।

उद्योगों के संरक्षण के लिये 3 वर्ष की जो अवधि रखी गयी है वह नितान्त रूप से अपर्याप्त है। इस अवधि में कोई उद्योग अपनी प्रगति दिखा नहीं सकता। मेरा अनुरोध है कि यह अवधि वर्ष 1975 तक होनी चाहिये। उद्योगों की भी यही मांग है।

रगरोगन को दो वर्गों में रखा गथा हैं। तैयार म'ल तथा आधा तैयार माल। इस बारे में मेरा निवेदन हैं कि वर्तमान शुल्क दरों में संशोधन किया जाये। एलयूमिनियम उद्योग की स्थिति कुछ समय से खराब चली आ रही है। उत्पादकों को अपना व्यय पूरा करने के लिये भी पर्याप्त आय नहीं हो रही है। यह उत्पादन शुल्क के कारण हैं। अतः सरकार को उत्पादन शुल्क कम करना चाहिये।

मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में सरकार को ध्यान से विचार करना चाहिये। जीपों के उत्पादन में प्रति वर्ष कमी होती जा रही है। वाणिज्यिक प्रयोजनों की मोटर गाड़ियों की उत्पादन संख्या में भी कमी होती जा रही है। हमारे देश में उत्पादन शुल्क की मात्रा बहुत अधिक है। सरकार को इनमें कमी करनी चाहिये।

हमारी सरकार ने आयात पर भी बहुत शुल्क लगा रखे हैं। यदि यह राजस्व शुल्क है तो यह 50 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत क्यों नहीं होती? अवमूल्यन के फलस्वरूप यह स्वतः ही बढ़ गयी है। इस प्रकार हमारे देश में मोटरगाड़ियों की कीमतें अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक है। इन के मूल्यों में 25 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिये। फिर पुरानी मोटर गाड़ियों के लिये फालतू पुर्जों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें आयात करना पड़ता है। इन पर आयात शुल्क कम किया जाना चाहिये। वािराज्य मंत्रालय को वित्त मंत्रा लय के लिये राजस्व एकक करने का कार्य नहीं करना चाहिये।

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई-उत्तर-पूर्व): मैं मोटर गाड़ी उद्योग में यात्री कारों के बारे में कहना चाहती हूं। भारत में यह एक काफ़ी पुराना उद्योग है। यह 1957 से एक संरिक्षत उद्योग है। 1960 में एक समिति ने सिफारिश की थी कि गाड़ियों में दोष होते हुए भी उन्हें फेक्टरी से सड़क पर भेज दिया जाता है।

फिर सरकार ने एक मोटर कार गुगा-प्रकार जांच सिमिति नियुक्त की थी। लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में निर्मित कारों की किस्म में गिरावट आ गयी है। कारों के बारे में बहुत शिकायतें हैं। नयी कारों में भी खराबियां पायी जाती है।

> श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए। } Shri Vasudevan Nair in the Chair

कार उद्योग वाले इन दोषों के लिये फालतू पुर्जे बनाने वालों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। अब लगभग सभी पुर्जे देश में ही तैयार हो रहे हैं। इसलिये सहायक उद्योगों के सहयोग से परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने की ग्रावश्यकता है।

एक अन्य चिन्ताजनक बात यह है कि मूल्यों में उत्तरोतर वृद्धि होती जा रही है। उत्पा-दक कहते हैं कि यह सरकार द्वारा कर आदि बढ़ा देने के कारण है। सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये। सरकार को छोटी कार सम्बन्धी अपने प्रस्तान को कार्यान्वित करना चाहिये। इससे कार के मूल्यों में कमी होगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं समक्त नहीं पा रहा कि मोटर गाड़ी उद्योग को क्यों संरक्षण की आवश्यकता है? आज कारों की कीमतें उत्तरोतर बढ़ती जा रही हैं। सरकार के सभी प्रयत्न असफल रहे हैं। मेरे विचार में तो यह उद्योग के मालिकों के लाभ के लिये अधिकाधिक लालच के कारण हैं। फिर कारों की किस्म घटती जा रही है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि एक उच्चशक्ति प्राप्त आयोग बनायें जो मोटर गाड़ियों के मूल्य ढांचे पर विचार करे और कार के मूल्य कम करने के प्रश्न पर अपने सुकाव दें।

मैं इस आयोग को और संरक्षण देने के विरुद्ध हूं। विदेशों में कारों की कीमतें बहुत कम है। फिर यहां पर यह क्यों महंगी है।

सरकारी क्षेत्र में कार बनाने के प्रस्ताव का क्या बना ? बड़े-बड़े उद्योगपित इस सम्बन्ध में बाधा खड़ी करते रहेंगे। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द): मारतीय प्रशुल्क आयोग बहुत सराहनीय कार्यं कर रहा है। यह हमारे देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है। इसी के फलस्वरूप हमारे उद्योग प्रगति कर रहे हैं। इस बारे में मत भेद है कि मोटरनाड़ी उद्योग को संरक्षण दिया जाये अथवा नहीं। इस बात से सभी सहमत है कि गुण प्रकार में गिरावट नहीं आनी चाहिये। हमें अन्तर्राब्ट्रीय बाजार तथा स्थानीय बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संरक्षण के बारे में निर्णय करना चाहिये। हमें देश के उद्योगों को अधिकाधिक विकसित करना है। उनके आयात को कम करना है ताकि देश आत्मित भंर हो सके। फिर वस्तुओं के गुण प्रकार वा ध्यान रखना है। जापान की कारें बहुत सस्ती है और उनकी विश्व में मांग है। हमें अपने उत्पादों में सुधार करना है और उनके मूल्य कम करने है।

भारतीय प्रशुल्क आयोग सरकार को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देता है। इस आयोग को देश के उत्पादों के गुण प्रकार का स्तर बनाये रखने के लिये सिक्रय रहना चाहिये अन्यथा हमारे देश के उत्पादों की साख जाती रहेगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh): The aim of this Bill is to provide protection to certain industries and to withdraw the same from others. I want that this protection should be provided keeping inview the interests of consumers and not those of big industrialists.

It is very unfortunate that the prices of cars are going up every year. This trend is there for the last two years. The worst part is that the quality of cars is also going down. It is obvious that the profit of manufacturers is going up and the consumer is not being cared for? This matter should be inquired into. I support this demand of Shri Banerjee. We know that the quality in other countries is being maintained. It shows the failure of our Government.

Secondly, no reasons have not been given for continuance of protection to certain items which no longer require it while in case of other items which still need protection it is being with drawn. Now the prices of items on which protection is being withdrawn, will short up. Government should assure that, that will not happen. I want that the interest of consumers should be the uppermost before Government while making a decision.

The demand for a cheap small car is a long standing one. It should be expedited so that we may get a car at a cheap rate.

श्री राजाराम (सलेम): सरकार इस प्रकार का महत्वपूर्ण विधेयक सत्र के अन्तिम दिनों में लाती है। यह जल्दी में पारित कराया जाता है। सरकार कारों के उद्योग को संर-क्षण दे रही है परन्तु इनका गुण-प्रकार घटता जा रहा है। यह स्थिति हमारे देश में ही है। अच्छा हो यदि कारों के ग्रायात की अनुमित दी जाये। अन्य देशों में कारें बहुत सस्ती है। इस संरक्षण के द्वारा सरकार बड़े बड़े उद्योगपितयों को लाभ पहुंचा रही है।

सरकार रंग रोगन को भी संरक्षण दे रही है। परन्तु सरकार को इस बारे में मूल्यों पर नियंत्रण की व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे क्षेत्र में हथकरधे वालों को रंग की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): इस विधेयक के द्वारा सरकार कुछ वस्तुओं पर प्रशुल्क समाप्त करके राजस्व बढ़ा रही है। इससे उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं होगा। रंग रोगन को संरक्षण देने से बड़े बड़े उद्योगपितयों को लाभ होगा। सरकार को छोटे लोगों के हितों का ज्यान रखना चाहिये।

प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदन में ग्रांकड़े दिये हैं। परन्तु साथ में यह भी कहा गया है कि छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी आंकड़े एकत्र नहीं किये गये हैं ' इसका अर्थ है कि ठीक आंकड़े एकत्र नहीं हुए हैं। यदि छोटे उद्योगों के उत्पादन के आंकड़े वास्तव में ग्रिधिक हैं तो संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लाइसेंस विभाग में तालमेल होना चाहिये। लाइसेंस दिये जाने के लिये इसकी बहुत आवश्यकता है।

एल्यूमिनियम की कुछ वस्तुओं को अब भी संरक्षण प्राप्त है और उसी पर शुलक लिया जा रहा है। क्या आपने एल्यूमिनियम की इन वस्तुओं के वास्ताविक उत्पादन का कोई अनुमान लगाया है ? इस बारे में पहले अनुमान लगाया जाना चाहिये।

मोटर गाड़ियों पर संरक्षण से बड़े बड़े उद्योगपितयों को ही लाम होगा। मैं प्रशुल्क का विरोधी नहीं हूं परन्तु इस पर पहले ग्रच्छी तरह विचार कर लिया जाना चाहिये।

{ श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए } Shri R.D. Bhandare in the Ch ir }

श्री चेंगलराया नाय (चित्तूर): हमारे देश में सरकार ने कुछ ही लोगों को कार बनाने का एकाधिकार देरखा है।

"""हमारे देश में तीन प्रकार की कारें अर्थात् हिन्दुस्तान एम्बेसेडर, फिएट तथा स्टैंडर्ड कारें बनाई जाती हैं। किन्तु केवल तीन ही व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने तथा किसी अन्य व्यक्ति को कार बनाने की अनुमति न देने झौर सरकारी द्वेत्र में स्वयं कारों का निर्माण न कर ने की सरकारी नीति के फलस्बरूप नार-क्रोताओं को दुगुने मून्य पर कारें खरीदनी पड़ती हैं और ये कार-निर्माता अत्यधिक मुनाफा ले रहे हैं। इसलिए सरकार को सरकारी क्षेत्र में कम से कम एक छोटी नार परियोजना अवश्य आरम्भ करनी चाहिये और देश में एक या दो गैर-सरकारी निर्माताओं को कार बनाने के लाइसेंस देने चाहिए और इस द्वेत्र में प्रतियोगिता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन निर्माताओं पर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिए। उन्हें प्रति वर्ष नार का मौडल बदलना चाहिए, पर्न्तु बे ऐसा नहीं करते।

जहां तक टायरों का सम्बन्ध है, देश में टायर बनाने के कई कारखाने हैं और सरकार उन्हें संरक्षण देती है जो सराहनीय कार्य है। परन्तु वितरण पद्धति की आर ध्यान नहीं दिया जाता और कोई मूल्य नियन्त्रण भी नहीं किया जाता। वितरण पद्धति में दोष होने के कारण बहुत-सी कम्पिनयां टायरों की कृत्रिम कमी पैदा करके उन्हें ऊ चे मूल्यों पर बेचते हैं और खुले-आम बेचते हैं। इसी प्रकार ट्रैक्टर-टायरों का मामला है। निर्माता लोग उन्हें कुछ इने-गिने व्यापारियों को देकर ऊ चे दामों पर बेचते हैं। इसीलिये इन टायर कम्पिनयों पर नियन्त्रण होना चाहिए, विशेषतः वितरण पद्धति पर, तािक टायर काले बाजार में न जाने पायें। ट्रैक्टर टायरों की कृत्रिम कमी के कारण एक तो किसान को बहुत हािन उठानी पड़ती है और साथ ही उत्पादन को भी हिन पहुँचती है। इसिलिये वितरण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सभी व्यापारियों को समान रूप से टायर मिलें तािक किसानों को उचित मूल्य पर टायर मिल सकें और उनकी कृत्रिम कभी पैदा न होने दी जाये।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): I do not support the Indian Tariff (Amendment) Bill, the provisions of which run contrary to the principles of industrialisation of the country through indigenous sources and opportunities to the foreign industrialists to make profits. The Bill mainly deals with three industries, namely, dye-Stuff, Aluminium and Auto-mobile and Auto-mobile Ancillary industry. The aluminium industry is not being touched, some changes are being made in the protection duty on the Dye-stuff Industry. I am not so much particular about these industries. But so far as the automobile industry is concerned, it has a very important role to play in the life of the country. We need it for our defence, transport and so many other purposes. The present position in respect of this industry is that it is being run by seven or eight private companies which are interested only in their profits and not in the development of the industry. It is, therefore, absolutely necessary for the Government to do something for its development and in the existing circumstances, the only course or way out to do so is to nationalise this industry and bring it into the public sector. This industry would not develop unless it is taken over by the Government. But they are inclined to do so.

The Bill is against the recommendations made by the Tariff Commission in respect of the automobile industry and automobile ancillary industry. They have recommended that the industry should continue to enjoy the benefit of the present scheme of protection. But the Bill seeks to discontinue the tariff protection. Similarly, the commission have stated in respect of the antillarly industry that it is an important adjunct of the main automobile industry and its development reeds to be carefully watched and at a later stage some change should be effected in the duty levied on it. But the Bill see a discontinuance of the tariff protection. Therefore it leaves no doubt that the Bill is going against the recommendations of the Tariff Commission.

About the handicaps in the way of the Car Industry and ancillary industry, the Tariff Commission has observed that its main handicaps are fragmentations, low volume of production and high prices, non-availability of raw materials even where indegenous sources are cacable of supplying them and extensive tie-up through collaboration agreements. The Bill provides sufficient opportunity for the expansion of the foreign capital in the country. It encourages foreign collaboration rather than seeking industrial development of the country through indegenous sources. This is not a good thing. On the one hand the scheme drawn up for the industrialisation of the country is itself defective, is based on the capitalistic approach and not in consistent with the conditions of the country, on the other hand, the provisions of the Bill attract foreign capital in the country and pave the way for exploitation of the Indian markets.

I, therefore, suggest that the Bill should be circulated to elicit public opinion thereon. It should be withdrawn at the moment, and should be brought before the House for consideration only after the recommendations of the Tariff Commission are considered carefully.

With these words I oppose the Bill.

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : त्रियक्तर सदस्य मोटरगाड़ी के सम्बन्ध में बोले हैं जिससे औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय का सम्बन्ध
है, न कि वाणिज्य मंत्रालय का । इसी प्रकार खाद्य उत्पादन तथा रबड़ टायरों का सम्बन्ध भी
अन्य मन्त्रालयों से है । कुछ सदस्यों ने प्रशुल्क आयोग के बारे में कुछ सन्देह व्यक्त किया है ।
परन्तु यह आयोग उद्योगों के लिये बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । यह आयोग संरक्षित
उद्योगों की प्रगति की जांच करने का केवल अपना दायित्व ही नहीं निभाता है अपितु अन्य कार्य
भी करता है । आना दायित्व निभाने के लिए यह आयोग उत्पादन, बिक्री स्टाक तथा अन्य
बातों के सम्बन्ध में सूचना के आधार पर केन्द्रीय सरकार को त्रैमासिक समीक्षा भेजता है
जिसमें संरक्षित क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा होती है । इस आयोग ने कई वस्तुओं के मूल्य ढांचों
की फिर से जांच की है । आयोग बहुत उपयोगी कार्य कर रहा है । प्रशुल्क अधोग का कार्य
संरक्षित उद्योगों की कार्य-प्रसाली की समीक्षा तथा जांच करना है ।

आयोग ऐसे प्रत्येक उद्योग का, जो संरक्षण की मांग करता है अथवा जिसके बारे में उद्योग ऐसा समभता है कि उसे संरक्षण दिया जाना चाहिए, विस्तृत सर्वेक्षण करता है और फिर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देता है।

प्रध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए } Mr. Speaker in the Chair

प्रणुक्त आयोग केवल सरक्षित उद्योगों के बारे में ही समीक्षा तथा जांच नहीं करता बक्ति वह मूल्य ढांचे के बारे में भी गहराई से विचार करता है और तब किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुँचता है। मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं सदस्यों की इन बात से बिल्कुल सहमत हूं कि विकेता बाजार में किस्म की गिरावट की प्रवृति हैं। यह उद्योग देश के सबसे बड़े उद्योगों में एक है, निर्माताओं से बार-बार कहा गया है कि उन्हें अपने मोटर-गाड़ियों की, जिन्हें वे हमारे लोगों को बेच रहे हैं, किस्म सुधारनी होगी और उपभोक्ता जिस स्तर की आशा करते हैं उसके अनुरूप स्तर बद्याने की पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि सरकार ने मोटर-कार क्वालिटी जांच समिति के प्रतिवेदन निलने के पश्चात कुछ कार्यवाहों की है। उदाहरणार्थ कारों की गारन्टी अवधि छ: माहीने से बढ़ा कर 1 वर्ष कर दी गई है। सरकार कारों की किस्म पर कड़ी निगरानी रख रही है।

जहां तक मोटर गाड़ी उद्योग का सम्बन्ध है, हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों का रहना जरूरो है जो एक दूसरे के अनुपूरक तथा प्रतिपूरक है। इसलिए इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रक्रन ही नहीं उटता। लेकिन हम यह सुनिविचत करने का प्रयत्न जरूर करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों में उत्पादन तथा वस्तु किस्म में सुधार हो।

श्रध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"िक 15 मार्च, 1969 तक विषेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव **अस्वीकृत हुया** The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर

प्रस्ताव स्वीकृत हुया The motion was adopted

श्री लोबो प्रभु (उदीपी): मुभे इस सम्बन्ध में अब भी दो बातें कहनी हैं। पहली यह कि मैंने मन्त्री जी से अनुरोध किया था कि वह संरक्षण की अविधि पांच वर्ष तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करें ताकि यह उद्योग अपनी स्थिति ठीक कर सके। लेकिन वह इस प्रश्न पर मौन रहे।

दूसरा अनुरोध मेरा यह था कि मोटर-गाड़ी उद्योग के सम्बन्ध में राजस्व शुल्क 50 से घटाकर 25 प्रतिशत किया जाये ताकि उपभोक्ताओं को लाम पहुंच सके क्योंकि यह राशि निर्माताओं को नहीं बल्कि कर के रूप में सरकार को मिलती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी मेरे इस सुभाव को जो कि संशोधन में रखा गया है, स्वीकार करें।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): The millionaires should not be given protection. They are trying to mislead the Con ress by making false representations. They want to destroy the Congress, which was so dear to Mahatma Gandhi. As such they do not deserve any protection.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: माननीय सदस्य के सुफाव मुफे मान्य नहीं हैं। हमें इस उद्योग पर पूरा यकीन है और मैं समफता हूँ कि वह तीन वर्ष में इतनी मजबूत हो जायेगी कि उसे फिर किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी।

जहां तक शुल्क लगाने का सम्बन्ध है, यह काम वित्त मन्त्रालय का है ग्रीर वह विभिन्न पहलुओं और वस्तुग्रों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए शुल्क लगाता है। माननीय सदस्य को मालूम है कि अवमूल्यन पूर्व मोटर गाड़ियों के पुर्जी पर 60 प्रतिशत शुल्क था और अवमूल्यन के पश्चात उसे घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसलिए उसे और कम करने का कोई प्रश्न नहीं है।

ग्रध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने संशोधन पेश नहीं किये हैं। इसलिए मैं विश्वेयक के खण्ड को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया। Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1, ग्रधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये। Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the B.H.

श्री मु म्मद शकी कुरेशी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): अवमूल्यन के पश्चात प्रभावी दर 40, 27 है है, किन्तु मद संख्या 66 (1) के सम्बन्ध में यह 40, 20 है। इस अन्तर का क्या कारण है ? क्या दोनों प्रमावी दरें है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: ये दरें भिन्न भिन्न मदों के लिये हैं, एक के लिये 27 है, दूसरी के लिये 20।

ग्रध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

'कि विधेयक पारित किया जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुन्ना The motion was adopted

सभा के कार्य के बारे में RE: BUSINESS OF THE HOUSE

श्राध्यक्ष महोदय: अगले कार्य पर विचार करने से पहले मैं सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि सभा इसके बाद बिहार सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में विचार करेगी और तत्पश्चात् दो और विषयों पर विचार-विमर्श करेगी। संविधान (संशोधन) विधेयक पर हम कल चर्चा करेंगे।

बिहार के संबन्ध में उद्घोषणा PROCLAMATION IN RESPECT OF BIHAR

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चृव्हाग्रा)ः मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"िक यह सभा राष्ट्रपित द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत बिहार के बारे में जारी की गई दिनां हु 29 जून, 1968 की उद्घोषणा को 25 जनवरी, 1969 से आरम्भ होने वाली 6 मास ी अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसा कि हम सभी को विदित है कि राष्ट्रपित की यह उद्घोषणा 29 जून, 1968 को जारो को गई थी और राज्य समा द्वारा 22 जुलाई को और लोक सभा द्वारा 25 जुलाई, 1968 को उसका अनुमोदन किया गया था। इस उद्घोषणा की छः महीने की अविध 24 जनवरी, 1969 को समाप्त हो जायेगी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वहां जाकर सभी राजनितिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद यह सिफारिश की है जिसकी वह घोषणा भी कर हुके हैं कि वहां पर मध्याविध चुनाद 9 फरवरी को आयोजित किये जायेंगे। इसलिए इस उद्घोषणा की अविध बढ़ाना अत्यावश्यक हो गया है। स्वाभाविक है हम सभा से छः महीने की अविध की अनुमित मांग सकते हैं। लेकिन सरकार का इरादा नहीं है कि अगले छः महीने तक वहां राष्ट्रपित का शासन जारी रखा जाये। इसलिए चुनावों के तुरन्त बाद वहां मन्त्रिपरिषद बनेगी और यह उद्घोषणा लागू नहीं रहेगी।

संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से जो सलाहकार समिति नियुक्त की गई थी उसकी दो चार बैठकें हुई हैं एक बार पटना, श्रौर कल और आज ही हम चार घंटे तक राज्य की समस्याओं तथा विधान सम्बन्धी कुछ ब तों पर विचार-विमशं किया विशेषतः कल और आज हमने बिहार की धूमि समस्याओं विशेषतः छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं से सम्बन्धित तीन बहुत महत्वपूर्ण उणायों को मंजूर किया। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के तुरन्त बाद इस प्रश्न को श्रध्यनार्थ लिया गया और एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई जिसने इस समस्या पर विचार किया और सिफारिशों की जिनके आधार पर हमने एक विधेयक तैयार किया सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदन विया गया है और मुफे यकीन है कि उसके आधार पर राष्ट्रपति अधिनियम की घोषणा की जायेगी।

अलवत्ता, पिछले छ महीनों में बिहार के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, विशेषत बाढ़ की दुखद घटना का जो राज्य प्रशासन के लिए एक चुनौती थी और राज्य प्रशासन ने उसका मुकाबला करने के लिए प्रपनी पूरी कोशिश की । स्वभावतः वहां विद्युती—करगा तथा कृषि—सुबिधाओं की अधिक मांगें हैं। सरकारी कर्मचारियों की भी समस्या है। वे और अधिक महगाई भत्ता ग्रादि मांग रहे हैं। हमने मान लिया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न फिर वित्त का आता है। इसलिए जब तक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय नहीं किये जाते उनकी मांगों को तत्काल पूरा नहीं किया जा सकता। निर्वाचित सरकार को सत्ताहढ़ होने के बाद इस सम्बन्ध में तुरन्त कुछ करना पड़ेगा।

हम चाहते हैं कि वहां जल्दी ही निर्वाचन हों और निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य में लोकतंत्र की पुनः स्थापना करने का दायित्व अपने ऊपर लें और लोगों को अपेक्षित कुशल और निर्दोष प्रशासन प्रदान करें।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka): Every party in the State is anxious to see that mid-term elections are held in a peaceful atmosphere. But the law and order sitution in the State is very serious and subversive elements are emerging. Naxatite forces are raising their heads and the incidents of Kerala are being repeated there. Even the public property is not safe there. It is, therefore, absolutely necessary to take steps to bring normalcy in the State so that the elections could be held peacefully.

The Pakistani elements and the Chinese agents on our borders are acting in collusion with each other. I would, therefore, request the Home Minister to keep a strict watch on their joint activites in the border areas for it is these people who are at the back of all disorders in the State. Steps should be taken to see that these forces are checked and dealt with firmly so that normalcy could be restored in the State.

To-day a new party by the name of Shoshit Dal, founded and led by Shri Vindheshwari Prasad has emerged in the State politics with a dangerous slogan based on casteism. They are creating communal tensions and arousing and spreading feelings of hatred among backward classes against the high caste people and this has vitated the entire atmosphere in the State. The Home Minister should see that stringent action is taken against those who are making such virulent propaganda which is against the election laws.

As appeared in the Press' the Aiyer Commission has asked Shri K. B. Sahay to give an explanation about his assets. It has been found that Shri Sahay was maintaining a personal account of Rs. 11 lakhs in the banks in addition to a fairly handsome amount deposited in the names of his wife and sons. But to our utter surprise, the Central Finance Department is playing the role of a mere observer and has not taken any action against him.

As regards education on the one hand, crores of rupees are being spent on Universities and Colleges there which are producing more graduates who are only adding to unemployment, and on the other hand, primary schools are being neglected. In rural areas the primary schools are being run in the open. Arrangements should be made to house them at least in Kachha buildings. Therefore steps should be taken to see that a certain percentage of the amount being spent on higher education is utilised in the construction of buildings for the primary schools.

As regards health, there are not enough hospitals in the State and there is dearth of doctors and most of the hospitals are without doctors. In my own constituency, Banka, there is a very old hospital which is without a doctor for the last six mouths. At present there is a lady doctor only. The hospital serves a large area of the State. Also, there is no electricity in this hospital. I would, therefore, request the Home Minister ensure that arrangents for such small things are made and inconvenience caused to the people is removed.

As regards irrigation, water is easily available in the tubewells for irrigation purposes and people have installed pumping sets. But they are not given power connections even though the power line passed through Their fields, I have invited the attention of the Government to this matter in writing also. The Government should see that connections are given to agriculturists.

The condition of roads in Bihar is pitiable. Rural areas which constitute 80 percent the population of the State have been neglected. Most of the roads are 'Kuchha' and even jeeps can not run there. It is, therefore, necessary that in the next Fourth Five Year Plan, adequate attention is paid to roads in the State.

Bihar abounds in minerals but the Government have not taken steps to fully exploit them. The recent mineral survey conducted in the State has revealed that there are copper deposits in the Bhagalpur district. But the progress made in regard to its exploitation is very slow and even drilling operations have not yet started there. The Khetari Copper project which was scheduled to be commissioned in 1967 could not be completed so far and we are loosing foreign exchange of the order of Rs. 16 lakh, per day on this account. Since copper is greatly needed for the country, the matter should be expedited.

Shri Mrityunjay Prasad (Maharaj-Ganj); At the very outset, I would like to invite the at ention of the Government to security problem of the State. The law and order situation is deteriorating and life and property are not safe. The naxalite forces are raising their ugly heads endangering the security of life and property. It is necessary for the Government to take immediate steps to check their activities otherwise life would become unsafe.

There is acute poverty in the State. There are public undertakings in the State which absorb outside labour and that too at higher wages. The local people, who are almost on the verge of starvation do not get employment even at lower rates. It is most unfair to allow this State affairs to cintinue. In order to improve the economic Dondition of the people there it is necessary to give them more employment rather than doing so in the case of outsiders. These workers are going to other States in search of employment. There is ample scope for their employment in various factories and undertakings in the State and they have still to face unemployment. The Government should try to see that the people of Bihar are their due share in employment at least so far as unskilled jobs are concerned.

It is said that Bihar is rich in minerals. But most of the resources are in the hands of outsiders who do not belong to this State and all profit goes outside the State. The only thing left for us is wages and that too are being taken away. Like this.

So far as small scale industries are concerned, 238 training cum production centres were established in the State But a decision was taken in September. 1968 to close down 113 such centres. This decision was taken in view of their runing at a loss. Have the Government considered why these Centres were suffering this loss? This was all because of the inefficiency of the staff employed there. They were not fit enough for the job even then they were intrusted with it.

The work of Tirhut Canal has not yet been completed All the money allocated for the purpose has already been spent, with the result that the work of this canal has been stopped for the last one and a half years. It is high time that work of the canal be restored so that the people of the area could be benefitted. Electricity should also be supplied to farmers as per their demand for irrigation puropses as there is no shortage of electricity there.

I would now like to invite the attention of the House to a very important question relating to our borders with Nepal. China has constructed roads running parallel to our boundary on the northern border of Bihar in the Nepalese territory. Why this has been done? Only with a view to supply arms and other war material in time of war. It order

to counteract this threat it is necessary for us to take retaliatory action. So we should also construct roads, lay rallway lines and improve our transport and communication system in the border areas.

Smuggling on a large scale is going on, on our borders. Chinese goods in large quantities are being smuggled into the country particulary in the border areas. The trade agreement entered into with Nepal has also helped increase smuggling. It is necessary to do something to stop it.

With these words I support the motion.

ग्रध्यक्ष महोदय: समय की कुछ सीमा तय होनी चाहिए वे लाग बड़ा सहयोग दे रहे हैं। विपक्ष की ओर से चार माननीय सदस्यों तथा दूसरी ओर से भी तीन या चार सदस्यों ने बोलना हैं। यदि प्रत्येक माननीय सदस्य 5,6 अथवा सात मिनट से अधिक न ले तो हम ठीक समय पर चर्चा समाप्त कर सकेंगे।

Dr. Surya Prakash Suri (Nawada): With the appointment of advisors to the Governor, it was hoped that there will be a better administration in that area, but we find no change and these advisors also wasted their time in attending different functions as the earlier congress or S. V. D. Ministers used to do. These advisors also did nothing to improve the administration. The purpose for appointing the consultative committee was, therefore, defeated.

The hon. Members from the Opposition have been complaining that conversions is going in some parts of the country particularly in Chhota Nagpur. I agree and also want that it should be totally brought to an end. But it cannot be stopped by the Govt. as our Govt. is a secular one. Now, if we want that our countrymen should not go to a particular religion viz. the christianity, we should preach our own religion in such a way that they themselves do not like to be converted to Christianity. This is only the right and effective way to stop this sort of conversion. We should also try to find out the reasons why people are affected by these Christian missionaries, perhaps they donot know that even the foreign countries are much influenced by our scriptures like Geeta and Puranas. We should collectively work for stopping this conversion and that propaganda which is going on through 'read book'. But the administration should also be active stop those unruly people who, for their political motives, creat troubles in that area by inciting people against one another. The administration has to be vigilant about all that.

Now there is no scope for the M. L. As, to express their views in regard to the various grievances of the people of this State since there is no Legislative Assembly. Although the hon. Home Minister has heard us in the meetings of the Consultative Committee and we hope that he would take necessary actions, but I once again say that the conditions of different pilgrim hospitals is very grave. Particuly in Gaya, the condition of two Women's hospitals, and also one that for the men, is very pitiable. The roo's of the patients' rooms leak during rains there by causing great inconvenince and discomfort to the patients. The same is the condition in Nawada's Govt. Hospital. Owing to shortage of beds, patients are made to lay on the floor irrespective of their nature and intensity of pain or disease. I invite the administration to go and see the things themselves.

With regard to recovery of loans from the farmers, the administration is using very strict measures. The officers, accompanied by armed police, go to the farmers for

recovery of loans taken by them but if the farmers are found unable to pay the same, the officers take away the farmers' belongings, and put them into jails also. Farmers, as you know well, are not in a position to repay the loans owing to drought etc. during the last several years. No doubt, this time they have got a very good crop but first of all they will have to settle those of their loans etc. which they took during their last hard times. It is, therefore, necessary that the recovery of loan form these farmers should be stopped till the next Rabi crop is ready. The Govt. should adopt a lenient attitude in this regard.

Govt.'s attention has been drawn towards the grievances the Zamindars also. They have not received the compensation for lands for the last 15 years.

The specific point that I want to emphasise upon here is that the teachers should not be given the duties of presiding officers in the coming elections. We are opposed to it

Shri P. G. Sen (Purnea): There have been many irregularities with regard to implementing the Education Department Rules in a minority school named Bhatte M. E. School. Finding the appointment of the Headmaster, not according to his own choice, the S. D. O. Education, created a troubles and stopped the payment to the teachers. Their payment was released only when they threatened to go on hunger strike. The significant aspect of this case is that case is that the pay of the teachers was, no doubt, drawn but it was not paid to them. Besides this, the management never cased for the Department rules and appointed teachers in that school. These facts can very well be verified by the hon. Minister. The poor Headmaster of that school has not received his salaries for the last two years. The S. D. O. has been having his own ways and he has threatened to set up an adhoc committee in place of the present management committee. The poor Headmaster is suffering for no fault oi his. Similar is the case of the Headmaster in Purnea District School. He too has not received his 15 day's salaries. The administration should see to it and get him his payment.

These little things develop into havoes like hunger strike etc. The authorities do not make payments and tlu teachess on strike. Such things should be repeated.

Ours is an irrigated area and when the farmers do not get water at those high places, naturally they develope heartburning. But this time that area has been affected by heavy floods. Dr. K. L. Rao has also reported that the loss in Purnea area is the most. Therefore, the Govt. should provide some relief to the farmers by suspending the recovery of loans for some time.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): We had hoped that on his arrival to this House, the present Home Minister would contribute a lot to the country's progress. Our country's democracy will be protected and new conventions would be established. But we have found that he wants to do everything with stick only.

After the last General Elections, the Congress made all out efforts to dislodge all non-Congress Governments. Bihar also has been their victims. Although the hon. Home Minister states that he has discussed the problems of Bihar with the Consultative Committee but we have found that he has never paid any heed to the advice of this Consultative Committee.

Whever there is Governor's rule, we find nothing but excesses, atrocities and corruption. Nothing is secured in the way the authorities and the police are functioning.

My point is that a Governor's rule is never preferable to a people's Government. In the Governor's rule in Bihar, law and order situation is worse. The State Govt. employees are demanding higher pays but the Govt. say that they have no money to pay; although Govt. finds enough money for constructing big bungalows and also for appointing high ranking officers etc. Similar is the case with the teachers there. The Govt. has not cared to hold any inquiry into the incidents that took place in Muzaffarpur. The Congress has been looting and destorying the country for the last 21 years. They con't allow any non-Congress Govt. to flourish or establish in any part of the country

I want to appeal to the hon-Minister not to believe much in Governor's rule. It is never preferable to a people's popular Govt. We are not bothered about any party's rule, but certainly we want a stable Govt. But I am afraid, the Central Govt. never allow it. They are always misguided by their high officers in the Home Ministry.

Finally, I would request the hon. Minister to do something for the betterment of States under his rule. He should save the people from the fear of bureaucracy in the Governor ruled States, and he should not encourage or repeat Governor's rule after the next elections.

श्रीकार्तिक उरांव (लोहारउगा): मैं बिहार में राष्ट्रपित शासन की स्रविध को बढ़ाने वाले इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, क्यों कि राष्ट्रपित शासन का लागू होना देश में आपत्तकाल की स्थित की प्रतिच्छाया होता है। इससे यह पता चलता है कि हम वहां प्रजातांत्रिक सरकार बनाने में असफल हैं। यदि मुक्ते अधिकार प्राप्त होता तो मैं तो इस अविध को छः वर्ष के लिये बढ़ा देता क्यों कि सरकार अथवा प्रशासन वही अच्छा है जो वास्तव में अच्छा और सफल है। राजने तिक दल तो बस एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त रहते हैं।

बिहार में राष्ट्रपति शासन के परिगाम स्वरूप निश्चय ही लाभ हुआ हैं। विशेष रूप से छोटा नागपुर में तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है। रांची नगर में जहां एक किनारे से दूसरे किनारे तक भुगियों आदि के कारण जगज ही मंगल दिवाई देता था, अब वहां तब साफ हो गया है और वहां पार्क करने के सुन्दर स्थान बना दिये गये हैं वहां के आदिवासियों के हितों के लिये मी काफी कार्य किया गया है। इस क्षेत्र में पहले बड़े उपद्रव हुआ करते थे और आदिवासियों को लोग उपद्रवी समभा करते थे। परन्तु वास्तव में यह बात न थी। उन गरीबों को तो खूटा और शोषित किया जाता था।

छोटा नागपुर यद्या अनेक औद्योगिक समूह है परन्तु उनमें वहां के स्थानीय लोगों और आदिवासियों को रोजगार नहीं दिया जाता। वहां सभी व्यक्ति बाहर से भर्ती किये जाते हैं। माना कि ये राष्ट्रीय परियोजनायें हैं और वहां अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को भर्ती किया जाना चाहिए परन्तु चपरासी से लेकर किसी ऊंचे पद तक सभी स्थान बाहर वालों से भरे जाते हैं। सभी शिक्षा संस्थानों में भी अध्यापक उत्तर बिहार के क्षेत्रों के हैं। यद्यपि छोटा नागपुर के लोग भी शिक्षित हैं परन्तु उन्हें द्वां का अवसर नहीं दिया जाता। छोटा नागपुर का एक मात्र विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय घाटे में चल रहा है परन्तु सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सिचाई और परिवहन सुविधाओं के बारे में इस क्षेत्र के साथ सौतेला ध्यवहार किया जा रहा है। सभी ओर से यह चेत्र अपेक्षित रहा और किसी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में इसकी दशा सुधारने में रुचि नहीं दिखाई। जो कुछ सुधार हुग्रा है वह केवल इस

राष्ट्रपति शासन के दौरान ही भूमि वायस दिलाने, उधार लेन देन ग्रादि बुरी बातों को रोकने हेतु कुछ कानून बनाये जा रहे हैं। अतः सरकार वहीं अच्छी है जो कि लोगों के लिए कुछ ग्रच्छा कार्य करे।

मैं निवेदन कर गा कि सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र छोटा नागपुर और संथाल परगनों के लिये और अधिक धनराशि दे। यद्यपि वहां कई परियोजनाएं है परन्तु फिर भी यह इलाका पिछड़ा हुआ है वहां लोग बहुत गरीब हैं। हमारी औद्योगिक नीति का उद्देश्य यद्यपि क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने का है परन्तु वास्तव में यह असन्तुलन दूर नहीं हो सका है।

भविष्य में हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जहां किसी दल का बहुमत न हो वहां वहां सरकारें न बनाने दी जायें और वहां सीधं ही राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया जाये । उस राज्य में संयुक्त सरकार बनाने की अनुमित कभी न दी जाये। ऐसी सरकारें बुरी (तरह असफल रही है। ऐसा करने से देग को बड़ा लाभ पहुंचेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तात का समर्थन करना चाहुंगा।

Shri Ram Charan (Khurja): Since his arrival in the Central Govt. Shri Chavan has made hismself expert in two things firstly in imposing Presidents Rule, and secondly in crushing the Govt. employees' strikes.

The law and order situation has become very deplorable in Bihar under Presidents Rule. There are broad daylight murders and the people are not provided with police protection. Harijans are the main victims since they have neither any defender nor money. No body bothers to give them physical protection.

A large number of tribals and Harijans are changing their religions and adopting Christianity. Whereas the Congress Govt. have not been able to provide these people anything at all and as a result of which their condition is deteriorating day by day. The foreign missionaries are exploiting them and converting these poor people to Christianity. Thus conversion of the Harijans and the tribals is going on large scale.

Bihar is subjected to two horrible menaces-one is the drought and the other is floods. These calamities ruins villages together, either in floods or by drought. The Govt. have not set up any industry during the last 3 Plans for the last 20 years so as to enable the people of this State to get some employment. The result is that the labourers go to Assam. Bengal or U. P. etc. in search of employment. The Govt. have not taken any care of these poor people.

They have not completed the Gandak project so far. Had it been done the farmers could have so some irrigation facilities which they need most. Similarly, different grants in aid are not made available to the Harijans and Adivasis. The officials misappropriate that money in between before it could reach those power people, These malpractices should have been checked atleast during this Presidents rule. I want to khow why more many was not given for the welfare of the Harijans and the tribals?

The Govt. Should, therefore, change their policy to bring in President's rule every now and then otherwise it would bring very bad results. If they continue this policy, they will be inviting communism in the country. I, therefore, reques that instead of imposing Presidents rule, they should set a popular Govt. in Bihar.

There has been five cracks in Kosi embankment but after the inquiry only an overseer was suspended not those high officials, like Executive Engineers who had taken more bribes. Govt. have never implemented the recommended of any inquiry whether against certain act of corruption, some officer or some political party. I appeal that very strict action should be taken against such officers.

The Central Govt. although provided financial help to the Harijans and poor labourers who were badly affected by the Kosi floods but the officers did not pay the money to those poor people. They were beaten by the B.D. O. instead. The Govt. have not taken any action on the complaints received in this connection.

I, therefore, suggest that the Govt. should never impose Presidents rule in any part of the country, otherwise democracy will be put to peril. They should not forget the ideals of socialism. They should help the 'Harijans and the triba's as much as they can if they want to avoid communism and preserve nation's democracy.

Shri Shiv Chandika Prasad (Jamshedpur): During the President's rule, the action taken by the Bihar Govt. in regard to the release of land to the great freedom fighter Shri Tana Bhagat and also to other Adivasi Comrades is very much appreciated. I congratulate the hon. Home Minister for bringing in a legislation in this regard. Now those people will get their land back.

It is quite true that nature has given all its blessings to B har; and the Govt. too have set up a few big factories there; and but it is very unfortunate that the per capita income in Bihar is the lowest in the country. All out efforts should, therefore, be made by all Governments, whether President; rule or a democratic popular Govt. to improve the economic condition of Bihar. For this purpose, although the Govt. have introduced the Tenancy Act in Chhota Nagpur under which they intend to bring agricultural reforms in that area. But in addition to this, it is also very necessary that at least one tractor and one pumping set should be provided in each block. This would help increasing production particularly in Chotta Nagpur and Santhal Pargana.

Chotta Nagpur is in much need of minor irrigation and power facilities. The authorities have not paid proper attention towards this urgent necessity. Similar is the case in Jamshedpur. For Barhgosha area, they sanctioned an electric line, invited tenders, but the work on it has still not been started.

Likewise, the authorities constructed houses for Low Income Group people but they have not provided even the basic amenities that of water, electricity etc. I would request the Govt. to pay adequate attention towards this. Similarly more money should be given for providing more loans to the Adivasis of Chhota Nagpur and Santhal Pargana.

I would request the hon. Railway Minister to set up a "gumti" instead of an unmanned railway crossing in Telco area. The Bihar Govt. may kindly provide land to the railway authorities for this purpose,

Finally, I would like to mention that lawlessness and crimes are on continuous increase in Bihar. I agree that the authorities are taking necessary action in this regard, but more stringent measures are required to be adopted to deal with the situation, so that these cases of broad-day-light thefts and murders particularly in Jamshedpur area are stopped forthwith.

With the above words I express my thanks to you.

Shri Kames! war Singh (Khagaria): The hon. Home Minister has just now stated that Bihar had to face so many difficulties during the last 6 months. Let me frankly say that all these troubles were created by the Central Govt, itself. These were not god-given. They say that some rats caused floods in Kosi. But the fact is that the big officers were responsible for the cracks in Kosi. Whereas the big rats i. e. these big officers misappropriated the money, the Govt. suspended a small rat that is, an overseer in this behalf. No action was taken against those who were really corrupt.

The law and order situation in Bihar is deteriorating day by day since the imposition of President's rule there. The Home Minister claims that the situation has improved, but the fact is that many reactionary and anti-national forces have raised their heads. Life is not at all secure in that State. Even the Chinese element has got encouragement In Khagria Division the harvested crop of a farmer was looted in broad day-light. This all is going on under the nose of the authorities there.

The Govt have been using very stringent measures in recovering loans from poor farmers in villages. On one hand the Govt ask the farmers to increase production, but on the other hand, they are auctioning the cattle like oxen etc. of those farmers. Some of them have been arrested also. The result is that out of fear the farmers are hiding themselves in jungles and fields. The money meant for the development of villages is actually being spent on the development of the cities.

In so far as the question of supply of power is concerned, about 200 tubewells have been installed in Khagaria sub-division and Bakhri and Balia and power has not been-supplied to them for the last six months. Even the existing tubewells are not being supplied power regularly. Instead of recovery of loan from the farmers Government should give compensation to them. The condition of hospitals is deplorable. Khagaria is backwrad area but there is no X-Ray Plant. A building of a T B. hospital has been constructed but the hospital has not started functioning.

A lady had donated money for a hospital in Jamalpur, Khagaria sub-division with the condition that a lady doctor should be appointed in that hospital but the same has not been done so far.

The people of Khagaria have contributed for opening a college and they require some land for this purpose but Government is not taking action to acquire the same. Moreover teachers do not get their salaries in time which affects the education of children and Government is responsible for it.

Khagaria sub-division and Begu Sarai are backward areas of Bihar. In order to connect national highway of Saharsa with Maheshpur a road was approved and tender was also called and passed but further action has not yet been started. President's rule is responsible for it. The condition of other roads in these areas is also deplorable.

A Pakat-Dam was proposed to be constructed in Khagaria sub-division which had to provide irrigation facilities to lakhs of acres of land but no progress has been made in this respect. Similarly a Gragri dam is essential for Beldaur but Government is paying attention towards it. Parvatta dam over river Ganga has not yet been repaired. Government will go on thinking while another flood would come.

A bridge in Sultanganj should be constructed as it is essential for the development of backward areas. Government should pay more attention towards these areas instead of paying special attention towards Delhi and other big cities.

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हारण): में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात को गौरव की बात नहीं समक्ता। राष्ट्रपति शासन तो इस बात का द्योतक है कि राज-नीतिक दल लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने में असफल रहे हैं। परन्तु किसी न किसी प्रकार से शासन तो चलाना ही है और राष्ट्रपति शासन का यही प्रयोजन है। जब बिहार में प्रशासन बिल्कुल ठप्प हो गया था तभी हमें राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। वहां पर स्थिति काफी खराब हो चुकी थी और हमने वहां की स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया है।

सर्वप्रथम वहां पर कर्मचारियों का साहस बिल्कुल समाप्त हो गया था। हमने उनमें इस साहस को पुनः जागृत किया। कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि विद्यार्थियों और पुलिस के बीच एक महीने में औसतन 30 भड़पें होती थी। परन्तु पिछले कुछ महीनों में विद्यार्थियों और पुलिस के बीच कोई विशेष भड़प नहीं हुई। सभी द्वेत्रों में ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं। यह ठीक है कि कुछ वित्तीय कठिनाइयों के कारण सिचाई तथा देहातों में बिजली लगाने के कार्यक्रम को अच्छी प्रकार से आरम्भ नहीं किया जा सका।

यह कहना उचित नहीं कि राष्ट्रपित शासन ही बिहार में बाढ़ जैसी आपित के लिये उत्तरदायी है।

Shri Kameshwar Singh: It has happened because of their negligence. Two perso have been suspended for that.

श्री यशवन्त राव चव्हाएा: यह एक अलग बात है, यह हमारा कर्तव्य है कि यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया जाना है तो हम उसे दण्ड देने से हिचकिचाते नहीं। यदि बाढ़ आने के समय प्रशासन ने कोई लापरवाही की है तो मैं उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिये तैयार है।

कुछ माननीय सदस्यों ने दीर्घकालीन कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ सुभाव दिये हैं। मैं इस सम्बन्ध में कोई वचन नहीं दे सकता। परन्तु शेष कुछ महीनों में जो कुछ सम्भव होगा, हम अवश्य करेंगे। माननीय सदस्यों ने जो अच्छे-अच्छे सुभाव दिये है हम उनका ध्यान रखेंगे। यह ठीक है बिहार विकास कर सकता है। वहां बहुत से प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं। वहां पर कुशल प्रशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व राजनीतिक दलों पर है। दुर्भाग्य इस सम्बन्ध में अभी तक सफलता नहीं मिली है।

यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं आशा करता हूँ कि बिहार के राजनीतिक नेता उस राज्य को स्थायी, योग्य ग्रीर कुशल प्रशासन दे सकेंगे जिससे प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का राज्य के लाभ के लिये उपयोग किया जा सके।

उपाष्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :---

"िक यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत बिहार के बारे में जारी की गई दिनांक 29 जून, 1968 की उद्घोषणा को 25 जनवरी, 1969 से

आरम्भ होने वाली 6 मास की अग्रेतर अविध के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव पारित हुन्ना The motion was adopted

निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियमों को रद्द किये जाने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: ANNULMENT OF CONDUCT OF ELECTIONS (SECOND AMENDMENT) RULES.

भी भीनिवास मिश्र (कटक) : में प्रस्ताव करता हूँ : —

"यह सभा संकल्प करती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 25 अप्रैल, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1520 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 25 जुलाई, 1968 को समा-पटल पर रखे गये थे, रद्द कर दिये जायें।"

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।

चुनाव नियम 40 के अन्तर्गत किसी अन्धे या अशक्त व्यक्ति के साथ कोई परिचर या प्रतिपत्री (प्राक्सी) की व्यवस्था है। अब इस नियम में संशोधन कर दिया गया और अब नियम 40-क के अनुसार यह उपबन्ध अशिक्षित मतदाता के सम्बन्ध में भी लागू कर दिया गया है। इसके दो पक्ष है। एक औचित्य और दूसरे ऐसी बातें कानूनी रूप से भी न्यायोचित होनी चाहिये। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 के अन्तर्गत नियम बनाने की व्यवस्था है उसमें लिखा है कि सब प्रकार के चुनावों में, नियमानुसार मतदान होगा और प्रतिपत्री (प्राक्सी) द्वारा मतदान की अनुमति नहीं होगी। जहां तक अन्धे और अशक्त व्यक्ति का सम्बन्ध है, हमें कोई आपित नहीं है परन्तु अशिक्षित व्यक्तियों के लिये यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। यह भशिक्षित व्यक्ति की इच्छा शक्ति का अधिकार उसके साथ आने वाले व्यक्ति को देने के समान होगा। साथ आने वाला व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का एजेण्ट भी हो सकता है। इस प्रकार वह राजनीतिक दल घन का प्रलोभन देकर ऐने मत अपने पक्ष में कर सकता है। यह एक औचित्य का पक्ष है।

'प्रावसी' शब्द का अर्थ है ''एक व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिये दूसरे व्यक्ति का नियुक्त किया जाना" और हमारी संकल्पना और हमारे कानून के भ्रनुसार मतदान का अर्थ है अपनी इच्छानुसार चिन्ह लगाना। अतः यदि कोई भ्रन्य व्यक्ति चिन्ह अंकित करता है तो

इसका अर्थ है 'प्राक्सी' द्वारा मतदान है जो निश्चित रूप से निषिद्ध है। फिर संशोधित रूप में नियम 40 विधान समा के सदस्यों द्वारा और परिषद निर्वाचिन क्षेत्र में लागू होता है और यह मतदान राष्ट्रपति के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव के सम्बन्ध में होगा। मेरे विचार में यह हमारे लिये शर्म की बात होगी कि इस प्रकार के निर्वाचन में भी अशिक्षित व्यक्ति भाग लेंगे। फिर भी देश में यदि विधान सभा के अशिक्षित सदस्य अथवा अन्य स्थानों पर अशिक्षित व्यक्ति है तो उनके लिये चिन्ह निर्धारित किये जा सकते हैं।

अतः इस प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन होगा। इसमें कोई औचित्य नहीं है।

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं इस सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 169 (2) (ग) का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसके अन्तर्गत मतदान के सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं। इस नियम में इस बात की भी व्यवस्था है कि शारीरिक रूप से अक्षम और अशिक्षत लोग किस प्रकार मत डालें। यह कोई नई बात नहीं है। निर्वाचन का संचालन नियमों के नियम 25 में लिखा है कि यदि कोई मतदाता अशिक्षित, अन्धा, अथवा किसी अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण डाक द्वारा भेजे गये मतपत्र पर चिन्ह नहीं लगा सकता और घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो वह उस मत-पत्र को सक्षम अधिकारी के पास ले जा सकता है और अपना मत दर्ज करवा सकता है। नियम 40 क सामान्य नियम 39 का अपवाद है। उसमें लिखा है कि यदि पीठासीन अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि कोई व्यक्ति अन्धा या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक अक्षमता के कारण चिन्ह पहचानने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी उसे उसके साथ एक और त्यक्ति मतदान के कमरे में ले जाने की अनुमित देगा जो उसकी इच्छानुसार मतदान करे। इस व्यवस्था के बिना एक अन्धा व्यक्ति कैसे मतदान कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: यहां अशिक्षित व्यक्तियों का प्रश्न है। क्या अशिक्षित होने की सीमा की कहीं परिमाषा की गयी है।

श्री गोविन्द मेनन: नियम 70 में नियम 40 को अशिक्षित मतदानाओं के सम्बन्ध में भी लागू कर दिया गया है।

परिषद चुनावों में कुछ निर्वाचक नयी बनी जिला परिषदों, पंचायत समितियों आदि के होते हैं और परिषद का चुनाव एकल सक्रमणीय मत पद्धित के अनुसार होता है । संसदीय समितियों के निर्वाचन की तरह विधान सभाओं के चुनावों में 20, 30 या 40 व्यक्तियों की सूची मतदाता को दे दी जाती है और उससे यह आशा की जाती है कि वह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां चिन्ह उन व्यक्तियों के नामों के आगे लगा दे जबकि उन पर कोई प्रतीक अंकित नहीं होता । यह एक कठोर सत्य है कि इन निर्वाचकों में ग्रशिक्षित व्यक्ति भी होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: जिला परिषदों के निर्वाचन के स्तर की मुक्ते जानकारी है । परन्तु हमें अशिक्षित होने की कोई सीमा निर्धास्ति करनी चाहिये अन्यथा हम इस कठिनाई को दूर नहीं कर सकेंगे।

श्री गोविन्द मेनन: नियम यह है कि पीठासीन ग्रिधकारी को विश्वास हो जाना चाहिये कि निर्वाचक मतदान करने में असमर्थ है। फिर निर्वाचक को अपना साथी स्वयं निश्चित करना होता है और पीठासीन अधिकारी उससे गोपनीयता की शपथ लेता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर यह नियम लागू किया गया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि इन कारणों से बहुत से मतदाता अपना मतदान नहीं कर सकते। मेरे विचार में यह नियम ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या साक्षरता इतनी कम है कि इतने अधिक मतदाता मतदान नहीं कर सकते ? अब प्रश्न पूछे जायेंगे।

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ़): एकल संक्रमगीय मत पद्धित के अनुसार 1952 से चुनाव होते रहे हैं। तभी से जिला परिषदों के सदस्यों को वोट देने के अधिकार दिये गये हैं। अब इनमें पंचायत समिति के सदस्य सिम्मिलित किये गये हैं।

हमारे देश में साक्षरत बढ़ रही है। वर्ष 1952 के ग्रंपेक्षा अब स्थित में काफी सुधार हो चुका है। अतः अब कोई नयी समस्या पैदा नहीं हुई जिसका समाधान किया जा रहा है। फिर निर्वाचन आयोग ने ऐसे आंकड़े नहीं बताये जिनके मत-पत्र इन अशिक्षित होने के कारण रद्द किये गये हों। नाम के सामने प्रतीक रखने से अशिक्षित व्यक्ति भी प्रतीक की पहचान करके मतदान कर सकता है। उसे केवल अंक ही तो पढ़ना होता है और मेरे विचार में पंचायत समिति, जिला परिषद अथवा विधान सभा के सदस्य इतने शिक्षित तो होते ही हैं कि आंकड़े पढ़ सकें। अतः जब पहले कोई कठिनाई नहीं हुई तो 1968 के कादून में संशोधन करने की क्या ग्रावश्यकता है?

श्री श्रीनिवास मिश्र: वर्ष 1950 से श्रिशिक्षित मतद।ताओं के बारे में कोई नियम नहीं सनाया गया है, परन्तु अब निर्वाचित लोगों के लिये यह नियम बनाने की क्या आवश्यकता है ? क्या यह बुरी बात नहीं है कि सरकार निर्वाचकों के बजाय निर्वाचित व्यक्तियों के लिये यह नियम बनाने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री गोविन्द मेनन: यह ठीक है कि निरक्षरता कम हो रही है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वर्ष 1952 में जो अशिक्षित थे, वे अब शिक्षित हो गये हैं। विधान सभा के लिये मतदान में पहले रंगीन बक्सों की पद्धित का प्रयोग किया गया था क्योंकि कुछ मतदाता अशिक्षित भी हैं। बाद में विभिन्न दलों के प्रतीक बनाये गये। परिषद के चुनावों में एकल संक्रमणीय मत पद्धित से और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धित से मतदान होता है और वहां कठिनाइयां सामने आती हैं। यदि कोई व्यक्ति उर्दू जानता है और मतपत्र अंग्रेजी या हिन्दी में छपे हों तो वह अशिक्षत ही समभा जायेगा। इस कठिन स्थिति में गोपनीयता का कुछ उल्लंघन करना ही पड़ेगा। जब तक अशिक्षित लोग है तभी तक यह नियम रहेगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हमें बताया है कि उन्हें कई अभ्यादेदन मिले है पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कई सदस्य अनपढ़ हैं। इसलिये यह नियम आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"यह सभा संकल्प करती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अनुसरएा में, निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 25 अप्र ल, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ग्रो० 1520 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 25 जुलाई, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, रह कर दिये जायें।"

"यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

प्रस्ताव ग्रस्वेकृत हुग्रा । The motion was negatined.

नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा DISCUSSION UNDER RULE 193

जांच समिति (इस्पात सौदे) का प्रतिवेदन

Shri Madhu Limaye (Monghyr): It is observed from the report of Sarkar Committee that such semi judiciary enquiry will not be fruitful. In future we should enquiries should be entrusted to the existing Parliamentary Committees or any special committee should be set up for this purpose.

Top officials of the Government have been trying to adopt unhelpful attitude towards Sarkar Committee right from the beginning and they have been trying to stand in their way. The committee has also mentioned that they had to experience great difficulties in getting necessary papers from the Directors Revenue intelligence and Central Bureau of Investigation.

In my opinion majority report of Sarkar Committee is disappointing. I would suggest that Government should not overlook the note of dissension. It has its own importance. I want to suggest that charges regarding the relations of Sardar Swarn Singh. Sardar Hukam Singh and Shri Jagjiwan Ram with Amin Chand Pyare Lal should be got investigated through Director, Revenue Intelligence and Central Bureau of Investigations.

The hon'ble Minister had said that it is difficult to take action against Shri Boothalingam because he has already been retired. I think Government could easily deduct his pension. Atleast they could stop payment being made to him for the other services being assigned to him. Other officers are also guilty of destroying necessary documents. It has been stated in the note of disension that in other Ministries original drafts are generally preserved in a separate bundle entitled "K.W. (Keep with) but it is not being done in Ministry of Iron and Steel. They want to conceal their offence in this manner. Shri Boothalingam and Shri Bam have favoured some firms and it has been accepted by Sarkar Committee.

It has now been proved that former Secretary, Ministry of Iron and Steel, Shri Wanchoo has given false evidence before Public Accounts Committee and he was helped by Deputy Steel Controller.

Shri S.B. Mukherjee: It is clear from Shri Padhi's note of dissent that Ram Krishan Kulwant Rai a sister concern of Amin Chand Pyare Lal has been favoured. Government can easily take action against such firms with the powers enjoyed by the Government. Drastic action should be taken against such guilty officers and defaulter firms.

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा): मेरे पास श्री पी० सी० घोष द्वारा श्री जगजीवन राम के पुत्र श्री कुमार को लिखा एक पत्र है। यह एक गम्भीर बात है क्योंकि यह करोड़ों रुपयों के श्रण्टाचार का मामला है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अमीनचन्द प्यारेलाल ग्रुप को आयात-पूर्व लाइसेंस क्यों दिया गया था? इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद अमीनचन्द प्यारेलाल और रामकृष्ण कुलवन्तराय फर्मों को कितने लाइसेंस दिये गये हैं? मैं यह मी जानना चाहता हूं कि क्या कोई टेन्डर मंगवाया गया है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि अमीनचन्द प्यारेलाल के साथ सम्बन्ध रखने वाले मंत्रियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की गई तो सरकार सिमिति का प्रतिवेदन निरर्थक हो जायेगा।

इस्पात, खान तथा घातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): लोक लेखा समिति की सिफारिश पर सरकार समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी मामलों की जांच की है। फाइलों में उपलब्ब साक्ष्यों की जांच के बाद समिति ने असाधारण राज-पत्र जारी करके और समस्त देश में सभी समा-चारों में सार्वजिनिक अधिसूच गा जारी करके ज़ुजनता से भी साक्ष्य मांगा था। इस अधिसूचना के बावजूद उन्हें केवल 9 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उनमें से केवल श्री वी० वी० स्वामी की ऐसी शिकायत थी जो जांच के योग्य थी। जांच करने से समिति को पता चला कि वह शिकायत ठीक नहीं थी। अन्य शिकायतें इस्पात की सप्लाई के सम्बन्ध में थी।

वर्तमान चर्चा के दौरान जो मामले उठाये जा रहे हैं वे इस समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आ सकते। जो पत्र अब सभा के समक्ष लाया जा रहा है वह समिति के समक्ष लाया जाना चाहिये था। परन्तु समिति के समक्ष ऐसी कोई चीज नहीं लाई गयी।

इस समिति ने 13 अधिकारियों को किसी न किसी रूप में दोषी पाया था। इन 13 अधिकारियों में से 4 सेवा निवृत हो गये हैं। अनुच्छेद 314 और नियम 351 (क) के उप-बन्धों के अनुसार आई० सी० एस० अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना कठिन है। श्री बूथिलगम वर्ष 1967 में सेवा निवृत हुए थे जबिक सिमिति हुँका प्रतिवेदन अप्रैल 1968 में प्रकाशित हुआ था। फिर 1960--61 में कार्यवाही का कारण था। संविधान के उपबन्धों के अनुसार यदि कार्यवाही का कारण सेवा निवृत्ति से 4 वर्ष पूर्ण का है तो कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। जहां तक कराधान जांच सिमिति में नियुक्ति की बात का सम्बन्ध है, यह नियुक्ति भी इस सिमिति के प्रतिवेदन से पहले की गई थी। अन्य अधिकारियों में से श्री बाम को आरोप-पत्र दिया गया था, उसका उत्तर मिल गया है और उसकी छानबीन की जा रही है। शेप 2-3 मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गये हैं, उनकी रिपोर्ट प्रन्त होने पर उन्हें

धारोप-पत्र दिये जायेंगे। सरकार समिति द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

सरकार समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने से बहुत पहले वर्ष 1966 में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने सभी महत्वपूर्ण फर्मों पर, जिनमें अमीनचन्द प्यारेलाल ग्रुप भी सम्मिलित हैं, प्रति-बन्ध लगा दिया था। परन्तु जब इस फर्म ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की तो ग्याया-लय ने निर्णय दिया कि उन पर प्रतिबन्ध लगाना लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के लिये आवश्यक नहीं था क्योंकि निर्यात तथा आयात नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने पर इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये थी।

कलक सा उच्च न्यायालय की व्यवस्था को देखते हुये निर्यात आयात नियन्त्रक ने इन व्यवसाय संगठनों को यह सूचना जारी की है कि क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये अथवा नहीं ? परन्तु इसके अलावा सरकार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इनके कुछ मामले उच्च न्नायालय में पंच निर्ण्य अथवा निर्ण्य होने के लिये पड़े हैं अतः उन मामलों पर उन्होंने विचार व्यक्त नहीं किये हैं।

निर्यात शायात नियंत्रण आदेश ग्रथवा विदेशी विनिमय नियमों के उल्लंघन के कारण कुछ अन्य मामले रिजर्व बेंक को सींपे गये हैं जिसने उन मामलों को आगे केन्द्रीय जांच विभाग को सींप दिया है, प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। आय कर और बिक्री कर के उल्लंघन के बारे में सांविधिक व्यवस्था है और यह समिति के चेत्र के अन्तर्गत नहीं आता कि वह इसकी जांच करे। यह समिति विनिमय सींदो तथा अन्य विषयों की ही जांच करेगी।

1959--60 में सेमीस की बहुतायत हो गई थी और मिलों में तैयार करने की क्षमता नहीं थी अतएव यह कहा गया कि सेमीस का निर्यात किया जा सकता है, उस समय हमें एक विशेष प्रकार के इस्पात की आन्तरित खपत के लिये आवश्यकता थी अतएव यह निर्णय किया गया कि सेमिस का निर्यात किया जाये, यह निर्णय 1960 में लिया गया। निर्यात के लिये 29 पार्टियों ने आवेदन पत्र दिया लेकिन कुछ ही पार्टियों को निर्यात करने के लिये ग्रायात के पूर्व के लाइसेंस 1.6 लाख मीट्रिक टन इस्पात के लिये दिये गये जिनमें ने 80,000 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया और बाकी मात्रा का न्यायालयों में मामले होने के कारण निर्यात न हो सकी।

सरकार समिति ने कहा है कि आयात और निर्यात दोनों आवश्यक हैं अतएव कभी को देखते हुए हिन्दुस्तान स्टील को निर्यात करने के लिये अनुमति दे दी गई।

जहां तक रामकृष्ण कुलवन्तराय का सम्बन्ध है, जिसने हिन्दुस्तान स्टील के साथ स्थायी ठेका करने के बाद आयात-पूर्व लाइसेंस प्राप्त कर लिया था, उसके मामले को सरकार समिति ने जांचा है और उसके प्रतिवेदन के अनुसार फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

Shri Madhu Limaye: Why the help of investigating agencies was not taken by the Sarkar Committee and secondly whether the hon. Minister will say something regarding the false evidence given by Shri Wanchoo before the Committee.

श्री प्र० चं० सेठी: जहां तक विशेष व्यक्ति ग्रीर एजेंसी के मदद लेने का सवाल है, मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री श्रीवास्तव, जोकि सीमाशुल्क के अतिरिक्त कलक्टर थे, से मदद देने की प्रार्थना की गई थी परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसी प्रकार एक अन्य सीमाशुल्क अधिकारी श्री केलकर ने भी मदद देने में असमर्थता प्रकट की, जहां कहीं भी सम्भव पाया पया ऐसे मामलों को केन्द्रीय सतर्कता श्रायोग को सौंपा गया। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि कुछ विशेष अधिकारी अथवा एजेन्सी की मदद इस जांच कार्य में नहीं ली गई।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): I want to know whether the Hon. Minister has the knowledge that the Messers Amin Chand Pyare Lal Jullundhar was a very small firm which neither export anything nor pay more income tax. Since the Government of Punjab gave order of poles to the firm, so she committed black marketing in it. Do you know that this firm was black listed thrice? It may be in your knowledge that questions against the firm were raised in both Houses but the Government denied it. Are you aware that this firm changed many names and continued to draw quota in coalition with offi ers? What do you say about the embezzlement committed by the Punjab National Bank.

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): The Sarkar Committee was formed on the recommendations of Public Accounts Committee It made enquiry and some findings came to light. One is about the Bank Guarantee. The Committee have asked to take action against those officials who are responsible for the lapse of Bank Guarantee. But the purpose for which the Bank Guarantee was given could not be fulfilled. Goods worth five crores rupees was imported and only goods worth $2\frac{1}{2}$ crores rupees exported. What action the Government will take to fulfill the Bank Guarantee. Secondly what action is being taken by the Government to compel the concerned parties to make up the shortfall. Thirdly, the Committee have pointed out that the rules of the office are not followed and there is much mismanagement. So what action is being taken to implement the recommendations made by the Committee in this respect?

Shri P. C. Sethi: The Government are taking action against those corrupt officials who have been named by the Sarkar Committee for raleasing the Bank Guarantee in driblet form. It is correct that there was no drill in keeping the record in the office of Iron and Steel Centroller. The Sarkar Committee have also admitted this. We have appointed Special Officer Shri Mangat Ram to make enquiry for not following the Drill. I will again give assurance to the House that the Government will follow the recommedations as made by the Sarkar Committee.

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1968 29 ध्रप्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 20, 1968 Agrahayana 29, 1890 (Saka),